सूर्योदय 5:32 सूर्यास्त 7:24

आज का तापमान

शिमला	17.4 न्यू	21.3 अधि
धर्मशाला	16.6 न्यू	27.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	77,470
निफ्टी	24,188

सोना 1,43,000 चांदी 2,23,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 7 श्रावण, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 88, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

दूसरे दिन भी संसद में हुआ भारी हंगामा

पेपर लीक मुद्दे पर राहुल स्पीकर से मिले, खड़गे बोले- विपक्ष को नहीं मिल रहा बोलने का मौका

एजेंसी, नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में मंगलवार को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा जारी रखा, जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित होने के बाद बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही दो बजे फिर शुरू हुई, तो पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने और अपने-अपने स्थान पर बैठने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियम 377 के तहत सदस्यों को जनहित के मुद्दे सदन के पटल पर रखने दिया जाए। इसके लिए करीब 20 मिनट का समय भी दिया गया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के कारण पहले 12 बजे तक और फिर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। कार्यवाही जब 2 बजे फिर शुरू हुई, तो उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों से कार्यसूची के अनुसार सदन चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए और जो सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं, वे क्रमवार बोलें। उन्होंने सभी सदस्यों से शोर-शराबा नहीं करने और सदन की कार्यवाही में सहयोग देने की अपील की। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति ने कार्यवाही शुरू होने के लगभग एक मिनट बाद ही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन के बाहर आकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में ऐसा करना गलत है। वहीं, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत काम रोकने का नोटिस दिया है।

धरने पर बैठे राहुल को पुलिस उठाकर ले गई, प्रियंका-अखिलेश भी हिरासत में लिए

नई दिल्ली। पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पीएम आवास के पास धरने पर बैठे राहुल गांधी को पुलिस उठाकर ले गई, जैसे ही पुलिस राहुल को उठाने आई, राहुल जमीन पर लेट गए। इस पर पुलिस कर्मी उन्हें हाथ-पैर से पकड़कर उठाकर ले गए। कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में पीएम आवास के पास मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 3 बजे से धरने पर बैठे थे। पुलिस धरने पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेता मौजूद थे। इससे पहले कांग्रेस के प्रदर्शनकारी नेताओं से बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। राहुल से चर्चा करने के बाद वह अमित शाह के पास गए। शाह से बातचीत के बाद उन्होंने फिर राहुल से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो। राहुल की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए। वह बोले- अब हमारी दो मांगे हैं। पहली- नीट पर संसद में चर्चा, दूसरी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। गृह सचिव ने राहुल से कहा- यह जगह धरने के लिए अनुकूल नही हैं, इस पर राहुल बोले- ये भी मेरी मर्जी है जहां चाहे बैठें।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे : पीएम मोदी

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीट पेपर लीक पर पहली बार बयान सामने आया। पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे.। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक राजनीति का विषय नहीं है। उनके भविष्य का नुकसान ना हो, इसलिए री-एग्जाम लिया गया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में सरकार की ओर से तुरंत कार्रवाई की गई। छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है।

अब बात करने सरकार खुद जंतर-मंतर आए : अभिजीत

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर सरकार ने समय बर्बाद किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल जब्त कर लिए। दोनों को एक तरह से जेपी नड्डा के घर पर नजरबंद कर दिया गया था। अब वे सरकार से फिर बातचीत करने नहीं जाएंगे, अब सरकार को यहां जंतर-मंतर पर आना होगा। इस बीच, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने प्रवक्ता विजेता दहिया को उनके पद से हटा दिया। यह कदम तब उठाया गया, जब एक वीडियो सामने आया जिसमें वे पार्टी के संसद' मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के बीच बर्गर खाते हुए दिख रहे थे। एक बयान में, सिजेपी ने कहा कि दहिया का व्यवहार आंदोलन के मूल्यों के अनुरूप नहीं था। आलोचना का जवाब देते हुए, दहिया ने कहा कि लोगों ने यह नहीं देखा कि वे भी दो रातों से सोए नहीं थे, ठीक वैसे ही जैसे प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोग नहीं सोए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से उनकी पसंद के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है। वांगचुक को तुरंत मेदांता ले जाया जाएगा और सफदरजंग अस्पताल उनके इलाज के सभी मेडिकल दस्तावेज मेदांता को सौंपेगा।

◆ हाईकोर्ट ने वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने की मंजूरी दी

न्यूज शॉर्ट्स

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की याचिका पर एम्स से मांगा मेडिकल अपडेट

एजेंसी, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली आसाराम बापू की याचिका पर एम्स अस्पताल से मेडिकल बोर्ड गठित कर स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आसाराम पूरी तरह स्वस्थ हैं और हाल में अयोध्या व काशी विश्वनाथ की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आसाराम ने वहां पैदल यात्रा भी की थी। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले उनकी सजा निलंबित करने से इनकार किया था और जेल में मिल रही चिकित्सा सुविधाएं जारी रखने के निर्देश दिए थे।

ईरान के हमलों में 100 अमेरिकी सैनिक घायल

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके करीब 100 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए। इनमें से 96% सैनिक ठीक होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर को सिर पर हल्की चोट लगी थी। पार्नेल ने यह बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के जवाब में दिया, जिसमें दावा किया गया था कि रक्षा मंत्रालय ईरान के साथ युद्ध में घायल हुए अमेरिकी सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। पार्नेल ने कहा कि इसमें जानबूझकर देरी हुई। ऐसा सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया।

सीएम सुक्खू ने 'तकनीकी रोजगार सेतु' पोर्टल का किया शुभारंभ

तकनीकी शिक्षा से रोजगार तक आसान होगा सफर

अनिल कुमार शर्मा भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को तकनीकी शिक्षा विभाग के 'तकनीकी रोजगार सेतु' पोर्टल का शुभारंभ किया। यह राज्य का अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों, छात्रों और नियोक्ताओं को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कौशल विकास व रोजगार सृजन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यह पोर्टल युवाओं व उद्योगों के बीच प्रभावी सेतु का कार्य करेगा तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। छात्र इस पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल, कौशल, प्रशिक्षण व प्रमाणपत्रों का विवरण अपलोड कर सकेंगे। साथ ही नौकरी के अवसरों की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन और प्लेसमेंट की स्थिति भी देख सकेंगे।

नियोक्ता भी पोर्टल पर पंजीकरण कर रिक्त पदों की जानकारी साझा कर सकेंगे, पात्र उम्मीदवारों की प्रोफाइल देखकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे और नियुक्तियों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करा सकेंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक देरी कम होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल पर अब तक 164 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 136 आईटीआई, 18 पॉलिटेक्निक, पांच इंजीनियरिंग व पांच फार्मेसी कॉलेज शामिल हैं। हिम एक्सेस इंटीग्रेशन पोर्टल के माध्यम से 26,168 छात्रों का पंजीकरण और 23,054 छात्रों की कौशल मैपिंग पूरी हो चुकी है। वहीं 97 नियोक्ता भी इससे जुड़ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर जैसे कुशल श्रमिक भी इस मंच पर पंजीकरण कर अल्प अवधि के कार्यों के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

एमपी में यूसीसी विधेयक पास

एजेंसी, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) विधेयक पारित हो गया है। इस बीच सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक, हंगामा और नारेबाजी हुई। कांग्रेस के विरोध के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही जारी रखते हुए बिल को पास घोषित कर दिया। विधानसभा में मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक यूसीसी के विरोध में नारेबाजी करने लगे, जबकि भाजपा विधायक और मंत्री बिल पर चर्चा कराने की मांग करते रहे।

दिल्ली के लाल डोरा और गांवों को मिलेगा डिजिटल अधिकार, सरकार जल्द जारी करेगी स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी के लाल डोरा व आबादी गांवों के निवासियों को उनकी संपत्तियों का आधुनिक, पारदर्शी और सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में 'स्वामित्व' (सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इंप्रोवाज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया) योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस योजना के तहत व्यापक सर्वेक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि वर्षों से लाल डोरा क्षेत्रों में संपत्तियों का व्यवस्थित व प्रमाणिक रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अब दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित कर रही है, जिससे भविष्य में रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। दिल्ली सरकार जल्द ही पात्र लोगों को स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने जा रही है। इसको लेकर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 48 गांवों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ हुए समझौते के तहत योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 30 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है व उनके अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, अब इन कार्डों में डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ने और स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

उन्होंने बताया कि अब तक 12,232 संपत्तियों (पॉलीगॉन) का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इनमें से 8,423 संपत्तियां विवाद-मुक्त हैं, जो कुल सर्वेक्षित संपत्तियों का लगभग 69 प्रतिशत हैं और इनके स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दक्षिण और उत्तर-पश्चिम जिले में सर्वे की गई सभी संपत्तियां विवाद-मुक्त हैं, जबकि अन्य जिलों में भी विवादों के समाधान के साथ आगे की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल कागजी रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली पर आधारित है।

◆ दिल्ली में संपत्तियों का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, सीएम रेखा ने की स्वामित्व योजना की समीक्षा

सिक्किम की निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड, 10 मजदूरों की मौत

एजेंसी, गंगटोक। सिक्किम में सोमवार को एक टनल पर लैंडस्लाइड होने से उसका एंट्री गेट बंद हो गया, जिससे अंदर मौजूद 27 मजदूर फंस गए। इनमें से 10 की मौत हो गई।

मृतकों में 3 की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जबकि 17 मजदूर अब भी फंसे हैं। नामची जिले के मामरिंग स्थित समरदुंग सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था। एसपी सोनम डोल्मा ने बताया कि फंसे हुए मजदूरों की संख्या 27 से कम या ज्यादा भी हो सकती है। सुरंग में मीथेन गैस लीक होने की आशंका है। कई बचावकर्मियों को अंदर जाने के दौरान चक्कर आए। कुछ बेहोश भी हो गए, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ। जिला अधिकारी तमलिंग ने बताया कि दोपहर करीब 3:40 बजे प्रशासन को हादसे की खबर मिली। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

सुरंग में पटेल इंजीनियरिंग के 21 और एनएचपीसी के 6 समेत कुल 27 मजदूर फंसे होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल से भी गैस-रोधी उपकरणों के साथ एक स्पेशल रेस्क्यू टीम लाई गई है। एंबुलेंस को तैयार रखा गया है। बचाव दल गैस मास्क पहनकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह टनल तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए पटेल इंजीनियरिंग कंपनी बना रही थी।

◆ 17 अब भी फंसे; मलबे से सुरंग बंद, रेस्क्यू करने गए कुछ वर्कर्स हुए बेहोश

सीएम ने पिंजौर सेब मंडी में किया पौधरोपण, युवाओं से किया संवाद

युवा शक्ति से साकार होगा विकसित भारत का सपना : सैनी

एजेंसी, पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर एचएमटी सेब मंडी में आयोजित युवा संवाद व पौधरोपण कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत एक पौधा रोपा।

इसके बाद युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 21 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से करीब 210 स्टूडेंट्स शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने सुझाव दिए और उनसे प्रश्न पूछे। मुख्यमंत्री ने छात्रों के सुझावों को ध्यान से सुना और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। छात्रों ने सभी वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल स्कूल शुरू करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, माउंटेन स्कूल और सतत विकास में छात्रों के योगदान को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव भी रखे गए।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री सैनी ने उपस्थित युवाओं और अन्य लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जो भी युवा सीखेगा, वह आगे 100 अन्य युवाओं को जागरूक करेगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि युवा शक्ति से ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है।

उन्होंने सभी युवाओं से अपने खास दिन पर एक पौधा लगाने और उसे वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने का आग्रह किया, जिससे हरियाणा हरा-भरा बनेगा। इस दौरान सेब मंडी के आढ़तियों ने भी अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

◆ युवाओं ने एक पौधा लगाने का संकल्प लिया

छात्रों को परीक्षा का तरीका नहीं, निष्पक्ष परीक्षा की व्यवस्था चाहिए : सीएम मान

एजेंसी, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री छात्रों को परीक्षा देने का तरीका तो बताते हैं, लेकिन अब यह भी बताना चाहिए कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कैसे कराई जाए।

उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को मेहनती विद्यार्थियों के साथ अन्याय बताया। साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका नहीं जाना चाहिए व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किसान संगठनों से बातचीत होनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण अध्यादेश और विधेयक पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में 10 लाख नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिन पात्र लोगों का नाम अब तक नहीं जुड़ा है, वे भी आवेदन कर सकेंगे।

◆ कहा- छात्रों को मिले न्याय किसानों की समस्याओं का बातचीत से हो समाधान

हरिद्वार गंगा कॉरिडोर को मिली नई रफ्तार, सीएम धामी ने 235 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया भूमि पूजन व शिलान्यास

एजेंसी, हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत लगभग 235 करोड़ रुपए की विभिन्न आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। उत्तराखंड निवेश व आधारिक संरचना विकास बोर्ड द्वारा संचालित इन परियोजनाओं का उद्देश्य हरिद्वार में आधुनिक, सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित आधारभूत सुविधाओं का विकास कर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है।

अलकनंदा होटल, हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 43.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली प्रशासनिक मार्ग परियोजना का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 66.76 करोड़ रुपए की लागत से हर की पैड़ी एवं सुभाष घाट के पुनरुद्धार, 66.34 करोड़ रुपए की लागत से हर की पैड़ी के उत्तर क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना विकास तथा 58.84 करोड़ रुपए की लागत से रोड़ी बेलवाला क्षेत्र के पुनरुद्धार कार्यों का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश और विश्व के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार का लक्ष्य हरिद्वार को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करना है, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि गंगा कॉरिडोर से जुड़े इन विकास कार्यों के पूरा होने के बाद हर की पैड़ी, सुभाष घाट व रोड़ी बेलवाला क्षेत्र की आधारभूत संरचना मजबूत होगी। इससे श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि होगी, भीड़ प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा तथा स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है।

उप्र कैबिनेट: महिला सशक्तिकरण व उच्च शिक्षा पर योगी सरकार का फोकस, स्कूटी योजना समेत कई प्रस्ताव मंजूर

50 हजार छात्राओं को स्कूटी देगी योगी सरकार

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित इस बैठक में उप्र विधान मंडल का मानसून सत्र तीन अगस्त से आहूत किए जाने, प्रदेश की लगभग 50 हजार छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ दिए जाने समेत अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

कैबिनेट की बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पहला प्रस्ताव रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए है। इसमें राज्य, निजी और संबद्ध विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण छात्राओं में से शीर्ष पांच फीसदी को लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूटी के साथ पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, आईएसआई मार्क हेलमेट, आवश्यक एक्सेसरीज़ और पांच लीटर पेट्रोल भी सरकार वहन करेगी। स्कूटी पेट्रोल चालित होंगी और उनका क्रय जेम पोर्टल से होगा। दिव्यांगजन, निराश्रित परिवारों और शहीद परिवारों की बेटियों को मेरिट के बिना यह लाभ मिलेगा। लगभग 50 हजार बेटियों को इस योजना से लाभ मिलेगा मंत्री उपाध्याय ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए शोध पीठों की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रत्येक सहायता प्राप्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए शोध पीठों की स्थापना होगी। एनईपी 2020 की अनुशंसाओं के तहत यह पहल की गई है। विश्वविद्यालयों को दो करोड़ रुपए तक और महाविद्यालयों को एक करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में होगा और शोध पीठों का संचालन इसके ब्याज से होगा। सीएसआर फंड या एल्युमिनाई से फंड जुटाकर इसे बढ़ाया जा सकता है। 50 वर्ष से अधिक पुराने और 5000 से अधिक छात्र वाले प्राचीन महाविद्यालयों को भी मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय ज्ञान (जैसे वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, गणित, खगोल शास्त्र, व्याकरण) को पुनर्जीवित करना और युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है।

बसंत महिला कॉलेज में बनेगा नया छात्रावास

उच्च शिक्षा विभाग के तीसरे प्रस्ताव में बसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट फोर्ट, वाराणसी में महिला छात्रावास का निर्माण है। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक संगठक महाविद्यालय है। 112 वर्षों से अध्ययन के क्षेत्र में सेवा कर रहा है। वर्तमान में केवल 220 छात्राओं के लिए एक छात्रावास है, जिससे दूरदराज की छात्राओं को असुविधा होती है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 248.30 लाख की लागत से 112 बच्चियों के लिए एक नए महिला छात्रावास का निर्माण होगा। इससे छात्राओं को आवासीय सुविधा और मनोवैज्ञानिक संबल मिलेगा, जिससे शिक्षा का बेहतर वातावरण बनेगा।

कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएं : सुक्खू

कार्यकर्ताओं के साथ संवाद' कार्यक्रम शुरू, कार्यकर्ताओं ने कहा, कांग्रेस सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 'मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम' की शुरूआत सिरमौर जिला के पच्छाद तथा शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र से की।

उन्होंने ओक ओवर शिमला में दोनों विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया व विकास कार्यों पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस सरकार के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्र की विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की और सरकार को पूर्ण सहयोग देने की बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएं व राज्य सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों

तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में कांग्रेस सरकार ने लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं और इनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदहाल व्यवस्था कांग्रेस सरकार को पिछली भाजपा सरकार से विरासत में मिली। इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाए हैं। मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे आने वाले समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में और सुधार नजर आएगा। इसके अलावा सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान भी बनाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 150 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके। इन स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दूध के मूल्य में वृद्धि की है। गाय का दूध 61 रुपए तथा भैंस का दूध 71 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा रही है और प्राकृतिक खेती से तैयार कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेब बागवानों का मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत 30 बोरी तक खरीदे गए सेब का पूरा भुगतान कर दिया है। अब राज्य सरकार 100 बोरी तक सेब का भुगतान करने जा रही है और उसके बाद 100 से ज्यादा सेब बोरी का पैसा जारी कर दिया जाएगा।

सुक्खू ने कहा कि विधवा महिलाओं और एकल नारियों के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी राज्य सरकार उठा रही है और पात्र विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर बीस लाख तक ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि पच्छाद और चौपाल विधानसभा क्षेत्र में विकास के मामले में कमी नहीं आने दी जाएगी और वहां अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए समुचित धन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार पूरे प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है।

राज्य सरकार पच्छाद क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कर रही : विनय

इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि पच्छाद प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाई एस परमार की जन्मभूमि है और राज्य सरकार पच्छाद क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाकर कांग्रेस हाईकमान ने पूरे सिरमौर जिला को सम्मान दिया है। प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं और वर्तमान कांग्रेस सरकार 2027 में पुनः सत्ता में आकर इतिहास रचने को तैयार हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव विनोद जिंटा, चौपाल से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रजनीश किमटा, जिला शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष कृष्ण हिमराल, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, कांग्रेस नेता दयाल प्यारी सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे।

हर्ष महाजन ने राज्यसभा में उठाया हिमाचल में नशा मुक्ति केंद्रों का मुद्दा

◆ केंद्र का खुलासा– सरकार ने नहीं भेजा कोई प्रस्ताव

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल आधारित नशा मुक्ति सुविधाओं को लेकर पूछे गए प्रश्न पर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने अपने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि वर्तमान में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की किसी भी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में एक भी सरकारी अस्पताल आधारित नशा मुक्ति केंद्र संचालित नहीं है।

इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार की ओर से नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया है। हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल में नशे की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल करती दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों को सहायता देने के लिए तैयार है, तब प्रदेश सरकार का प्रस्ताव तक न भेजना उसकी उदासीनता और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है, लेकिन कांग्रेस सरकार केवल बयानबाज़ी में व्यस्त है। यदि समय रहते केंद्र को प्रस्ताव भेजे जाते तो हिमाचल के विभिन्न जिलों में सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आधुनिक नशा मुक्ति सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती थीं। केंद्र सरकार ने अपने उत्तर में यह भी बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत प्रदेश में कुछ नशा उपचार सुविधाओं को वित्तीय सहायता दी गई है। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल को वर्ष 2023-24 में 41.79 लाख, वर्ष 2024-25 में 35.32 लाख तथा वर्ष 2025-26 में 35.11 लाख की सहायता दी गई। किन्नौर के क्षेत्रीय अस्पताल को वर्ष 2024-25 में 17.64 लाख तथा एम्स बिलासपुर में सुविधा स्थापना के लिए वर्ष 2025-26 में 9.87 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई।

शिमला में दो जगहों से 29 ग्राम चिट्टा बरामद, दो काबू

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई में दो लोगों को करीब 29 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है।

दोनों मामलों में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 20 जुलाई को पुलिस थाना बालूगंज और स्पेशल सेल शिमला की संयुक्त टीम शोघी क्षेत्र में गश्त और जांच पर थी। इस दौरान एक एचआरटीसी बस की तलाशी ली गई। जांच के दौरान एक युवक के कब्जे से 13 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुल्लू जिले के निरमंड निवासी 19 वर्षीय अजय ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर मामले की आगे की जांच कर रही है। एक अन्य मामले में 20 जुलाई को पुलिस थाना चिड़गांव की टीम आंध्रा पावर हाउस चिड़गांव के पास गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 16 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान 23 वर्षीय मनींदर सिंह, निवासी अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया जा रहा है। मामले की गहन जांच जारी है। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने मंगलवार को बताया कि दोनों मामलों में यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद चिट्टा कहां से लाया गया था और इसे किसे पहुंचाया जाना था। इस संबंध में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

राजनीति व शतरंज का गहन संबंध : रोहित ठाकुर

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिक्षा मंत्री ठियोग में अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के उपलक्ष्य पर एसपी लोहिया फाउंडेशन एवं हिमाचल प्रदेश राज्य शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित 13 वर्ष से कम आयु वर्ग की शतरंज प्रतियोगिता के दौरान मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में सात स्कूलों के 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

◆ कहा- दोनों में चलता है शह और मात का खेल

इस दौरान उन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए बताया कि शतरंज एक बहुत ही रोचक और मनोरंजन खेल है और वह स्वयं भी इस खेल को बहुत पसंद करते और खेलते हैं। उन्होंने इस आयोजन पर आयोजनकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई दी और यह आशा भी व्यक्त की कि आने वाले समय में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहेगा। उन्होंने खेलों के विषय में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रदेश के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के साथ-साथ बेहतर खेल सुविधाएं भी प्रदान कर रही है, जिसके अंतर्गत शतरंज के खेल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। ठाकुर राम लाल खेल छात्रावास जुब्बल में इस खेल हेतु 10 सीटें रखी गई हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र जिला शिमला का एक महत्वपूर्ण भाग है और यहां के निवासियों ने ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर राजनीति, खेल और अन्य गतिविधियों में वर्तमान समय तक प्रदेश के उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि मतियाना स्थित खेल छात्रावास भी जिला का एक प्रमुख खेल संस्थान है और भविष्य में यहां पर भी शतरंज के खेल के लिए सीटों का प्रावधान किया जायेगा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने विनोदपूर्ण भाव से बताया कि राजनीति और शतरंज का आपस में एक गहन संबंध है और दोनों में ही शह और मात का खेल चलता रहता है और इस खेल से बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है। इस अवसर पर ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह राठौर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं, बल्कि बौद्धिक क्षमता, अनुशासन और तार्किक सोच को विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे आयोजन क्षेत्र में खेल संस्कृति को और अधिक सशक्त बनाएंगे तथा युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में उठाए किसानों के अधिकार व बीज संरक्षण से जुड़े मद्दे

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में पौध किस्म व कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किसानों के अधिकारों, पारंपरिक बीजों के संरक्षण, बीज अनुसंधान और हिमाचल प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्रों की कार्यप्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।

उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के लिए चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों, पौध किस्मों के पंजीकरण, बीज अनुसंधान, कृषि विज्ञान केंद्रों की गतिविधियों और इन योजनाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों की जानकारी मांगी। सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने पालमपुर में अपनी शाखा स्थापित की है। पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, मेले, प्रदर्शनियां और पौध किस्मों के पंजीकरण से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इस दौरान प्रदेश की 31 पौध एवं बीज किस्मों का पंजीकरण किया गया। सरकार ने बताया कि पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के बीज अनुसंधान केंद्र ने तीन वर्षों में 1,957.20 क्विंटल ब्रीडर बीज और 17,512 क्विंटल गुणवत्तायुक्त बीज का उत्पादन किया। वहीं प्रदेश के 13 कृषि विज्ञान केंद्रों ने 23,960 खेत प्रदर्शन आयोजित किए और करीब 93 हजार किसानों व अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण दिया। इन केंद्रों ने 5,567.35 क्विंटल गुणवत्तायुक्त बीज और 18.27 लाख बागवानी पौध तैयार किए। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में संबंधित गतिविधियों के लिए कुल 18.58 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए, जिसमें पौध किस्म संरक्षण के लिए 2.94 करोड़, बीज अनुसंधान के लिए 5.31 करोड़ और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 10.33 करोड़ रुपए शामिल हैं।

बिलासपुर के कई क्षेत्रों में कल बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिजली उपमंडल संख्या-1 बिलासपुर के सहायक अधिशाषी अभियंता इंजी. सन्नी जगोता ने बताया कि 33 केवी सर्किट संख्या-1 कांगू-जबली बिजली लाइन के साथ लगते पेड़ों की टहनियों की कटाई-छंटाई का कार्य 23 जुलाई को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रखरखाव कार्य के चलते बैरी, बरमाणा, देयोली, कंज्योता, चमलोग, घागस, बिनोला, पंजगाईं, धारटटोह, सिहड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि यह कार्य मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। बिजली विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे रखरखाव कार्य के दौरान सहयोग करें। विभाग ने कहा कि यह कार्य विद्युत व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

एसएफआई की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। छात्र संगठन एसएफआई की ओर से शिक्षा व्यवस्था में सुधार व प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर शुरू की गई क्रमिक भूख हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। संगठन ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।

एसएफआई के अनुसार 20 जुलाई से शुरू हुई इस क्रमिक भूख हड़ताल के पहले दिन संगठन के कार्यकर्ता प्रवेश, कृतिका, मितेश, राजेश और आशीष चौहान भूख हड़ताल पर बैठे थे। मंगलवार को दूसरे दिन स्नेहा, कुशाल राणा, अमन, अंकुश और आरुष ने क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखी। संगठन ने आरोप लगाया कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में लगातार गंभीर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। एसएफआई ने दावा किया कि नीट परीक्षा में करीब 22 लाख छात्रों ने भाग लिया था और पेपर लीक की घटनाओं के बाद कई छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ा।

संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस मामले में अपनी जवाबदेही तय नहीं की है। एसएफआई ने कहा कि 21 जून को दोबारा कराई गई नीट परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल नहीं हो सके। संगठन के अनुसार यह स्थिति परीक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर करती है। एसएफआई ने दावा किया कि इसी मुद्दे को लेकर छात्र दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और एनटीए को भंग करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करता है। एसएफआई ने अपनी मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को भंग करने, नई शिक्षा नीति को वापस लेने और सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग शामिल की है। संगठन का कहना है कि एनटीए देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं, जिनमें नीट, जेईई, सीयूईटी और यूजीसी-नेट शामिल हैं, का आयोजन करता है। एसएफआई ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में इन परीक्षाओं के संचालन को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जिससे छात्रों का भरोसा प्रभावित हुआ है। संगठन ने वर्ष 2026 की परीक्षा रद्द होने, वर्ष 2024 की नीट परीक्षा और यूजीसी-नेट परीक्षा से जुड़े विवादों के साथ वर्ष 2021 की जेईई मेन परीक्षा में कथित सुरक्षा चूक का भी उल्लेख किया।

राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ने शुरू की तीन ओटीएस योजनाएं

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। वर्षों से पुराने कर्ज के बोझ तले दबे किसानों और अन्य ऋणधारकों के लिए कर्ज चुकाने के सुनहरा अवसर है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ने छह महीने के लिए तीन वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजनाएं शुरू की हैं।

इन योजनाओं के तहत पात्र किसानों को ब्याज में राहत मिलेगी, जबकि पुराने ऋण खातों के निपटारे के लिए भी विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। बैंक का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में लोग अपने बकाया ऋण का निपटारा कर सकेंगे। बैंक अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने मंगलवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री कृषि ऋण राहत योजना के तहत कृषि क्षेत्र में तीन लाख रुपये तक का ऋण लेने वाले किसानों के बकाया ब्याज का 50 प्रतिशत सरकार वहन करेगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के 6,319 किसानों को मिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि योजना आज से लागू हो गई है और अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि बैंक ने वर्ष 2016 तक के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) खातों के लिए भी अलग ओटीएस योजना लागू की है। इसके तहत ऐसे खातों में बकाया ब्याज पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2016 तक के उन ऋण खातों को भी योजना में शामिल किया गया है, जिनकी प्रोविजनिंग बैंक पहले ही नाबार्ड के पास कर चुका है। ऐसे खातों में भी ब्याज पर 25 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी। संजय सिंह चौहान ने कहा कि तीनों ओटीएस योजनाएं केवल छह महीने तक लागू रहेंगी। इस अवधि में बैंक के कर्मचारी गांव-गांव और घर-घर जाकर पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे। उनका कहना था कि बैंक चाहता है कि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने ऋण खातों का निपटारा करें।

आरबीआई शिमला में टास्क फोर्स की 31वीं बैठक आयोजित

शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने पर मंथन

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय रिजर्व बैंक, शिमला की ओर से हिमाचल प्रदेश में शहरी सहकारी बैंकों के लिए टास्क फोर्स ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (टीएएफसीयूबी) की 31वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक अनुपम किशोर और हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (सहकारिता) सुदेश कुमार मोख्ता ने की।

बैठक में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड के प्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रदेश में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान

नियामकीय अनुपालन, परिसंपत्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और निगरानी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

टास्क फोर्स ने बैंकों की वित्तीय मजबूती के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली में तेजी लाने, बेहतर प्रशासन व्यवस्था, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। अधिकारियों ने कहा कि टीएएफसीयूबी एक महत्वपूर्ण संस्थागत मंच है, जो नियामक संस्थाओं और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित कर शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय चुनौतियों के समाधान में सहायता करता है। बैठक का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी बनाना रहा।

फीस वृद्धि के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन

एचपीयू प्रशासन से फैसले वापस लेने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने फीस वृद्धि के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। संगठन ने कुलपति, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को चेतावनी देते हुए फीस वृद्धि के फैसले को आम छात्रों पर आर्थिक बोझ बताया और इसे वापस लेने की मांग की।

इकाई अध्यक्ष अक्षय ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई शुल्कों में भारी बढ़ोतरी की है। उन्होंने बताया कि माइग्रेशन फीस को 600 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दिया गया है, जबकि विशेष परीक्षा फॉर्म की फीस 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी लगभग 7500 रुपए तक की वृद्धि की गई है। इसके अलावा डुप्लीकेट डिग्री और प्रमाणपत्र सुधार शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में छात्रों की मूलभूत सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संगठन ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने, नए छात्रावासों के निर्माण, छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था, खाने की गुणवत्ता सुधारने और पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग उठाई।

धरने के दौरान पार्किंग निर्माण, इनडोर स्टेडियम, गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती और केंद्रीय पुस्तकालय में चार्जिंग प्वाइंट लगाने जैसी मांगें भी रखी गईं। संगठन ने विश्वविद्यालय की बस सुविधा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले छात्रों के लिए आठ बसें उपलब्ध थीं, जो अब घटकर तीन रह गई हैं। एबीवीपी ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो छात्र आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

राहत विधायक मलेंद्र राजन ने आपदा से निपटने के लिए सतर्क रहने का किया आह्वान

इंदौरा की पंचायतों को मिलीं आपदा प्रबंधन किट

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। विधायक मलेंद्र राजन ने विकास खंड कार्यालय इंदौरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक इंदौरा की विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों को आपदा प्रबंधन किट वितरित कीं।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पहले से तैयारी और समन्वय अत्यंत आवश्यक है। पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी हमेशा सक्रिय रहें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें। विधायक ने कहा कि वर्ष 2023 और 2025 में आई भीषण बाढ़ के दौरान इंदौरा विधानसभा क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे अनुभवों से सीख लेते हुए भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर पर्याप्त उपकरण और प्रशिक्षित व्यवस्था उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से

आह्वान किया कि वे आपदा प्रबंधन को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानें, बल्कि जनभागीदारी के माध्यम से अपने गांवों में जागरूकता बढ़ाएं और संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी करें।

उन्होंने अधिकारियों को भी पंचायतों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखते हुए हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए। विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने उनके समक्ष पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन किट उपलब्ध करवाने की मांग रखी थी। उन्होंने इस मांग को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए किट उपलब्ध करवाईं। विधायक ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विधायक ने बताया कि वितरित की गई आपदा प्रबंधन किट में सुरक्षा हेलमेट, लाइफ जैकेट, 50 मीटर रस्सी, सर्च लाइट, ताला-चाबी, मेटल ट्रंक, सीटी , फोल्डिंग स्ट्रेचर, तिरपाल, दो व्यक्तियों के लिए टेंट,गैंती, कुल्हाड़ी, फावड़ा, हथौड़ा, एल्युमिनियम सीढ़ी, फर्स्ट एड किट तथा मेगाफोन जैसे आवश्यक राहत एवं बचाव उपकरण शामिल हैं, जो आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई में सहायक सिद्ध होंगे। इस अवसर पर विधायक ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की।

आपदा प्रबंधन पर केंद्र ने हिमाचल की सराहना की, पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति पर जताया संतोष

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन व वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य में चल रहे पुनर्वास, पुनर्निर्माण और आपदा जोखिम कम करने से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में केंद्र ने इन कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए भविष्य में इन्हें और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव डॉ. पुष्पेंद्र राणा और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वर्ष 2023 की आपदा के बाद शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं, पुनर्वास योजनाओं और जोखिम कम करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान गृह मंत्रालय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। मंत्रालय ने पुनर्वास, पुनर्निर्माण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़ी परियोजनाओं में हुई प्रगति की भी सराहना की। साथ ही राज्य सरकार को परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को और मजबूत करने की सलाह दी। मंत्रालय का कहना था कि इससे कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी क्रियान्वयन को और मजबूती मिलेगी। बैठक में एनडीएमए की सदस्य रीता ने भी हिमाचल सरकार की ओर से तैयार किए गए आउटपुट एवं आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पुनर्वास और पुनर्निर्माण परियोजनाओं की व्यवस्थित निगरानी के लिए एक प्रभावी पहल है और इससे परियोजनाओं की प्रगति का बेहतर आकलन किया जा सकता है। वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य शुरू किए गए थे। केंद्र सरकार की ताजा समीक्षा बैठक में इन प्रयासों की सराहना को राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

शारदा नदी उफान पर, बैराज में रेड अलर्ट

बनबसा बैराज क्षेत्र में लोगों और वाहनों की आवाजाही बंद

◆ एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, प्रशासन अलर्ट

◆ सिंचाई विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट और तेज की निगरानी

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। कुमाऊं क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिंचाई विभाग ने भारत-नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा शारदा बैराज पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एहतियात के तौर पर बैराज क्षेत्र में वाहनों और आम लोगों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शारदा नदी में पानी की आवक बढ़ी है। बढ़ते जलदबाव को नियंत्रित करने के लिए बनबसा शारदा बैराज से एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है।

कांवड़ यात्रा में एसपीओ निभाएंगे अहम भूमिका

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को नगर निगम रुड़की के सभागार में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल की अध्यक्षता में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लक्सर क्षेत्र को छोड़कर देहात क्षेत्र के सभी सर्किल ऑफिसर्स, थाना प्रभारी और ग्रामीण क्षेत्र के स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स शामिल हुए। बैठक के दौरान एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस द्वारा अब तक की गई तैयारियों और कार्ययोजना की जानकारी साझा की। उन्होंने एसपीओ से यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात को सुचारू रखने तथा शिवभक्त कांवड़ियों को निर्धारित कांवड़ पटरी से सुरक्षित रूप से भेजने में सक्रिय सहयोग की अपील की।

यूपीईएस रनवे ने चुने एआई स्टार्टअप्स मिलेगी 25 लाख तक फंडिंग

यूपीईएस रनवे ने चुने तीन एआई स्टार्टअप्स, एआई क्रांति को गति देगा यूपीईएस रनवे का द पिच 3.0

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। यूपीईएस में स्थित स्टार्टअप इन्क्यूबेटर यूपीईएस रनवे ने एआई आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द पिच 3.0 के दिल्ली चरण का आयोजन किया। इस पहल का लक्ष्य उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नए विचारों और तकनीकी समाधानों पर काम कर रहे स्टार्टअप्स की पहचान कर उन्हें आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है। दिल्ली चरण में 20 से अधिक स्टार्टअप्स ने आवेदन किया, जिनमें से सात चुनिंदा स्टार्टअप्स को अपने विचार निवेशकों, मेंटर्स और यूपीईएस के विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला।

द पिच 3.0 में शामिल स्टार्टअप्स ने एआई इमेज रिकग्निशन, फिनटेक, एडटेक, आपदा प्रबंधन, फ्लीट टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और डीप टेक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने अभिनव समाधान पेश किए। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे उद्यमियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो तकनीक की मदद से वास्तविक समस्याओं का समाधान तैयार कर रहे हैं।

यूपीईएस रनवे इस वर्ष 10 इनोवेटर्स को समर्थन देने की योजना बना रहा है। चयनित स्टार्टअप्स को उत्पाद विकास, बाजार तक पहुंच और कारोबार विस्तार के लिए 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं मजबूत तकनीकी क्षमता, बाजार की जरूरतों और विस्तार की संभावनाओं वाले स्टार्टअप्स को निवेश समिति की मंजूरी के बाद 50 लाख रुपये तक का सहयोग भी मिल सकता है।

दिल्ली पिच डे में फाउंडर्स को अपने बिजनेस मॉडल को विशेषज्ञों के सामने रखने और उनसे सुझाव प्राप्त करने का अवसर मिला।

द पिच 3.0 का उद्देश्य ऐसे संस्थापकों को समर्थन देना है, जो एआई आधारित समाधान तैयार कर रहे हैं और जिनमें बाजार की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि फंडिंग, मेंटरशिप और निवेशकों से जुड़ाव के माध्यम से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का मजबूत अवसर मिलेगा। वर्ष 2021 में शुरू हुआ यूपीईएस रनवे अब तक 50 से अधिक स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान कर चुका है। द पिच 3.0 के माध्यम से यूपीईएस एआई आधारित नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। **-(यूपीईएस रनवे सीईओ, राहुल नैनवाल)**

25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी

यूपीईएस रनवे इस वर्ष 10 इनोवेटर्स को समर्थन देने की योजना बना रहा है। चयनित स्टार्टअप्स को उत्पाद विकास, बाजार तक पहुंच और कारोबार विस्तार के लिए 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्टार्टअप्स को निवेश समिति की मंजूरी के बाद 50 लाख रुपए तक का सहयोग भी मिल सकता है।

शिक्षा सुधार की ओर तेज कदम, राज्य ने एनईपी के 71 लक्ष्य किए हासिल

◆ एनईपी-2020 को धरातल पर उतारने में जुटा शिक्षा विभाग

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में विद्यालयी शिक्षा विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 202 लक्ष्यों में से राज्य अब तक 71 लक्ष्य पूरे कर चुका है, जबकि 111 लक्ष्यों पर तेजी से कार्य जारी है। राज्य में प्री-प्राइमरी शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए सभी 5982 सह-स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाटिकाओं का संचालन किया जा रहा है।

इसके साथ ही एससीईआरटी और सभी 13 डायट में मॉडल बालवाटिकाएं स्थापित की गई हैं। बालवाटिका संचालन के लिए 11 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए 'जादुई पिटारा' और 'आरोही' मॉड्यूल लागू किए गए हैं। निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण, नवाचार आधारित और रोजगारोन्मुख शिक्षा पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उत्तराखंड सरकार एनईपी-2020 के प्रावधानों को पूरी प्रतिबद्धता लागू करने में जुटी है। 'सार्थक ट्रैकर' पर शिक्षा विभाग के लिए निर्धारित 202 लक्ष्यों में से 71 लक्ष्यों की पूर्ण करना हमारे टीम वर्क का प्रमाण है। हमारी प्राथमिकता एनईपी-2020 के अनुरूप प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण, नवाचार आधारित और रोजगारोन्मुख शिक्षा पहुंचाना है। **- डॉ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।**

मुन्ना सिंह चौहान ने किया विकसित भारत मिशन कार्यक्रम का उद्घाटन

विकसित भारत के संकल्प से जुड़ेंगे गांव, चकराता में तीन दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून जिले के चकराता में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो देहरादून की ओर से 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' विषयक तीन दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर कैंट बोर्ड चकराता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिपु दमन सिंह, उपाध्यक्ष अनिल चांदना और खंड विकास अधिकारी राकेश बिष्ट सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब गांवों का विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आजीविका के साधनों का विस्तार होगा। उन्होंने लोगों से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई।

◆ विकसित भारत मिशन से सशक्त होंगे गांव

नैनीताल मॉल रोड पर 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्न नियम

भारतेंदु संवाददाता, नैनीताल। शहर में 1 अगस्त से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-187 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक के संपूर्ण मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश पूर्व में जारी किए थे। इन आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने 1 अगस्त से लागू होने वाले इस प्रतिबंध के लिए पुलिस, परिवहन, राजस्व, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ पर्यटकों और बाहरी लोगों को भी इसके बारे में पहले से जानकारी के लिए नो हॉर्न से संबंधित डिस्प्ले बोर्ड, साइन बोर्ड और फ्लेक्सी विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएं।

बौख नाग धाम को मिला पर्यटन स्थल का दर्जा

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बौख नाग धाम को घोषित किया धार्मिक पर्यटन स्थल

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बौख नाग धाम को अब पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान मिल गई है। प्रदेश के पर्यटन धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बाबा बौखनाग की पवित्र तपोस्थली बौख टिब्बा को धार्मिक पर्यटक स्थल घोषित किया है। इस निर्णय से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार और विकास के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

बाबा बौखनाग धाम यमुना और गंगा घाटी के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण आस्था केंद्र है। लंबे समय से श्रद्धालुओं की इस स्थान के प्रति गहरी आस्था रही है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। क्षेत्र की धार्मिक महत्ता और प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे पर्यटन क्षेत्र में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही थी।

जानकारी के अनुसार 18 जुलाई 2026 को बाबा बौखनाग की डोली यात्रा के जनपद आगमन के दौरान श्री बाबा बौखनाग देव समिति के प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने यमुना गंगा के मध्य सिलक्यारा सुरंग के ऊपर स्थित बाबा बौखनाग की तपोभूमि बौख टिब्बा को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग रखी थी। मंत्री ने इस मांग का तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बाबा बौखनाग की तपोस्थली धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आगमन होता रहता है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में तीसरे वर्ष आयोजित होने वाला सेम नाग राजा की तर्ज पर त्रिवार्षिक राजकीय मेला भी विशेष आकर्षण का केंद्र है।

◆ पर्यटन मानचित्र पर शामिल हुआ पवित्र बौख नाग धाम

पथरेश्वर महादेव मंदिर में दो साधुओं की बेरहमी से हत्या, जंगल में दफनाए शव

◆ जंगल में गड्ढे से मिले दो साधुओं के शव, जांच तेज

◆ मंदिर में रह रहे दो साधुओं की हत्या से मचा हड़कंप

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार जिले के पथरी क्षेत्र स्थित पथरेश्वर महादेव मंदिर में दो साधुओं की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंदिर में रहने वाले दोनों साधुओं के शव मंदिर के पास जंगल क्षेत्र में गड्ढे से बरामद किए गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

पुलिस के अनुसार मंदिर के एक सेवादार ने साधु सेवा गिरी और उत्तम गिरी के लापता होने तथा किसी अनहोनी की आशंका की जानकारी दी थी। इसके बाद पथरी थाना प्रभारी रविंद्र सिंह पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान मंदिर के समीप जंगल में खुदाई कराई गई, जहां से दोनों साधुओं के शव बरामद हुए।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शवों को गड्ढे में दफनाया गया। घटना के संबंध में मंदिर में कुछ दिन पहले ठहरे तीन साधुओं पर संदेह जताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से फरार हैं।

रतूड़ा पुलिस लाइन में दौड़ और पीटी से जवानों ने बढ़ाया दमखम

रुद्रप्रयाग पुलिस की साप्ताहिक परेड में जवानों ने दिखाई फिटनेस

भारतेंदु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। पुलिस जवानों की शारीरिक क्षमता, मानसिक सतर्कता और कार्यकुशलता को बनाए रखने के उद्देश्य से रिजर्व पुलिस लाइन रतूड़ा में मंगलवार को साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग विकास पुण्डीर ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जवानों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

परेड के दौरान जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत और चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए विभिन्न गतिविधियां कराई गईं। मैदान में जवानों से दौड़ लगवाई गई, जिससे उनकी सहनशक्ति और कार्यक्षमता का विकास हो सके। इसके बाद प्रशिक्षकों की देखरेख में शारीरिक प्रशिक्षण (पीटी) और कई तरह के व्यायाम कराए गए। पुलिस विभाग का मानना है कि नियमित शारीरिक अभ्यास से जवान कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं।

पुलिस उपाधीक्षक विकास पुण्डीर ने परेड के बाद पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जवानों को अनुशासन बनाए रखने, ड्यूटी के प्रति सजग रहने और पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक रूप से मजबूत रहना भी बेहद जरूरी है।

◆ फिटनेस और सतर्कता के लिए पुलिस जवानों की साप्ताहिक परेड

उन्होंने कहा कि नियमित परेड और प्रशिक्षण कार्यक्रम जवानों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वे आम जनता की सुरक्षा एवं सेवा के लिए अधिक तत्पर रहते हैं।

यूकॉस्ट का दो दिवसीय जल एवं मृदा विज्ञान प्रशिक्षण शुरू

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) और युवा शक्ति नवसृजन समिति के संयुक्त तत्वावधान में 'मां धरा नमन' कार्यक्रम के अंतर्गत दो दिवसीय जल एवं मृदा विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण के पहले दिन यूपीईएस तथा अन्य संस्थानों के प्रशिक्षुओं को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज और जल एवं मृदा गुणवत्ता के वैज्ञानिक विश्लेषण की विस्तृत जानकारी दी गई। यूकॉस्ट की जल गुणवत्ता प्रयोगशाला में विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को जल गुणवत्ता के विभिन्न मानकों, परीक्षण विधियों तथा मृदा गुणवत्ता के आकलन से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया। कार्यक्रम में यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि 'मां धरा नमन' अभियान पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

'आओ, धरती को फिर से हरा करें' अभियान के तहत वृहद पौधा-रोपण

गोरापड़ाव जीजीआईसी में छात्राओं ने लगाए पौधे, लिया हरियाली बचाने का संकल्प

भारतेंदु संवाददाता, हल्द्वानी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव्स संस्था की ओर से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (जीजीआईसी), गोरापड़ाव में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की थीम 'आओ, धरती को फिर से हरा करें' रही।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के छायादार एवं फलदार पौधे लगाए। 'एक पौधा आप लगाइए' संकल्प के साथ प्रतिभागियों ने पौधों के संरक्षण और नियमित देखभाल का भी संकल्प लिया।

विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि छात्राओं में प्रकृति के प्रति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी और पौधों की सतत देखभाल की भावना विकसित करना है। आज लगाए गए पौधों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा।

सुरक्षित कार्यस्थल के लिए फोरगिवनेस फाउंडेशन ने आयोजित की निशुल्क कार्यशाला

जागरूकता कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रतिभागियों का सामूहिक चित्र।

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और महिला यौन अपराधों से बचाव को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था फोरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी की ओर से यूजेवीएन लिमिटेड ढाकरानी के कार्मिकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को पॉश कानून, महिला सुरक्षा और कार्यस्थल पर सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी गई।

कार्यशाला में मनोवैज्ञानिक एवं समाजसेवी डॉ. पवन शर्मा ने उदाहरणों और व्यवहारिक तरीकों से प्रतिभागियों को यौन उत्पीड़न की पहचान, बचाव के उपाय और कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना संस्थानों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिससे कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यक्षमता में सुधार होता है।

डॉ. शर्मा ने यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को सही तरीके से दर्ज कराने, आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने कई सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञ ने विस्तार से समाधान किया।

बीकेटीसी ने जांच समिति को सौंपे वित्तीय अभिलेख

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिरों की व्यवस्था होगी और पारदर्शी

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। बदरीनाथ मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले के बाद बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समिति ने चढ़ावे से संबंधित सभी वित्तीय अभिलेख उपजिलाधिकारी ज्योतिर्मठ के माध्यम से जांच समिति को सौंप दिए हैं। इन अभिलेखों की जांच गढ़वाल मंडल आयुक्त की निगरानी में की जा रही है।

बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधीनस्थ मंदिरों, गेस्ट हाउसों और विद्यालयों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने बदरीनाथ, केदारनाथ, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, ज्योतिर्मठ स्थित नृसिंह मंदिर सहित अन्य मंदिरों में चढ़ावे की गणना और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मंदिरों में प्राप्त होने वाले प्रत्येक चढ़ावे का सही तरीके से अभिलेखीकरण किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। इसके साथ ही सभी मंदिरों में लगे सीसीटीवी कैमरों को 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

खतरा बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, चार राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 153 सड़कें बंद

उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट 11 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और अगले 24 घंटों के दौरान फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) का खतरा जताया है। लगातार वर्षा के कारण प्रदेश में 153 सड़कें बंद हैं, जबकि चारधाम यात्रियों और पर्यटकों को मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार बुधवार को देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और अत्यंत तीव्र वर्षा के दौर पड़ सकते हैं।

इसके अलावा टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। विभाग ने अगले सात दिनों तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना व्यक्त की है।

शिरोमणि अकाली दल में बड़ी टूट, 15 नेताओं ने छोड़ी पार्टी; नए दल का ऐलान

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़।

पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 15 वरिष्ठ नेताओं ने संगठन से अलग होने का फैसला करते हुए नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर दिया है। बागी नेताओं के इस कदम से राज्य की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है।

जानकारी के अनुसार, इन नेताओं ने पार्टी की मौजूदा कार्यप्रणाली और फैसलों को लेकर नाराजगी जताई थी। उनका कहना है कि पंजाब के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए एक नए राजनीतिक मंच की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी को देखते हुए उन्होंने अलग संगठन बनाने का निर्णय लिया है। नए दल के गठन को लेकर नेताओं ने संकेत दिया है कि वे पंजाब की क्षेत्रीय राजनीति को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने राज्य के किसानों, युवाओं, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताई है।

सूत्रों के मुताबिक, नए दल की ओर से अमृतपाल सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चा चल रही है। यदि यह गठबंधन होता है तो पंजाब की आगामी राजनीतिक दिशा पर इसका असर पड़ सकता है। अकाली दल के लिए यह घटनाक्रम चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी पहले भी कई बार आंतरिक मतभेदों और राजनीतिक नुकसान का सामना कर चुकी है।

बागी नेताओं के अलग होने से संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं, पंजाब की अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। नए दल के गठन और संभावित गठबंधन के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।

अवैध खनन पर सैटेलाइट की नजर, हर छह महीने होगी 3डी निगरानी

अरावली में अवैध खनन रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा, सैटेलाइट रिकॉर्ड होगा सुरक्षित

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

अरावली क्षेत्र में अवैध खनन और प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह खनन क्षेत्रों की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करे, जिससे अवैध खनन की पहचान और रोकथाम को प्रभावी बनाया जा सके।

अदालत के निर्देशों के अनुसार, खनन क्षेत्रों की हर छह महीने में त्रिआयामी (3डी) सैटेलाइट इमेजिंग करवाई जाएगी। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों के भौगोलिक निर्देशांक (जियो-कोऑर्डिनेट्स) का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी क्षेत्र में स्वीकृत सीमा से अधिक खनन तो नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट का मानना है कि तकनीक के माध्यम से निगरानी करने से अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है।

अदालत ने यह भी सुझाव दिया है कि खनन स्थलों से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार किया जाए। इससे आम लोग भी पर्यावरण नियमों के उल्लंघन या अवैध खनन की शिकायत आसानी से दर्ज करा सकेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को अगली सुनवाई तक इस संबंध में अपना प्रस्ताव और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला चरखी दादरी जिले के पिचोपा कलां गांव में कथित अवैध खनन से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान आरोप लगाया गया कि खनन करने वालों ने निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र में गतिविधियां संचालित कीं।

इससे अरावली की प्राकृतिक संरचना, पर्यावरण और आसपास की कृषि भूमि को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया पर्यावरण को गंभीर नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर दोहन के संकेत मिले हैं। अदालत ने चिंता जताई कि लंबे समय तक प्राकृतिक क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां चलने से पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो सकता है।

हालांकि, अब तक जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय नहीं हो पाई है। अदालत ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। सैटेलाइट तकनीक के इस्तेमाल से खनन गतिविधियों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा और समय रहते कार्रवाई संभव होगी।

अरावली क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां होने वाली अवैध खनन गतिविधियों से पहाड़ियों, वन क्षेत्र और जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। पर्यावरण विशेषज्ञ भी लंबे समय से अरावली संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग करते रहे हैं। अब हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्र और राज्य सरकार को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए ठोस योजना तैयार करनी होगी। माना जा रहा है कि 3डी सैटेलाइट निगरानी व्यवस्था लागू होने के बाद खनन क्षेत्रों में होने वाली अनियमितताओं पर नजर रखना आसान होगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में भी मदद मिलेगी।

न्यूज ब्रीफ

चंडीगढ़ में 16 हजार अलॉटियों पर 90 करोड़ बकाया, सीएचबी लाएगा ओटीएस योजना

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने करीब 16 हजार अलॉटियों पर लंबित 90 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत डिफाल्टर अलॉटियों को बकाया राशि जमा कराने का अंतिम अवसर दिया जाएगा। सीएचबी का उद्देश्य लंबे समय से लंबित भुगतान को निपटाना और राजस्व बढ़ाना है। अधिकारियों के अनुसार, कई अलॉटी समय पर किश्त और अन्य शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण बड़ी राशि अटकी हुई है। ओटीएस योजना लागू होने के बाद पात्र लोगों को एकमुश्त भुगतान कर राहत मिल सकती है। बोर्ड जल्द ही योजना की शर्तों और प्रक्रिया की जानकारी जारी करेगा।

चंडीगढ़ में पुलिस बीट बॉक्स पर वेंडर का कब्जा, ताला लगाकर रखा सामान

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पुलिस बीट बॉक्स पर वेंडर के कब्जे का मामला सामने आया है। बीट बॉक्स के अंदर वेंडर द्वारा सामान रखे जाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। वीडियो में पुलिस बूथ पर ताला लगा दिखाई दे रहा है और अंदर सामान रखा हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं कि पुलिस निगरानी के लिए बनाए गए बीट बॉक्स का इस्तेमाल निजी सामान रखने के लिए कैसे किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाना प्रभारी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और नियमों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

28 साल सेवा के बाद बर्खास्तगी रद्द, हाईकोर्ट ने कर्मचारी की बहाली के दिए आदेश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 साल तक बैंक में सेवा देने वाले कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए बहाली के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए सेवा समाप्त होना केवल रोजगार खत्म होना नहीं होता, बल्कि इससे कर्मचारी और उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होती है। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति कर्मचारी के लिए आर्थिक मृत्यु जैसी हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय कर्मचारी की सेवा अवधि, पिछला रिकॉर्ड और आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखना जरूरी है। फैसले से कर्मचारी को दोबारा नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

8 एसआईटी, 3 सरकारें और 11 साल का इंतजार, बरगाड़ी केस में इंसाफ बाकी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब का बरगाड़ी बेअदबी कांड और इसके बाद हुआ बहिबल कलां गोलीकांड आज भी राज्य की सियासत में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अक्तूबर 2015 में हुई इस घटना के करीब 11 साल बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया है। इस दौरान पंजाब में तीन सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन दोषियों को सजा दिलाने का मामला अभी तक अधूरा है। इस मामले की जांच के लिए अब तक आठ बार विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। इसके अलावा जस्टिस रणजीत सिंह आयोग ने भी मामले की जांच की थी। जांच के दौरान कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन अभी तक किसी को अंतिम सजा नहीं मिल सकी है। चुनावों से पहले यह मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाता है। सभी दल पीड़ितों को न्याय दिलाने का दावा करते हैं, लेकिन लंबे समय से लंबित कार्रवाई पर सवाल उठते रहे हैं।

पंजाब में ट्रेन उड़ाने की साजिश नाकाम आतंकी नेटवर्क के 17 साथी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली।

पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए विदेश में बैठे आतंकी के नेटवर्क से जुड़े 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपित फिरोजपुर-जम्मू रेल मार्ग पर ट्रेन को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आईईडी, डेटोनेटर, ग्लॉक पिस्टल समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क को विदेश में बैठे एक आतंकी द्वारा संचालित किया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपित कथित तौर पर उसके संपर्क में थे और पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे। सुरक्षा एजेंसियों को मिली सूचना के आधार पर कई स्थानों पर कार्रवाई कर इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, बरामद सामग्री की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपितों का नेटवर्क कितना बड़ा है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस साजिश में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। सुरक्षा एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि आरोपितों ने इससे पहले किसी अन्य वारदात को अंजाम दिया है या नहीं। इसके अलावा विदेश से मिलने वाले निर्देशों, आर्थिक मदद और संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है।

रेलवे सुरक्षा को देखते हुए पंजाब के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि समय रहते कार्रवाई होने से बड़ी घटना को टाल दिया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें। जांच एजेंसियां गिरफ्तार आरोपितों के मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही हैं।

बारिश से बढ़ी मुश्किलें, पठानकोट में भूस्खलन; पंजाब-चंडीगढ़ में अलर्ट जारी

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

पंजाब में मानसून की सक्रियता के बीच कई इलाकों में बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पठानकोट जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिससे कई गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा गिरने से सड़क मार्ग बाधित हुए हैं और लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भूस्खलन वाले स्थानों पर मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर उन इलाकों में जहां पहाड़ी ढलानों और कमजोर रास्तों के कारण खतरा अधिक बना हुआ है। वहीं, अमृतसर में भी बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण मौसम सुहावना हुआ, लेकिन कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।

मोहाली में सुबह से ही बादल छाए रहे और मौसम में ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग ने पंजाब और चंडीगढ़ में अगले तीन दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। लोगों को नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बारिश के चलते प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

नगर निकायों और आपदा प्रबंधन टीमों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। किसानों के लिए भी बारिश महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे फसलों को फायदा मिल सकता है। हालांकि, अधिक बारिश होने पर जलभराव और फसल नुकसान की आशंका भी बनी रहती है।

आठ साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में गवाह की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस से मांगा गया जवाब

चंडीगढ़ पुलिस पर सवाल, गवाह धमकी मामले में कोर्ट सख्त

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

रिश्वतखोरी के आठ साल पुराने मामले में नया मोड़ सामने आया है। मामले में फंसे पुलिसकर्मियों पर गवाह को धमकाने के आरोप लगे हैं। धमकियों से परेशान होकर गवाह ने सीबीआई की विशेष अदालत में सुरक्षा की मांग करते हुए अर्जी दायर की है। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2018 का है, जब चंडीगढ़ पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की गई थी। अब केस की सुनवाई के दौरान गवाह ने आरोप लगाया है कि उसे लगातार दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और धमकियां दी जा रही हैं। गवाह ने अदालत को बताया कि उसे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। उसने मांग की है कि उसे उचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह बिना किसी डर के अदालत में अपना पक्ष रख सके।

गवाह की शिकायत के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लिया। अदालत ने सीबीआई और चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि गवाह की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और आरोपों की जांच के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। इस मामले के सामने आने के बाद चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में गवाहों की सुरक्षा को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कई बार डर और दबाव के कारण गवाह अपने बयान बदल सकते हैं या मामले की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। सीबीआई कोर्ट के निर्देश के बाद अब पुलिस विभाग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। जांच एजेंसी भी मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर नजर रख रही है। वर्ष 2018 के इस रिश्वत मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है। अब गवाह को धमकी देने के आरोपों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अदालत के अगले आदेश का इंतजार है। माना जा रहा है कि एसएसपी की रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी।

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अदालतें लगातार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं कि गवाह बिना किसी भय के न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। इस मामले में भी कोर्ट का मुख्य उद्देश्य गवाह की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है। अब अदालत के निर्देश के बाद चंडीगढ़ पुलिस और सीबीआई की भूमिका पर नजर रहेगी। एसएसपी की रिपोर्ट में गवाह की सुरक्षा और धमकी के आरोपों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी।

बलौंगी पुल पर खतरा, ज्वॉइंट में आई दरार से वाहन चालकों की बढ़ी चिंता

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। बलौंगी जाने वाले पुल से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। पुल के एक्सपेंशन ज्वॉइंट में बड़ा गैप आने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। बारिश के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो गई है, क्योंकि पानी भरने और फिसलन के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

यह पुल मोहाली, बलौंगी और आसपास के कई क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां से रोजाना हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। नौकरीपेशा लोगों, स्कूली वाहनों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही के कारण इस मार्ग पर हमेशा दबाव बना रहता है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों के अनुसार, एक्सपेंशन ज्वॉइंट में आए गैप के कारण खासकर दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। तेज गति से गुजरने पर वाहन के संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है। बारिश के दौरान सड़क की स्थिति और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल की स्थिति का तुरंत निरीक्षण करवाया जाए और जल्द से जल्द मरम्मत कार्य शुरू किया जाए। साथ ही, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक सुरक्षा के लिए उचित संकेतक और बैरिकेड लगाए जाएं, ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके।

प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में आधिकारिक कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की मरम्मत में देरी करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। बारिश के मौसम को देखते हुए जल्द कदम उठाना जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की नियमित जांच और रखरखाव नहीं होने के कारण ऐसी समस्या सामने आई है। लगातार बारिश के बीच अगर समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। वाहन चालकों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द तकनीकी टीम भेजकर ज्वॉइंट की जांच करवाई जाए और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित किया जाए।

किसानों और पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने किसानों पर पुलिस कार्रवाई और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आवाज को दबाने के लिए सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित कर रही है। वड़िंग ने कहा कि किसानों को अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने का पूरा अधिकार है और कांग्रेस उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी रहेगी।

राजा वड़िंग ने दिल्ली कूच से पहले किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि रात के समय पुलिस बल का इस्तेमाल कर किसानों को रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं को सुनना चाहिए और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए, न कि कार्रवाई के जरिए उनकी आवाज दबाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस किसानों के हर जायज आंदोलन का समर्थन करेगी।

जरूरत पड़ने पर पार्टी कार्यकर्ता किसानों के साथ सड़क पर उतरकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। वड़िंग ने केंद्र सरकार से अपील की कि किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और उनके साथ सम्मानजनक बातचीत की जाए। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने देश में बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा।

उन्होंने सवाल उठाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक के लिए जिम्मेदारी किसकी है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। वड़िंग ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने से लाखों छात्रों की मेहनत प्रभावित होती है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की और कहा कि परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार की भी आलोचना की।

वड़िंग ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दे केवल राजनीतिक विषय नहीं हैं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़े मामले हैं।

पेपर लीक पर केंद्र से जवाब

वड़िंग ने कहा कि किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने वाले लोगों के साथ सख्ती करना उचित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह संवाद के रास्ते को अपनाए और सभी पक्षों की बात सुने। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं देश की परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। इससे मेहनती छात्रों का विश्वास कमजोर होता है और भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों और छात्रों से जुड़े हर मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी। पार्टी का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सामने लाना और सरकार से जवाबदेही तय कराना है। वड़िंग ने केंद्र से आग्रह किया कि वह किसानों की मांगों और युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से लेकर जल्द समाधान निकाले। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है।

पंजाब में एससी छात्रों को 15 अगस्त तक बैंक खाता आधार से लिंक करने का निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। सरकार ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे 15 अगस्त 2026 तक अपने बैंक खाते को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करवा लें, ताकि उन्हें पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ समय पर मिल सके।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना के तहत लंबित राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जानी है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते आधार से जुड़े नहीं होंगे, उनके खाते में छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। मंत्री ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2025-26 तक कई ऐसे विद्यार्थियों की सूची तैयार की गई है, जिनकी छात्रवृत्ति केवल बैंक खाते की आधार लिंकिंग पूरी नहीं होने के कारण रुकी हुई है। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपना नाम सूची में जांचें और जल्द से जल्द बैंक जाकर खाते को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करें।

सरकार ने यह सूची डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल और पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी जांच सकते हैं और किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित बैंक या विभाग से संपर्क कर सकते हैं। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास और सशक्तीकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य विद्यार्थी केवल तकनीकी या दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करने में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसलिए सभी पात्र विद्यार्थियों को समय सीमा के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि 15 अगस्त 2026 तक आधार से जुड़े सक्रिय बैंक खाते की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है, ताकि छात्रवृत्ति राशि के वितरण में किसी प्रकार की परेशानी न आए।

पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से, सीएम मान ने किए कई बड़े ऐलान

मानसून सत्र में किसान मुद्दे, नए राशन कार्ड और जनहित योजनाओं पर होगी अहम चर्चा

भारतेंदु संवाददाता, मोहाली

पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा। सत्र को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता और किसानों के हितों को लेकर विधानसभा में अपनी बात मजबूती से रखेगी।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब सरकार प्रदेश में 10 लाख नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। नए राशन कार्ड बनने से बड़ी संख्या में लोगों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा। सीएम मान ने केंद्र सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और उनके हितों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि किसानों से उनका हक न छीना जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

किसान देश के लिए अन्न पैदा करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को विधानसभा और अन्य मंचों पर उठाती रहेगी।

मानसून सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाएं और जनकल्याण योजनाएं शामिल हो सकती हैं। विपक्ष भी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, विधानसभा का यह सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें किसानों, सरकारी योजनाओं और राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर बहस हो सकती है। सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष विभिन्न मामलों को लेकर सवाल उठा सकता है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना और किसानों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। राशन कार्ड योजना को लेकर सरकार का कहना है कि इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी। नए लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। इससे राज्य में कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ेगा।

किसान मुद्दे पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना है। पंजाब में किसान आंदोलन और कृषि नीतियां लंबे समय से प्रमुख राजनीतिक मुद्दे रहे हैं। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान इस विषय पर चर्चा होने के आसार हैं। विधानसभा सत्र को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विधायकों के सवाल, विभिन्न विभागों की रिपोर्ट और सरकारी प्रस्तावों को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है।

कुल मिलाकर पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम रहने वाला है। जहां सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं को सामने रखेगी, वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग सकता है। कुल मिलाकर पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम रहने वाला है। सत्र के दौरान सरकार जहां अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने रखने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। किसानों के मुद्दे, राशन कार्ड योजना, विकास कार्य, कानून व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाएं सदन में प्रमुख विषय बन सकती हैं। विधानसभा सत्र को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

ब्रिक्स देशों के हेल्थ सिस्टम में शामिल होगा योग आयुर्वेद, चंडीगढ़ में 21 देशों के प्रतिनिधियों ने किया मंथन

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों योग और आयुर्वेद को अब वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में नई पहचान मिलने जा रही है। चंडीगढ़ में आयोजित हो रहे ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में योग और आयुर्वेद को ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की जा रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस चार दिवसीय सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, अनुभवों का आदान-प्रदान करना और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के बेहतर समन्वय पर विचार करना है। बैठक में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य पारंपरिक उपचार पद्धतियों को लेकर विभिन्न देशों के विशेषज्ञ अपने विचार साझा कर रहे हैं। भारत ने लंबे समय से योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया है। योग को पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और जीवनशैली सुधार के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। वहीं आयुर्वेद भी कई देशों में प्राकृतिक उपचार पद्धति के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पारंपरिक चिकित्सा को वैज्ञानिक शोध और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसके लिए ब्रिक्स देशों के बीच शोध, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, बदलती जीवनशैली और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच योग और आयुर्वेद जैसी पद्धतियां लोगों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती हैं। भारत का प्रयास है कि इन चिकित्सा पद्धतियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और विस्तार मिले। चंडीगढ़ में हो रहे इस सम्मेलन को भारत की पारंपरिक चिकित्सा कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य की रणनीतियों पर भी विचार किया जा रहा है।

ब्रिक्स देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा को लेकर यह पहल वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में नए अवसर खोल सकती है। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, पारंपरिक चिकित्सा के मानकीकरण और नई शोध परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की जा रही है। भारत का लक्ष्य योग और आयुर्वेद को विश्व स्तर पर सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक आधार वाली चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करना है।

नीट पेपर लीक और किसान आंदोलन पर हरसिमरत कौर ने केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग की

भारतेंदु संवाददाता, बठिंडा । बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने नीट पेपर लीक मामले और किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार से गंभीरता से विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक जैसी घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं और इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

संसद के मानसून सत्र के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं वास्तविक हैं। उन्होंने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के साथ-साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई तकनीकी कमियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जीवनभर की कमाई खर्च करते हैं, ऐसे में परीक्षा व्यवस्था में खामियां होना बेहद चिंताजनक है। हरसिमरत कौर ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे चौंकाने वाला बताते हुए

कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाले छात्रों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि छात्रों की समस्याओं को सुनकर बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए।

इसके अलावा हरसिमरत कौर ने पंजाब के किसानों के मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने किसानों की मांगों को लेकर सरकार से संवाद बनाए रखने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि किसानों से जुड़े विषयों पर बातचीत के जरिए रास्ता निकालना जरूरी है, ताकि सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जा सके।

उन्होंने कहा कि शिक्षा और कृषि दोनों ही देश के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सरकार को इनसे जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई, जिससे छात्रों का विश्वास बना रहे। हरसिमरत कौर के बयान के बाद नीट पेपर लीक और किसान मुद्दों को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।

ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी ड्राइवर से बदसलूकी, रेडियो संदेशों पर मचा विवाद

भारतेंदु संवाददाता, पठानकोट। ऑस्ट्रेलिया में एक पंजाबी ड्राइवर के साथ हुई कथित बदसलूकी और आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, ड्राइवर पर थूकने की घटना के बाद विवाद बढ़ गया। इसके अलावा रेडियो प्रसारण के दौरान बच्चों की हत्या और महिलाओं को गुलाम बनाने जैसी धमकियों वाले संदेशों को लेकर भी चिंता जताई गई है। मामले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के गृहमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे समाज के लिए कड़वा सच बताया और कहा कि नफरत फैलाने वाली सोच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई और जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया। घटना के बाद प्रवासी समुदायों में नाराजगी देखने को मिली है। लोगों ने मांग की है कि नस्लीय भेदभाव और घृणा फैलाने वाली गतिविधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। प्रशासन मामले की जांच और संबंधित कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के प्रयास जारी रहेंगे।

फाजिल्का और अबोहर चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज

नगर निकाय चुनाव को लेकर पंजाब में तेज हुई राजनीति, सुरक्षा के बीच होगा फैसला

भारतेंदु संवाददाता, फाजिल्का। नगर परिषद अध्यक्ष और अबोहर नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर मंगलवार को राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। चुनाव से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत कर दिया। डीसी कार्यालय परिसर और चुनाव स्थलों के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं।

फाजिल्का नगर परिषद अध्यक्ष और अबोहर नगर निगम मेयर पद के चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में लगातार बैठकों और रणनीति बनाने का दौर चलता रहा। चुनाव से कुछ घंटे पहले ही नेताओं की सक्रियता बढ़ गई। भाजपा सहित कई दलों के प्रमुख नेता भी चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मौके पर पहुंचे। परिसर में प्रवेश को लेकर भी

सख्ती बरती गई। सुरक्षा कर्मियों ने आने-जाने वाले लोगों की जांच की और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई।

चुनाव स्थल के आसपास बैरिकेडिंग कर यातायात और भीड़ को नियंत्रित किया गया। हाईकोर्ट की निगरानी में हो रहे इन चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में विशेष उत्साह देखा गया। दोनों निकायों में अध्यक्ष और मेयर पद के लिए मुकाबला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव परिणाम स्थानीय राजनीति की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

फाजिल्का और अबोहर क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव लंबे समय से राजनीतिक चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अध्यक्ष और मेयर पद हासिल करने के लिए विभिन्न दलों ने अपने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश की। नेताओं ने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए लगातार संपर्क अभियान चलाया।

जिला प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रखा गया है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, फाजिल्का नगर परिषद अध्यक्ष और अबोहर नगर निगम मेयर चुनाव स्थानीय स्तर पर दलों की पकड़ और संगठनात्मक ताकत का भी परीक्षण माना जा रहा है।

पंजाब में निजी स्कूलों की फीस पर सख्ती, संचालकों ने जताई आपत्ति

भारतेंदु संवाददाता चंडीगढ़ । पंजाब सरकार की ओर से निजी स्कूलों की वार्षिक फीस वृद्धि को पांच प्रतिशत तक सीमित करने के फैसले का निजी स्कूल संगठनों ने विरोध किया है। स्कूल संचालकों का कहना है कि फीस वृद्धि की सीमा तय करने से पहले सभी पक्षों से चर्चा की जानी चाहिए थी। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की मांग की है।

सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के साथ ही पिछले तीन वर्षों में निर्धारित सीमा से अधिक ली गई फीस को वापस करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद निजी स्कूल प्रबंधन संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। स्कूल संचालकों का तर्क है कि फीस में बदलाव स्कूलों के संचालन खर्च, शिक्षकों के

वेतन, सुविधाओं और अन्य आवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

निजी स्कूल संगठनों ने कहा कि अचानक फीस सीमा तय करने और पुरानी फीस वापसी के आदेश से स्कूलों के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के साथ बैठक कर व्यावहारिक नीति तैयार की जाए।

शंभू बॉर्डर बंदी के बीच पुलिस ने यात्रियों को दिए नए रास्ते

शंभू बॉर्डर बंद होने से यातायात प्रभावित राजपुरा पुलिस ने जारी किए वैकल्पिक मार्ग

भारतेंदु संवाददाता, राजपुरा। शंभू बॉर्डर बंद रहने के कारण पंजाब और हरियाणा के बीच आवागमन प्रभावित हो रहा है। यात्रियों को जाम और परेशानी से बचाने के लिए पटियाला के राजपुरा ट्रैफिक पुलिस ने नए वैकल्पिक मार्ग जारी किए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले निर्धारित रूट का इस्तेमाल करें, ताकि समय और परेशानी दोनों से बचा जा सके।

राजपुरा ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज गुरबचन सिंह ने बताया कि शंभू बॉर्डर बंद होने से दिल्ली, अंबाला, लुधियाना और अन्य प्रमुख शहरों की ओर जाने वाले मार्गों पर

वाहनों का दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए अलग-अलग रास्तों की जानकारी जारी की गई है।

दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राजपुरा से गगन चौक होते हुए जीरकपुर-डेराबस्सी मार्ग का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा राजपुरा से गांव भोगला, जनड मंगोली और पीपल मंगोली के रास्ते अंबाला होते हुए दिल्ली पहुंचने का मार्ग भी बताया गया है।

पटियाला से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बहादुरगढ़ से घनौर और कपूररी के रास्ते अंबाला की ओर जाने की सलाह दी गई है।

कुत्तों के काटने से बुजुर्गों की मौत

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर पंजाब मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। कुत्तों के काटने से दो बुजुर्गों की मौत के मामलों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने लुधियाना और अमृतसर के जिला उपायुक्तों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने प्रशासन से पूछा है कि आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या योजना बनाई गई है। बताया जा रहा है कि दोनों जिलों में कुत्तों के हमलों की घटनाओं ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

फरीदकोट में कूड़ा उठाने पहुंची प्रशासनिक टीम का विरोध, सफाईकर्मियों ने रोका

भारतेंदु संवाददाता, फरीदकोट । फरीदकोट में सफाई व्यवस्था को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को प्रशासनिक टीम कूड़ा उठाने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन हड़ताल पर बैठे सफाईकर्मियों ने टीम का विरोध करते हुए काम रोक दिया। अधिकारियों के पहुंचने के बाद मौके पर कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई।

जानकारी के अनुसार, शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कूड़ा जमा हो रहा था। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कूड़ा उठाने की कार्रवाई शुरू की। इसके लिए अधिकारियों के नेतृत्व में टीम को विभिन्न इलाकों में भेजा गया। जैसे ही प्रशासनिक टीम कूड़ा उठाने

पहुंची, हड़ताली सफाईकर्मियों ने इसका विरोध किया और कर्मचारियों को काम करने से रोकने का प्रयास किया।

सफाईकर्मियों का कहना था कि उनकी मांगों को नजरअंदाज कर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कूड़ा उठाना आवश्यक है। अधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है। फिलहाल प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच गतिरोध जारी है।

शादी के ढाई महीने बाद एनआरआई दूल्हे की मौत, पत्नी ने बताई हैरान करने वाली बात

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में शादी के महज ढाई महीने बाद एक एनआरआई दूल्हे की मौत का मामला सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने उसे कुछ समय पहले दवाइयां खाते हुए देखा था। जब उसने दवाइयां लेने का कारण पूछा तो पति ने बताया था कि जिम में चोट लगने के कारण वह इन्हें खा रहा है।

जानकारी के अनुसार, मृतक की शादी हाल ही में हुई थी और परिवार में खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक हुई मौत के बाद परिजनों और रिश्तेदारों में मातम छा गया। घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। परिवार के अनुसार, मृतक विदेश में रहता था और शादी के बाद पंजाब आया था। पत्नी ने बताया कि उसने कई बार उसे दवाइयां लेते देखा था। पूछने पर उसने चोट लगने की बात कही थी। हालांकि, मौत के बाद इन दवाइयों को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। घटना के बाद मृतक के परिवार और ससुराल पक्ष से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं, इस घटना ने इलाके में भी चर्चा बढ़ा दी है। शादी के कुछ ही समय बाद हुई इस मौत से परिवार सदमे में है और सभी की नजर पुलिस जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतक के परिवार ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं और लोग पुलिस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं।

सख्ती अमेरिकी इमिग्रेशन विशेषज्ञ ने युवाओं को वैध प्रक्रिया अपनाने की दी सलाह

ट्रंप की सख्ती से पंजाबियों पर असर, अमेरिका जाने के अवैध रास्ते हुए बंद

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। अमेरिका की बदलती इमिग्रेशन नीतियों का सबसे अधिक असर पंजाब पर पड़ने का दावा किया गया है। अमेरिका के इमिग्रेशन कानून विशेषज्ञ और अटॉर्नी जसप्रीत सिंह ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की सख्त नीतियों के कारण अब अवैध रास्तों से अमेरिका पहुंचना और वहां स्थायी होने की संभावनाएं काफी कम हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि मैक्सिको बॉर्डर के जरिए अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए हालात पहले की तुलना में बेहद कठिन हो गए हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित 'रूबरू' कार्यक्रम के दौरान जसप्रीत सिंह ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासन की बदलती तस्वीर, भारत अमेरिका संबंध और पंजाब पर इसके प्रभाव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग मैक्सिको सीमा के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे।

उस समय पैरोल, बॉन्ड और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए कई लोगों को राहत मिल जाती थी, लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन ने सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन व्यवस्थाओं को काफी सख्त कर दिया है। विशेषज्ञ ने बताया कि पहले कई लोग अमेरिका पहुंचने के बाद पैरोल या वर्क परमिट मिलने की उम्मीद रखते थे, लेकिन वर्तमान नीतियों में यह प्रक्रिया बेहद कठिन हो गई है। उन्होंने कहा कि अब विदेश

जाने वाले लोगों को अवैध रास्तों के बजाय वैध वीजा और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जसप्रीत सिंह के अनुसार, पंजाब से बड़ी संख्या में युवा बेहतर रोजगार, आर्थिक अवसर और भविष्य की उम्मीदों के कारण अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अमेरिकी नीतियों में बदलाव का सीधा असर पंजाब के परिवारों और युवाओं पर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि कई लोग एजेंटों के झांसे में आकर लाखों रुपये खर्च कर देते हैं और बाद में उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि विदेश जाने से पहले सभी नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं की सही जानकारी हासिल करें। गलत जानकारी या अवैध तरीकों से विदेश जाने की कोशिश भविष्य में बड़ी समस्या पैदा कर सकती है।

कार्यक्रम में भारत-अमेरिका संबंधों और प्रवासन से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञ ने कहा कि दुनिया भर में इमिग्रेशन नियम लगातार बदल रहे हैं और हर देश अपनी सुरक्षा और आर्थिक नीतियों के अनुसार फैसले ले रहा है। ऐसे में विदेश जाने की इच्छा रखने वालों को बदलते नियमों के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। और वैध प्रक्रिया अपनाना जरूरी है।

मंदिरों के चढ़ावे का पारदर्शी प्रबंधन समय की मांग श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोपरि

देश में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक संरचना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक आस्था का जीवंत प्रतीक भी है।

ऐसे पवित्र स्थल पर यदि श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धाभाव से अर्पित चढ़ावे से जुड़ी किसी भी प्रकार की चोरी, अनियमितता या गड़बड़ी की बात सामने आती है, तो यह केवल वित्तीय अपराध नहीं रह जाता, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और विश्वास पर भी गहरी चोट के रूप में देखा जाता है। मंदिरों में चढ़ाया गया प्रत्येक रुपया, प्रत्येक आभूषण और प्रत्येक भेंट किसी न किसी श्रद्धालु की आस्था का प्रतिनिधित्व करता है। लोग यह विश्वास करके दान करते हैं कि उनका अर्पण धर्म, समाज सेवा, जनकल्याण और मंदिर व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन में ईमानदारी से उपयोग होगा। ऐसे में यदि इस व्यवस्था में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, चोरी या अनियमितता सामने आती है, तो स्वाभाविक रूप से न केवल प्रबंधन की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही भी कठघरे में आ जाती है। यह प्रश्न केवल किसी एक मंदिर या किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। यह व्यापक रूप से उन सभी धार्मिक संस्थानों के लिए चेतावनी है, जहां बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावा एकत्र होता है। आस्था के केंद्रों में वित्तीय प्रबंधन की प्र्, या को अब अधिक आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने की आवश्यकता है।

राजन कुमार शर्मा
डुगली, लंबलू (हमीरपुर)

सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल दान प्रणाली, ऑनलाइन ट्रैकिंग, नियमित ऑडिट, रियल-टाइम अकाउंटिंग और स्वतंत्र जांच तंत्र जैसी व्यवस्थाएँ अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को न्यूनतम किया जा सके और श्रद्धालुओं का विश्वास अक्षुण्ण रहे। धर्म का मूल आधार सत्य, ईमानदारी और नैतिकता है। यदि धार्मिक संस्थानों के भीतर ही इन मूल्यों का उल्लंघन होने लगे, तो समाज में एक गलत और खतरनाक संदेश जाता है। आस्था केवल भावनाओं का विषय नहीं, बल्कि एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में बिना किसी दबाव या पक्षपात के निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार की लीपापोती या उदासीनता भविष्य में ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा दे सकती है, जिससे समाज का विश्वास व्यवस्था से कमजोर हो सकता है। आस्था का सम्मान केवल भव्य मंदिरों, विशाल संरचनाओं या आकर्षक स्थापत्य से नहीं होता, बल्कि उनकी पवित्रता, पारदर्शिता और ईमानदार प्रशासन से होता है। करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोपरि है, और उसकी रक्षा करना केवल मंदिर प्रशासन ही नहीं, बल्कि संबंधित सरकारी और सामाजिक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है।

राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर पारदर्शिता का प्रश्न और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और पहचान से जुड़ा प्रतीक है। इसलिए यहां किसी भी प्रकार की अनियमितता की जांच अत्यंत गंभीरता, निष्पक्षता और तेजी के साथ होनी चाहिए, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। समय की मांग है कि धार्मिक संस्थाएं भी आधुनिक प्रशासनिक मानकों को अपनाएं। दान और चढ़ावे की पूरी प्र्, या डिजिटल हो, ताकि हर लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। साथ ही, ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित हो सकें।

धार्मिक स्थलों की गरिमा केवल उनकी भव्यता या ऐतिहासिक महत्व से नहीं, बल्कि उनके संचालन में अपनाई जाने वाली पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी से भी निर्धारित होती है। श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई से दान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि यह राशि धर्म, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गौसेवा, गरीबों की सहायता और मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए सदुपयोग में लाई जाएगी। यदि इस विश्वास को किसी भी स्तर पर ठेस पहुंचती है, तो उसका प्रभाव केवल एक संस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज में अविश्वास का वातावरण बन सकता है।

इसलिए आवश्यक है कि धार्मिक संस्थानों में आधुनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, नियमित स्वतंत्र लेखा परीक्षण, सामाजिक निगरानी और जनसहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इससे न केवल श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक मजबूत होगा, बल्कि धर्मस्थलों की पवित्रता, विश्वसनीयता और सामाजिक प्रतिष्ठा भी अक्षुण्ण बनी रहेगी। अंततः किसी भी मंदिर की सबसे बड़ी पूंजी उसका धन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास होता है और उस विश्वास की रक्षा करना प्रत्येक संबंधित संस्था तथा समाज की साझा जिम्मेदारी है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

तुवालु का डूबता अस्तित्व जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी चेतावनी

जब एक देश अपना भूगोल खोने लगे, तब संकट केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के भविष्य का होता है, मानचित्र पर तुवालु को ढूंढना आसान नहीं है। प्रशांत महासागर के विस्तृत नीले विस्तार में बिखरे नौ छोटे-छोटे कोरल द्वीपों का यह देश क्षेत्रफल और जनसंख्या-दोनों दृष्टियों से विश्व के सबसे छोटे राष्ट्रों में गिना जाता है। लगभग 10,000 नागरिकों वाला यह द्वीपीय राष्ट्र आज उस वैश्विक संकट का सबसे मार्मिक चेहरा बन चुका है, जिसे वर्षों तक केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की बहस समझा जाता रहा-जलवायु परिवर्तन।

तुवालु का अपराध केवल इतना है कि वह समुद्र तल से औसतन दो मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसका दुर्भाग्य यह है कि उसने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग कोई योगदान नहीं दिया, फिर भी जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी कीमत वही चुका रहा है। यह विडंबना आधुनिक विकास मॉडल की सबसे बड़ी नैतिक विफलता है। आज तुवालु की धरती धीरे-धीरे समुद्र में समा रही है। बढ़ता समुद्री जलस्तर तटीय क्षेत्रों को काट रहा है, खारा पानी भूजल स्रोतों में प्रवेश कर चुका है, कृषि भूमि अनुपजाऊ होती जा रही है और हर वर्ष समुद्री तूफानों की तीव्रता बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि वैश्विक तापमान वृद्धि वर्तमान गति से जारी रही, तो इस शताब्दी के अंत तक तुवालु की राजधानी फुनाफूटी का अधिकांश भाग सामान्य उच्च ज्वार के समय ही जलमग्न हो सकता है। यह केवल भूमि के डूबने का प्रश्न नहीं है; यह एक राष्ट्र की संप्रभुता, संस्कृति, भाषा, इतिहास और सामूहिक स्मृति के विलुप्त होने का संकट है। इतिहास में अनेक सभ्यताएं युद्ध, महामारी या आर्थिक पतन से समाप्त हुई हैं, किंतु पहली बार मानव इतिहास ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां पूरा का पूरा देश जलवायु परिवर्तन के कारण मानचित्र से गायब हो सकता है।

इसी पृष्ठभूमि में ऑस्ट्रेलिया द्वारा घोषित 'क्लाइमेट वीज़ा' योजना वैश्विक राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का संकेत देती है। फालेपिली यूनियन संधि के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 280 तुवालु नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास, रोजगार और शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। यह विश्व की पहली ऐसी औपचारिक नीति है जिसने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संभावित विस्थापन को कानूनी और मानवीय आधार पर स्वीकार किया है। यह नीति केवल वीज़ा व्यवस्था नहीं है; यह स्वीकारोक्ति है कि आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन सीमाओं, नागरिकता और प्रवासन की पारंपरिक अवधारणाओं को बदल देगा। संयुक्त राष्ट्र पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यदि वैश्विक तापमान वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ, तो आने वाले दशकों में करोड़ों लोग समुद्र के बढ़ते जलस्तर, भीषण सूखे, बाढ़ और चरम मौसमी घटनाओं के कारण विस्थापित हो सकते हैं। फिर भी यह पहल अपने आप में पर्याप्त नहीं है। यदि प्रतिवर्ष केवल 280 लोगों को स्थानांतरित किया जाए, तो तुवालु की संपूर्ण आबादी को सुरक्षित स्थानांतरित करने में लगभग चार दशक लग जाएंगे।

केशव शर्मा 'रसिक'
कोटला, घुमारवीं

प्रश्न यह भी है कि क्या केवल लोगों को स्थानांतरित कर देना किसी राष्ट्र को बचा लेना कहलाएगा? क्या नागरिकों के विस्थापित हो जाने के बाद भी कोई राष्ट्र अपनी पहचान, संस्कृति, परंपरा और आत्मा को जीवित रख सकता है? यहीं से जलवायु परिवर्तन का प्रश्न केवल पर्यावरणीय न रहकर मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक न्याय का प्रश्न बन जाता है।

तुवालु ने स्वयं को केवल पीड़ित राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उसने पूरी दुनिया को झकझोरने का प्रयास भी किया। पूर्व विदेश मंत्री साइमन कोफे का समुद्र के भीतर खड़े होकर दिया गया भाषण इतिहास के सबसे प्रभावशाली जलवायु संदेशों में गिना जाता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

> **जैसे** जीने के लिए मृत्यु का अस्वीकरण जरूरी है वैसे ही सृजनशील बने रहने के लिए प्रतिष्ठा का अस्वीकरण जरूरी है।
>
> -डॉ. रघुवंश

संपादकीय

चुनावी राजनीति और बढ़ता घाटा

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं। किंतु जब कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक विकास के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ प्राप्त करना बन जाए, तब यह प्रवृत्ति न केवल सरकारी वित्त पर दबाव डालती है बल्कि भविष्य की आर्थिक स्थिरता और विकास की संभावनाओं को भी प्रभावित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट इसी गंभीर चुनौती की ओर संकेत करती है और राज्यों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता का स्पष्ट संदेश देती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 2024 के बीच अधिकांश राज्यों का सकल वित्तीय घाटा तीन प्रतिशत से नीचे बना रहा, लेकिन चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर लगभग 3.3 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। यह केवल एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि कई राज्य अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। बढ़ता वित्तीय घाटा बताता है कि सरकारी खर्च आय की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है और इस अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज का सहारा लिया जा रहा है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर राज्य की विकास क्षमता, निवेश, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ना स्वाभाविक है।

पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण आधारित योजनाओं का तेजी से विस्तार किया है। मध्यप्रदेश की लाडली बहना योजना, झारखंड की मइयां सम्मान योजना, हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना और अन्य राज्यों की समान योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाई है। महंगाई, बेरोजगारी और आय की असमानता के दौर में ऐसी योजनाओं की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए यह सहायता जीवनयापन का महत्वपूर्ण आधार बनी है। इसलिए इन योजनाओं को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। सामाजिक सुरक्षा किसी भी कल्याणकारी राज्य का आवश्यक तत्व है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन योजनाओं का विस्तार बिना पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के किया जाता है। यदि सरकारें चुनावी प्रतिस्पर्धा में एक-दूसरे से अधिक नकद सहायता देने की होड़ में शामिल हो जाएं और उसके लिए स्थायी राजस्व स्रोत विकसित न करें, तो भविष्य में गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। आज जो सहायता लोगों को राहत दे रही है, वही कल बढ़ते कर्ज, ब्याज भुगतान और विकास कार्यों में कमी का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक योजना की घोषणा से पहले उसकी वित्तीय व्यवहार्यता का गंभीर मूल्यांकन आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कई राज्यों के बढ़ते सार्वजनिक कर्ज पर भी चिंता व्यक्त की गई है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश का सार्वजनिक कर्ज सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लगभग चालीस प्रतिशत के आसपास पहुंच चुका है। राजस्थान भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जबकि केरल का ऋण स्तर भी लगातार चिंता बढ़ा रहा है। बढ़ता कर्ज केवल एक आर्थिक चुनौती नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों पर बढ़ते वित्तीय बोझ का संकेत भी है। सरकार को लिए गए ऋण पर ब्याज चुकाना पड़ता है और इसके कारण विकास संबंधी योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो जाते हैं। जब सरकारी आय का बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन जैसे अनिवार्य खर्चों में चला जाता है तब सड़क, सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, अनुसंधान और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रभावित होता है। यही वे क्षेत्र हैं जो दीर्घकाल में रोजगार पैदा करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। यदि पूंजीगत निवेश लगातार घटता है तो राज्य की विकास गति भी धीमी पड़ सकती है।

मध्यप्रदेश सहित अनेक राज्यों के लिए यह समय संतुलित आर्थिक नीति अपनाने का है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जारी रखना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ उद्योगों में निवेश, नए रोजगार, कृषि सुधार, पर्यटन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के विस्तार पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। केवल सहायता राशि वितरित करने से गरीबी स्थायी रूप से समाप्त नहीं होती। लोगों को रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना अधिक स्थायी समाधान है। यह भी समझना होगा कि सभी नकद हस्तांतरण योजनाएं गलत नहीं होतीं। यदि लाभार्थियों की स्पष्ट पहचान हो, योजना पूरी तरह पारदर्शी हो, डिजिटल माध्यम से भुगतान हो, भ्रष्टाचार की संभावना कम हो और उसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों, तो ऐसी योजनाएं सामाजिक असमानता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अनेक देशों में भी लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने गरीबी कम करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इसलिए समस्या योजनाओं में नहीं बल्कि उनके वित्तीय प्रबंधन और क्रियान्वयन के तरीके में है। राज्यों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कर संग्रह की दक्षता सुधारनी होगी। कर चोरी पर नियंत्रण, उद्योगों को प्रोत्साहन, निवेश के अनुकूल वातावरण, आधारभूत ढांचे का विस्तार और नए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना होगा। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो सरकार की आय भी बढ़ेगी और कल्याणकारी योजनाओं के लिए स्थायी संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही गैर-जरूरी सरकारी खर्चों पर नियंत्रण और वित्तीय पारदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक है।

-शिवांश धाकड़

स्वस्थ मस्तिष्क से ही संभव है बेहतर शिक्षा, सकारात्मक सोच और खुशहाल जीवन का निर्माण

हर वर्ष 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को मस्तिष्क के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों की रोकथाम उपचार और समय पर पहचान के महत्व को समझाना है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2014 में विश्व न्यूरोलॉजी महासंघ द्वारा की गई थी। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अलग अलग विषय के साथ इस दिवस का आयोजन किया जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति का शारीरिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक जीवन भी अधिक संतुलित रहेगा। इसलिए मस्तिष्क की देखभाल को संपूर्ण स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।

सुभाष चंद कासव
राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
कवि लेखक एवं साहित्यकार

मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे शरीर की लगभग हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। सोचने समझने याद रखने निर्णय लेने बोलने चलने महसूस करने और भावनाओं को व्यक्त करने जैसी सभी प्रक्रियाओं का संचालन मस्तिष्क ही करता है। हृदय की धड़कन सांस लेने की प्रक्रिया शरीर का संतुलन और विभिन्न अंगों के बीच समन्वय भी मस्तिष्क के माध्यम से ही संभव होता है। यही कारण है कि इसे शरीर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों लोग किसी न किसी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल यानी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़े रोगों से प्रभावित हैं। इनमें स्ट्रोक अल्जाइमर पार्किंसन मिर्गी माइग्रेन ब्रेन ट्यूमर मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं भी अप्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। समय पर पहचान और उचित उपचार मिलने पर इनमें से कई रोगों के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

विश्व मस्तिष्क दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि मस्तिष्क संबंधी रोग केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं हैं। आज के समय में बच्चे युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लगातार तनाव

अनियमित दिनचर्या नींद की कमी असंतुलित भोजन नशे की आदत शारीरिक गतिविधियों का अभाव और अत्यधिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए बचपन से ही स्वस्थ जीवनशैली अपनाना आवश्यक है।

आज की तेज रफ्तार जीवनशैली में मानसिक तनाव एक बड़ी चुनौती बन चुका है। नौकरी व्यवसाय पढ़ाई प्रतियोगिता आर्थिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण लोगों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। लंबे समय तक तनाव बने रहने पर याददाश्त कमजोर हो सकती है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और अवसाद जैसी समस्याएं विकसित हो सकती हैं। इसलिए विशेषज्ञ नियमित व्यायाम योग ध्यान और पर्याप्त विश्राम को मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी मानते हैं।

स्वस्थ मस्तिष्क के लिए संतुलित आहार भी अत्यंत आवश्यक है। भोजन में हरी सब्जियां ताजे फल साबुत अनाज दालें मेवे बीज और ओमेगा तीन फैटी अम्ल से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी मस्तिष्क की कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद करता है। अत्यधिक तैलीय जंक फूड और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना चाहिए क्योंकि ये लंबे समय में मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद मस्तिष्क के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। जब हम सोते हैं तब मस्तिष्क पूरे दिन की सूचनाओं को व्यवस्थित करता है और नई यादों को मजबूत बनाता है। लगातार कम नींद लेने से स्मरण शक्ति प्रभावित होती है निर्णय लेने की क्षमता घटती है और मानसिक थकान बढ़ जाती है। वयस्कों के लिए प्रतिदिन लगभग सात से आठ घंटे की नींद आवश्यक मानी जाती है।

शारीरिक गतिविधियां भी मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नियमित रूप से पैदल चलना दौड़ना साइकिल चलाना तैराकी करना या योग करना मस्तिष्क में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इससे नई तंत्रिका कोशिकाओं के विकास को प्रोत्साहन मिलता है और स्मरण शक्ति तथा एकाग्रता में सुधार होता है। व्यायाम तनाव कम करने और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी सहायक होता है। मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखने के लिए मानसिक अभ्यास भी जरूरी है। नई भाषा सीखना पुस्तकें पढ़ना पहेलियां हल करना संगीत सीखना शतरंज खेलना और नई चीजें सीखते रहना मस्तिष्क को लगातार सक्रिय रखते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

युवाओं की प्रेरणा हैं सेलेना गोमेज

सेलेना गोमेज

22 जुलाई 1992 को अमेरिका के टेक्सास राज्य के ग्रैंड प्रेयरी में जन्मी सेलेना गोमेज आज दुनिया की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं, अभिनेत्रियों, निर्माताओं और समाजसेवियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में मनोरंजन जगत में कदम रखा और अपनी प्रतिभा के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई। बचपन में उन्होंने टेलीविजन कार्यक्रमों में अभिनय करना शुरू किया, लेकिन उन्हें वास्तविक लोकप्रियता डिज्नी चैनल के धारावाहिक विजार्ड्स ऑफ वेवरली प्लेस से मिली। इस धारावाहिक में निभाए गए उनके किरदार ने उन्हें दुनिया भर के युवाओं का पसंदीदा बना दिया।

कविता

दीवार के उस पार

सतीश धर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

वो जो दीवार के उस पार हैं, सभी कुछ तो वैसा ही है
जैसा अपने देश में होता है।
फूलों पर रंग यकसा, हवाओं में मस्ती यकसा,
पेट के निवाले यकसा, पैरों में छाले यकसा,
दिलों में दर्द यकसा।
सदियां अब भी तलाश रही हैं, जो इस ओर है,
वह उस ओर क्यों नहीं।
लम्हों ने बदले पहरावे दोनों ओर,
खून ने भी बदला रंग दोनों ओर,
दीवारों पर शहादत ही, लिखी गई दोनों ओर।
बावजूद इसके, सब कुछ वैसा ही रहा,
जैसा दीवार के उस पार था।
कह दो, एक बार-दीवारों को आदत बदलनी होगी,
या फिर टूटकर बिखरना होगा।
आदत तो बदली जा सकती है,पर बिखरने का दर्द
इतिहास की कहानी बन जाती है।

सावन का पावन महीना आस्था और भक्ति के संदेश को नई ऊर्जा के साथ जोड़ता है

भारतीय संस्कृति में सावन मास का विशेष स्थान है। यह केवल वर्षा ऋतु का एक महीना नहीं बल्कि आस्था भक्ति प्रेम और प्रकृति के साथ मनुष्य के गहरे संबंध का प्रतीक भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ के बाद आने वाला श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। पूरे भारत में इस महीने का स्वागत श्रद्धा और उल्लास के साथ किया जाता है। मंदिरों में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ती है। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। व्रत उपवास रखे जाते हैं और भगवान शिव की आराधना से वातावरण भक्तिमय हो उठता है।

सावन का महीना प्रकृति की हरियाली और जीवन की नई ऊर्जा का संदेश लेकर आता है। चारों ओर वर्षा की फुहारें धरती को शीतल करती हैं। खेत लहलहाने लगते हैं। पेड़ पौधे नई हरियाली से भर जाते हैं। नदियां और झरने जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय साहित्य संगीत और लोकगीतों में सावन को प्रेम आनंद और सौंदर्य का महीना कहा गया है। कवियों ने इसे प्रकृति के नवजीवन का उत्सव बताया है।

डॉ. दमन आहूजा
'सफलता से सार्थकता तक'
किताब के लेखक

धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तब संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इसी घटना के स्मरण में सावन मास में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा प्रचलित हुई। श्रद्धालु गंगाजल दूध दही शहद घी और शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तथा सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हैं।

सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। इन दिनों शिव मंदिरों में प्रातःकाल से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। महिलाएं और पुरुष व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। अविवाहित कन्याएं योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति तथा विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि श्रद्धा और सच्चे मन से की गई शिव आराधना मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है।

सावन मास का एक महत्वपूर्ण पक्ष कांवड़ यात्रा भी है। देश के विभिन्न भागों से लाखों शिवभक्त गंगा या अन्य पवित्र नदियों से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए अपने निकटवर्ती शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं। इन श्रद्धालुओं को कांवड़िया कहा जाता है। कंधों पर सजी हुई कांवड़ लेकर वे बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष के साथ लंबी यात्राएं करते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अनुशासन धैर्य सेवा और सामूहिक आस्था का भी अद्भुत उदाहरण है। मार्ग में अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं कांवड़ियों के लिए भोजन चिकित्सा विश्राम और पेयजल की व्यवस्था करती हैं जो भारतीय समाज की सेवा भावना को भी दर्शाती है।

सावन का महीना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि यह भारतीय लोक संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में झूले डाले जाते हैं। महिलाएं और युवतियां पारंपरिक वेशभूषा धारण कर सावन के गीत गाती हैं। लोकगीतों में वर्षा ऋतु की सुंदरता प्रेम विरह और पारिवारिक संबंधों का भावपूर्ण चित्रण मिलता है। राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश हरियाणा और पंजाब सहित अनेक राज्यों में तीज का पर्व सावन में ही बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं नए वस्त्र पहनती हैं और माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह पर्व वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि और परिवार के मंगल का प्रतीक माना जाता है।

सावन का कृषि से भी गहरा संबंध है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और वर्षा किसानों के लिए जीवनदायिनी होती है। सावन में होने वाली अच्छी वर्षा से धान मक्का बाजरा सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई और वृद्धि होती है। किसान वर्षा को ईश्वर का वरदान मानते हैं क्योंकि इससे खेतों में नई जान आती है और भविष्य की समृद्धि की आशा बढ़ती है। यदि वर्षा संतुलित हो तो कृषि उत्पादन अच्छा होता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है।

आयुर्वेद के अनुसार सावन का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती है। इसलिए इस समय हल्का सुपाच्य और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। व्रत रखने की परंपरा का एक वैज्ञानिक पक्ष भी माना जाता है क्योंकि इससे शरीर को विश्राम मिलता है और भोजन में संयम बना रहता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना तथा दूषित भोजन और पानी से बचना भी इस मौसम में आवश्यक होता है।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी सावन हमें देता है। वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। अनेक स्थानों पर इस महीने में पौधारोपण अभियान चलाए जाते हैं। पेड़ पौधे केवल पर्यावरण को संतुलित नहीं रखते बल्कि वर्षा चक्र को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए सावन प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की प्रेरणा देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस महीने एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा योगदान दिया जा सकता है।

आधुनिक जीवन की भागदौड़ में सावन हमें आत्मचिंतन और मानसिक शांति का अवसर भी देता है। भगवान शिव का स्वरूप सादगी धैर्य त्याग और संतुलन का संदेश देता है। शिव की उपासना हमें क्रोध लोभ अहंकार और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने की प्रेरणा देती है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि सावन को केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं बल्कि आत्मिक विकास का भी श्रेष्ठ अवसर माना जाता है।

भारत की विविधता में एकता का सुंदर स्वरूप भी सावन में दिखाई देता है। अलग अलग राज्यों में परंपराएं भले ही अलग हों लेकिन भगवान शिव के प्रति श्रद्धा सभी को एक सूत्र में बांध देती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

उप्र में अगले सात दिन होगी झमाझम बारिश वज्रपात की भी संभावना

एजेंसी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार 21 से 27 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 और 23 जुलाई को वर्षा का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा, जबकि 24 से 27 जुलाई तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय ने किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने और जलभराव वाली फसलों की विशेष निगरानी करने की सलाह दी है। साथ ही गरज-चमक और वज्रपात के दौरान खेतों में काम नहीं करने तथा पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने की अपील की गई है।

बरहज की समस्याओं को लेकर सपा नेता विजय रावत की भूख हड़ताल शुरू

एजेंसी, देवरिया। बरहज विधानसभा क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता विजय रावत ने मंगलवार को काली मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। विजय रावत ने भाजपा सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने बरहज-सोनूघाट मार्ग की बदहाली, बिजली कटौती, मोहन सेतु निर्माण और कटान रोकने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से समस्याओं का समाधान नहीं होने से आम जनता परेशान है। सपा नेता ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शन में कई सपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

झांसी-कानपुर हाईवे पर अनियंत्रित बस पलटी यात्रियों में मची चीख-पुकार

एजेंसी, उरई । झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा एक होटल के पास हुआ। बस गोरखपुर से ग्वालियर जा रही थी। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। दुर्घटना में दो यात्री घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि अन्य यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उरई कोतवाल आनंद सिंह के अनुसार, जीके ट्रेवल्स की बस (एमपी 44 जेई 4999) के चालक योगेश ने अचानक ब्रेक लगाए, लेकिन ब्रेक जाम होने के कारण बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाकर हाईवे पर यातायात व्यवस्था बहाल कराई गई। घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह ब्रेक जाम होना बताई जा रही है।

भारी बारिश से यूपी बेहाल, 20 शहरों में जलभराव और दो जिलों में स्कूल बंद

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून की तेज बारिश ने कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश के कारण 20 शहरों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात के बीच मगरमच्छ भी सड़कों पर दिखाई दिए। घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान खराब हो गया, वहीं कई जगह घरेलू वस्तुएं पानी में तैरती नजर आईं। हालात को देखते हुए दो जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बीते तीन दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत की सूचना है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों की टीमें तैनात हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

गौकशी करने पहुंचे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, दो आरोपितों को लगी गोली

एजेंसी, बरेली

बरेली। जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौकशी के प्रयास को विफल करते हुए मुठभेड़ के दौरान दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपितों के पैर में गोली लगी। घायल सिपाही और आरोपितों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोवध निवारण अधिनियम के एक मामले में वांछित दो आरोपी तजुवा-मिलक करारा खड़ंजा मार्ग के पास एक खेत में गौवंशीय पशु को काटने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कुँवर बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपितों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से कांस्टेबल लक्की के बाएं हाथ में चोट आई। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपित घायल हो गए और उन्हें मौके से पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान धौराटांडा निवासी दानिश (27) और फईम (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से दो अवैध तमंचे, कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। मौके से एक जीवित बैल भी मिला, जिसे रस्सियों से बांधा गया था। पुलिस ने उसे सुरक्षित मुक्त कराया। इसके अलावा घटनास्थल से छुरियां, बांका, दांव, लकड़ी का गुटका और रस्सियां भी बरामद की गईं। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस फरार अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है।

योगी कैबिनेट की मंजूरी, 50 हजार मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का मिलेगा लाभ

योगी सरकार का शिक्षा पर फोकस, छात्राओं को सुविधाएं और संस्थानों को मिलेगा आर्थिक सहयोग

एजेंसी, लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू किए जाने के प्रस्ताव के साथ-साथ उच्च शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें प्रदेश की करीब 50 हजार छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ देने का निर्णय प्रमुख है।

कैबिनेट बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित तीन प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। पहला प्रस्ताव रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से जुड़ा है। इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करना और उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच को आसान बनाना है। योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य, निजी और संबद्ध विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं में से शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को लाभ दिया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से छात्राओं को स्कूटी के साथ पंजीकरण शुल्क, वाहन बीमा, आईएसआई मार्क हेलमेट, आवश्यक एक्सेसरीज और पांच लीटर पेट्रोल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूटी पेट्रोल चालित होंगी और इनकी खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा दिव्यांगजन, निराश्रित परिवारों और शहीद परिवारों की बेटियों को मेरिट की बाध्यता के बिना योजना का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट ने भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए शोध पीठों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सिफारिशों के अनुरूप इस पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। योजना के तहत विश्वविद्यालयों को दो करोड़ रुपये तक और महाविद्यालयों को एक करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी जाएगी और इसके ब्याज से शोध पीठों का संचालन किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, गणित, खगोल शास्त्र और व्याकरण जैसी भारतीय ज्ञान परंपराओं को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। 50 वर्ष से अधिक पुराने और पांच हजार से अधिक विद्यार्थियों वाले प्राचीन महाविद्यालयों को भी इस योजना में सहायता दी जाएगी। बैठक में वाराणसी स्थित बसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट फोर्ट में नए महिला छात्रावास के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस संगठक महाविद्यालय में वर्तमान में केवल 220 छात्राओं के लिए छात्रावास उपलब्ध है। नए छात्रावास के निर्माण पर 248.30 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 112 छात्राओं के रहने की सुविधा होगी।

बीएचयू में 'पूरब के रंग' विषयक कार्यशाला में विशिष्ट गायन शैली का व्यावहारिक प्रशिक्षण

एजेंसी, वाराणसी

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संगीत एवं मंच कला संकाय के गायन विभाग द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय कार्यशाला 'पूरब के रंग' के दूसरे दिन मंगलवार को विद्यार्थियों को पूरब अंग गायकी की विशिष्ट शैली का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में छात्र छात्राओं ने शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत की बारीकियों को समझा।

बीएचयू में गायन परंपरा को आगे बढ़ाने की पहल

कार्यशाला की प्रशिक्षक एवं बीएचयू महिला महाविद्यालय की आचार्या प्रो. ऋचा कुमार ने प्रतिभागियों को पूरब अंग गायकी की शैलीगत विशेषताओं, बोल-बनाव, भावाभिव्यक्ति और ठुमरी गायन की प्रस्तुति के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने स्वयं गायन का प्रदर्शन कर विद्यार्थियों को इस शैली की बारीकियों का अभ्यास भी कराया। संगीत एवं मंच कला संकाय की अधिष्ठाता प्रो. संगीता पंडित, आयोजन सचिव डॉ. मधुमिता भट्टाचार्य और डॉ. श्यामा कुमारी ने बताया कि कार्यशाला का आयोजन तीन दिनों के लिए किया जा रहा है। इसमें 'पूरब के रंग' विषय के तहत इस विशिष्ट गायन परंपरा, उसकी विशेषताओं और व्यावहारिक पक्षों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रो. ऋचा कुमार शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका हैं। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को पूरब अंग गायकी की परंपरा को करीब से सीखने का अवसर मिल रहा है। कार्यशाला में बीपीए, एमपीए और पीएचडी के विद्यार्थियों के अलावा बीएचयू महिला महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया।

कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों ने पूरब अंग गायकी की परंपरा, ठुमरी के भाव पक्ष और प्रस्तुति शैली को समझते हुए अपनी संगीत प्रतिभा को निखारा। विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसी कार्यशालाएं शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए उत्साहपूर्वक भागीदारी की।

गंगा नदी में नहाते समय किशोरी की डूबकर मौत

एजेंसी, वाराणसी

मीरघाट पर गंगा स्नान के दौरान किशोरी डूबी बचाव अभियान के बाद भी नहीं बच सकी जान

दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के मीरघाट पर मंगलवार सुबह गंगा स्नान के दौरान 14 वर्षीय किशोरी की डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान बिहार के छपरा जिले के बनसोई मुशरख गांव निवासी सिमरन ठाकुर के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वाराणसी आई थी।

जानकारी के अनुसार, सुबह परिवार के लोग मीरघाट पर गंगा स्नान कर रहे थे। इसी दौरान सिमरन का पैर अचानक फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। परिजनों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह पानी में डूब गई। सूचना मिलते ही दशाश्वमेध पुलिस, जल पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद किशोरी को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार में घटना के बाद मातम छा गया।

सोशल मीडिया दोस्ती में धोखा, युवती का वीडियो वायरल करने का आरोप

एजेंसी, नोएडा। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद एक युवती ने युवक पर निजी वीडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल करने का आरोप लगाया है। मामले में थाना सेक्टर-24 पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, प्रयागराज निवासी युवती वर्तमान में नोएडा के सेक्टर-22 में रहती है। युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2025 में उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से पंकज राजपूत नामक युवक से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ गईं।
युवती का आरोप है कि एक दिन वीडियो कॉल के दौरान युवक ने उसकी जानकारी के बिना आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आरोपी उसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर कथित रूप से वीडियो प्रसारित कर दिया।

जनपद संभल के शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को

एजेंसी, संभल

उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर मंगलवार को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 25 अगस्त 2026 निर्धारित की है।

सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने और वहां से स्थगन आदेश प्रभावी रहने के कारण अदालत में कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी। यह याचिका आठ पक्षकारों की ओर से 19 नवंबर 2024 को दायर की गई थी, जिसमें शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 26 मई को हुई थी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के चलते सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यस्थता का प्रयास सफल नहीं हुआ।

वहीं मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने बताया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण अगली सुनवाई 25 अगस्त तय की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी।

ऑपरेशन कवच के तहत परिवहन विभाग ने 9 वाहन किए सीज, 10 का चालान

एजेंसी, उरई

जालौन में अभियान के दौरान नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करते अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में परिवहन विभाग ने मंगलवार को ऑपरेशन कवच अभियान के तहत अनाधिकृत और नियमों का उल्लंघन कर संचालित वाहनों के खिलाफ सघन कार्रवाई की। माधौगढ़ क्षेत्र में पीटीओ आनंद राय के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान दो स्लीपर बसों सहित कुल नौ वाहनों को सीज किया गया, जबकि बिना वैध परमिट और आवश्यक दस्तावेजों के संचालित दस अन्य वाहनों के चालान काटे गए।

परिवहन विभाग के अनुसार अभियान का उद्देश्य अवैध रूप से संचालित वाहनों पर अंकुश लगाना, सड़क सुरक्षा को मजबूत करना तथा परिवहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने वाहनों के परमिट, कर भुगतान, फिटनेस और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की। पीटीओ आनंद राय ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने सभी वाहन स्वामियों से वैध दस्तावेजों के साथ ही वाहन संचालन करने की अपील की, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति जागरूक भी किया। अधिकारियों ने कहा कि बिना वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा और कर अदायगी के वाहन चलाना कानूनन अपराध है। विभाग भविष्य में भी विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।

ट्रक और कार की भिड़ंत में महिला की मौत और सात लोग घायल

एजेंसी, हाथरस। हाथरस रोड पर मंगलवार तड़के सलेमपुर बंबा के पास ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो वर्षीय बच्ची समेत छह लोग घायल हो गए। घायलों में ट्रक सवार दो लोग भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, स्विफ्ट डिजायर कार में सवार लोग झांसी में आयोजित गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सादाबाद से हाथरस की ओर लौट रहे थे। जैसे ही कार सलेमपुर बंबा के पास पहुंची, चालक को नींद की झपकी आ गई। इससे कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई।

हादसे में रानी पत्नी चंद्रभान निवासी किला मेंवई, खुर्जा बुलंदशहर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अर्पित चौधरी, प्रवेश, कुसुम देवी, कल्पना कुमारी और दो वर्षीय अर्पिता सहित अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया। ट्रक सवार सुहान और रिहान को भी चोटें आईं, जिनका उपचार कराया गया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में चालक को नींद आने की बात सामने आई है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

नोएडा में ऑनलाइन शराब तस्करी का खुलासा, 27 बोतलों के साथ दो गिरफ्तार

एजेंसी, नोएडा

नोएडा जिला आबकारी विभाग ने अवैध रूप से शराब की होम डिलीवरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नोएडा की सोसाइटियों में तस्करी की अंग्रेजी शराब पहुंचाते थे। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इनके कब्जे से 27 बोतल विदेशी मदिरा बरामद की गई है।

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आबकारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह और थाना सेक्टर-113 पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार रात कार्रवाई करते हुए अनिल पुत्र प्रेमपाल सिंह और कमल कुमार को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से विदेशी शराब की 27 बोतलें मिलीं। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे सेक्टर-78 और आसपास की विभिन्न सोसाइटियों में ऑनलाइन माध्यम से अवैध शराब की सप्लाई करते थे। बरामद शराब की बोतलों पर उत्तर प्रदेश का क्यूआर कोड नहीं था। अधिकारियों के अनुसार, आरोपित दूसरे राज्यों से सस्ती कीमत पर शराब मंगाकर उत्तर प्रदेश में अधिक दामों पर बेचते थे। आबकारी विभाग ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। आबकारी विभाग की कार्रवाई से ऑनलाइन शराब तस्करी नेटवर्क में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब सप्लाई करने वाले अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

विकास 425.50 करोड़ रुपए के बजट से खरीदी जाएंगी 250 यूपी रोडवेज इलेक्ट्रिक बसें

योगी कैबिनेट का फैसला, यूपी रोडवेज में शामिल होंगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसें

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इन बसों की खरीद पर कुल 425.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जबकि 25.50 करोड़ रुपये का खर्च उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नई बसों में 100 इलेक्ट्रिक बसें 12 मीटर लंबी, 3म2 श्रेणी की होंगी, जिनमें करीब 50 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं 150 बसें 12 मीटर लंबी 2म2 श्रेणी की होंगी, जिनमें 41 सीटों की सुविधा उपलब्ध होगी।

इन बसों के संचालन से प्रदेश के प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों में यातायात सुविधा को मजबूती मिलेगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में प्रदेश के निर्माताओं को प्राथमिकता देने का निर्णय भी लिया है। इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के पर्यावरणीय मानकों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक नवंबर 2026 से दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस 6 श्रेणी के वाहनों को प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश हैं। ऐसे में यूपी रोडवेज के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से एनसीआर क्षेत्र में परिवहन संचालन को सुचारू रखने में मदद मिलेगी। योगी सरकार का दावा है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से डीजल वाहनों पर निर्भरता कम होगी और वायु प्रदूषण में कमी आएगी।

इसके अलावा यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ यह कदम प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगा। कैबिनेट के इस फैसले से परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। बसों के संचालन के लिए चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसके अलावा बस अड्डों, रखरखाव सेवाओं और यात्रियों से जुड़े अन्य व्यवसायों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही कैबिनेट ने वाराणसी में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत 500 क्षमता वाले आधुनिक महिला छात्रावास के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 6000 वर्गमीटर सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

तीन माह से वेतन नहीं मिला, मेडिकल कॉलेज के 300 आउटसोर्स कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार

एजेंसी, देवरिया

प्रदर्शन के कारण मरीजों को झेलनी पड़ी परेशानी

वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे स्टाफ नर्स और सफाई कर्मचारी

महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को वेतन भुगतान की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग पर कार्यरत स्टाफ नर्सों और सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। करीब तीन सौ कर्मचारियों ने सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक हड़ताल की, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। ओपीडी, वार्ड और इमरजेंसी में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। कई वार्डों में मरीजों को समय पर दवाएं और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में दिक्कत आई। वहीं सफाई कर्मचारियों के काम बंद करने से अस्पताल परिसर और वार्डों में सफाई व्यवस्था भी प्रभावित रही। ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिलीं, जबकि इमरजेंसी सेवाओं पर भी स्टाफ की कमी का असर पड़ा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिला है।

वेतन भुगतान को लेकर कई बार आउटसोर्सिंग एजेंसी और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कर्मचारियों का कहना था कि लगातार वेतन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हड़ताल के बाद कर्मचारी मेडिकल कॉलेज परिसर से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लंबित वेतन का जल्द भुगतान कराने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो वे दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए कि कर्मचारियों का बकाया वेतन दो दिन के भीतर भुगतान कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी जल्द वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने का भरोसा दिलाया है।

तकनीकी शिक्षा को नई उड़ान 60 आईटीआई का होगा उन्नयन

भारतेन्दु संवाददाता,चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने राज्य में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री स्किल एंड इंप्लायबिलिटी ट्रांसफार्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना के तहत प्रदेश के 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के लिए 2,892 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

योजना के अंतर्गत राज्य के 12 हब-एंड-स्पोक क्लस्टरों में आने वाले 60 आईटीआई को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इनमें आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल कक्षाएं, उन्नत मशीनें, स्मार्ट प्रशिक्षण उपकरण और उद्योग आधारित पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों को नई तकनीकों और आधुनिक औद्योगिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

पहले चरण में कुरुक्षेत्र, पलवल सहित सात क्लस्टरों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का मानना है कि इस पहल से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उद्योगों को प्रशिक्षित एवं दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध होगा। इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों के बीच समन्वय भी मजबूत किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर बढ़ सकें। सरकार के अनुसार, पीएम-सेतु योजना प्रदेश में कौशल विकास को नई गति देगी और हरियाणा को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पुरातात्विक खुदाई में हरियाणा सबसे आगे, राखीगढ़ी अग्रोहा पर एएसआई ने खर्च किए 3.42 करोड़ रुपए

देश की 16 उत्खनन परियोजनाओं में हरियाणा की दोनों साइटों पर हुआ सबसे ज्यादा खर्च

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा की प्राचीन सभ्यता और ऐतिहासिक धरोहरों की वैज्ञानिक जांच को लेकर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान बढ़ रहा है। देशभर में चल रही पुरातात्विक खुदाई परियोजनाओं में हरियाणा की दो महत्वपूर्ण साइटें राखीगढ़ी और अग्रोहा खर्च के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार, इन दोनों स्थलों पर अब तक कुल 3.42 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो देश की अन्य प्रमुख उत्खनन परियोजनाओं की तुलना में सबसे अधिक है।

खर्च के आधार पर देखा जाए तो राखीगढ़ी देश की सभी 16 चल रही पुरातात्विक उत्खनन परियोजनाओं में पहले स्थान पर है, जबकि हरियाणा की ही अग्रोहा साइट दूसरे स्थान पर है। इसके बाद गुजरात की प्रसिद्ध द्वारका साइट पर एक करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की गई है।

राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में शामिल किया जाता है। यहां हुई खुदाई से हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, रहन-सहन, व्यापार और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रमाण सामने आए हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार, राखीगढ़ी की खोज से भारतीय इतिहास के कई अनछुए पहलुओं को समझने में मदद मिली है।

वहीं, अग्रोहा भी हरियाणा का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जहां प्राचीन काल से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई हैं। यहां की खुदाई के माध्यम से पुरानी बस्तियों, संरचनाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 के बीच देश में कई पुरातात्विक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। लोकसभा सांसद टीआर बालू द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि वर्ष 2021 22 में 24 परियोजनाओं को अनुमति दी गई थी।

इसके बाद 2022-23 में 31, वर्ष 2023 में 19, वर्ष 2024 में 22 और वर्ष 2025 में 25 पुरातात्विक परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इन वर्षों में देश के 16 प्रमुख स्थलों पर चल रही खुदाई परियोजनाओं पर लगभग 6.8 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इनमें हरियाणा की राखीगढ़ी और अग्रोहा परियोजनाओं का हिस्सा सबसे अधिक है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि इन स्थलों की खुदाई से भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इन खोजों से भारतीय इतिहास को नई दिशा मिलेगी और प्राचीन सभ्यताओं के विकास क्रम को समझने में सहायता मिलेगी।

चार बच्चों के पिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले के जाखल मंडी की नायक बस्ती में एक व्यक्ति द्वारा फंदा लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय करमवीर सिंह के रूप में हुई है। वह जाखल रेलवे स्टेशन स्थित एक फूड स्टॉल पर हेल्पर के रूप में कार्यरत थे और अपने पीछे पत्नी, तीन बेटियों तथा एक बेटे सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार, करमवीर सिंह का परिवार पिछले करीब दो वर्षों से नई बस्ती में रह रहा था। इससे पहले वे जिस पुराने मकान में रहते थे, वह लगातार बारिश और समय के साथ काफी जर्जर हो चुका था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को करमवीर सिंह किसी समय अपने पुराने मकान में पहुंचे। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों और आसपास के लोगों को संदेह हुआ। जब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो वह फंदे से लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर जाखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए टोहाना के नागरिक अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। परिजनों ने बताया कि करमवीर सिंह की शादी करीब 18 वर्ष पहले जींद निवासी अमरजीत कौर से हुई थी। परिवार के अनुसार, वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थे। हालांकि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। घटना से पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है तथा पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जाखल थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मृतक के भाई शिवनाथ के बयानों के आधार पर पुलिस ने इत्तेफाकिया कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी प्रकार की संदिग्ध परिस्थिति सामने नहीं आई है, फिर भी जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने आएगी।

न्यूज ब्रीफ

चार शव निकालने कुएं में उतरे एसआई जहरीली गैस की चपेट में आए

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर। झज्जर जिले में जहरीली गैस से भरे कुएं में चार ग्रामीणों की मौत के बाद चलाए गए राहत एवं बचाव अभियान में एक पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) ने साहस और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की। जब जहरीली गैस के कारण कोई भी व्यक्ति कुएं में उतरने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, तब एसआई सुरक्षा उपकरणों के साथ नीचे उतरे और बचाव दल की मदद से चारों ग्रामीणों के शव बाहर निकलवाए। इस दौरान वह स्वयं भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बिना सुरक्षा इंतजामों के बंद कुओं या ऐसे स्थानों में प्रवेश न करें, जहां जहरीली गैस होने की आशंका हो।

एडवोकेट के घर करोड़ों की चोरी, दो किलो सोना और नकदी ले उड़े चोर

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-16 स्थित एक एडवोकेट के घर में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए करीब दो किलो सोने के आभूषण और 20 लाख रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना उस समय हुई, जब परिवार 20 जुलाई को नोएडा में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने गया हुआ था। सूना मकान देखकर बदमाश चारदीवारी फांदकर अंदर घुसे और एसी की खिड़की का शीशा तोड़कर प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने कमरों के ताले और अलमारी तोड़कर कीमती सामान समेट लिया। चोरी हुए सोने की मौजूदा बाजार कीमत करीब 2.75 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वारदात के बाद चोर गहनों के खाली डिब्बे कमरे में फेंककर फरार हो गए। घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही पुलिस चौकी होने के बावजूद चोरी होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आंगनबाड़ी केंद्र में लापरवाही पर डीसी सख्त नोटिस जारी करने के निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल । उपायुक्त अपराजिता ने मंगलवार सुबह बलराज नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने राशन, हाजिरी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, दवाइयों, खिलौनों और अन्य सुविधाओं की जांच की। रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला कार्यक्रम अधिकारी सपना को नियमित फील्ड विजिट कर सभी केंद्रों की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान आयरन एवं फोलिक एसिड सिरप की एक्सपायरी डेट भी जांची गई तथा टीकाकरण की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए। बच्चों की लंबाई और वजन मापने वाली मशीन खराब मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और सभी खराब मशीनों को तत्काल ठीक कराने या आवश्यकता होने पर नई मशीनें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

भाखड़ा में छलांग लगाने वाले युवक का शव तीसरे दिन बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले के गांव जांडली खुर्द निवासी 65 वर्षीय बलवीर सिंह का शव भाखड़ा नहर से घटना के करीब 48 घंटे बाद बरामद कर लिया गया। शनिवार शाम वह अचानक लापता हो गए थे और गोरखपुर गांव के पास नहर में छलांग लगा दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण वह लापता हो गए। घटना के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से कई किलोमीटर तक सर्च अभियान चलाया तथा शव रोकने के लिए पुल पर लोहे का जाल भी लगाया। सोमवार देर रात शव बरामद होने के बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया गया कि बलवीर सिंह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे और उनका उपचार चल रहा था।

सोहना-तावडू मार्ग पर टूटी सेफ्टी दीवारें बढ़ा रहीं हादसों का खतरा

भारतेन्दु संवाददाता , सोहना

सोहना-तावडू पहाड़ी मार्ग पर जगह-जगह टूटी सेफ्टी दीवारें वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। घाटी की ओर बनी इन सुरक्षा दीवारों के क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद लोकनिर्माण विभाग ने अब तक मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

पिछले एक वर्ष के दौरान इस मार्ग पर कई सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई है, जबकि अनेक लोग घायल हुए हैं। ताऊ देवीलाल मोड़ और कॉम्प्लेक्स मोड़ जैसे संवेदनशील स्थानों पर सेफ्टी दीवारें टूटी होने से वाहन अनियंत्रित होने पर सीधे गहरी खाई की ओर जा सकते हैं। विशेषकर रात के समय और बरसात के मौसम में यह मार्ग और अधिक जोखिमभरा हो जाता है। स्थानीय नागरिकों और नियमित रूप से इस मार्ग का उपयोग करने वाले वाहन चालकों ने विभाग से जल्द से जल्द टूटी दीवारों की मरम्मत कराने की मांग की है।

उनका कहना है कि समय रहते सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो भविष्य में बड़े हादसे हो सकते हैं। क्षेत्र के विधायक ने बताया कि सोहना-तावडू मार्ग के विस्तार और सुधार की मंजूरी मिल चुकी है। परियोजना के तहत सड़क को अधिक सुरक्षित बनाने के साथ आवश्यक स्थानों पर नई सेफ्टी दीवारें और अन्य सुरक्षा सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हालांकि लोगों का कहना है कि परियोजना पूरी होने में समय लगेगा, इसलिए तब तक क्षतिग्रस्त दीवारों की तत्काल मरम्मत कराना जरूरी है।

दिल्ली कूच से पहले हरियाणा की सीमाएं सील कुंडली बॉर्डर पर चार किलोमीटर लंबा जाम लगा

भारतेन्दु संवाददाता , गुरुग्राम

अमेरिका-भारत मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड डील) के विरोध में किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद घेराव कार्यक्रम को देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर कड़ी कर दी गई है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रमुख बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कई जिलों में किसान नेताओं और सीजेपी समर्थकों को एहतियातन नजरबंद किया गया है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

प्रदेश के रोहतक, सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, झज्जर, पानीपत, करनाल समेत करीब 12 जिलों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर वज्र वाहन, दंगा नियंत्रण उपकरण और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं। बॉर्डरों पर हर वाहन की गहन जांच के बाद ही दिल्ली की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है।

सोनीपत के कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर सुरक्षा जांच के कारण करीब चार किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस लगातार यातायात को सामान्य बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जांच प्रक्रिया के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी बनी हुई है। वहीं, अंबाला के शंभू बॉर्डर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

कैथल होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, संचालक पर मामला दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल। कैथल में एक होटल में कथित देह व्यापार का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि करनाल और नरवाना से युवतियों को बुलाकर ग्राहकों के सामने सौदा तय कराया जाता था और इसके बदले पैसे लेकर अनैतिक गतिविधियां संचालित की जाती थीं। सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल में छापा मारा, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ लोगों को पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच के बाद होटल संचालक और कैथल निवासी डिंपल के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं।

हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के 20 प्रतिशत आरक्षण का श्रेणीवार विभाजन कर निर्देश किए जारी

भारतेन्दु संवाददाता , चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को मिलने वाले 20 प्रतिशत आरक्षण का श्रेणीवार वर्गीकरण करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, इस आरक्षण में 11 प्रतिशत सीटें आरक्षित वर्गों के पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित होंगी, जबकि नौ प्रतिशत सीटें अनारक्षित श्रेणी के पूर्व अग्निवीरों को मिलेंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से आरक्षण व्यवस्था अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनेगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि यह संशोधन 20 अगस्त 2025 को जारी पूर्व आदेश में आंशिक बदलाव के रूप में किया गया है। नई व्यवस्था के तहत सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ निर्धारित श्रेणियों के अनुसार मिलेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था वन रक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड तथा अन्य पात्र पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगी। संबंधित भर्ती एजेंसियों और विभागों को नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप चयन प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। भर्ती विज्ञापनों और चयन प्रक्रिया में भी इस वर्गीकरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

राज्य सरकार का कहना है कि पूर्व अग्निवीरों के अनुभव और अनुशासन का लाभ प्रशासनिक सेवाओं में मिलेगा। इसी उद्देश्य से उन्हें सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता देने के लिए आरक्षण नीति लागू की गई है। अब श्रेणीवार विभाजन तय होने से आरक्षण का लाभ पात्र अभ्यर्थियों तक अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पहुंचेगा। सरकार ने सभी विभागों से निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध, निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप पूरी की जा सके।

नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद सभी संबंधित विभागों और भर्ती एजेंसियों को चयन प्रक्रिया में निर्धारित आरक्षण अनुपात का पालन करना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्रता, आयु सीमा और अन्य भर्ती शर्तें संबंधित सेवा नियमों के अनुसार ही लागू रहेंगी। पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप मिलेगा। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से पूर्व सैनिकों के पुनर्वास को मजबूती मिलेगी और उन्हें सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विवादरहित बनने की उम्मीद है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति मिल सकेगी।

दिल्ली से चुराई क्रेटा करनाल में बरामद आरोपी दबोचा

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल। करनाल पुलिस ने चोरी की एक क्रेटा कार समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया है। आरोपी दिल्ली से चोरी की गई क्रेटा पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसे बेचने के लिए करनाल पहुंचा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति चोरी की कार का सौदा करने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि बरामद क्रेटा दिल्ली क्षेत्र से चोरी की गई थी। जांच में कार पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी पाई गई, जिसे वाहन की पहचान छिपाने के लिए लगाया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है ताकि वाहन चोरी गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी की अन्य गाड़ियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। बरामद कार को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मूसलाधार बारिश से हरियाणा बेहाल गुरुग्राम-फरीदाबाद में जनजीवन प्रभावित

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मंगलवार सुबह गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, भिवानी और महेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। लगातार हुई वर्षा से कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है।

सबसे अधिक असर गुरुग्राम में देखने को मिला, जहां सेक्टर-10 से हीरो होंडा चौक तक लंबा जाम लग गया। दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले वाहन भी करीब पांच से छह किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए। राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर वाहनों की लंबी कतारें एयरपोर्ट टनल के अंदर तक पहुंच गईं। कार्यालय जाने वाले लोगों और यात्रियों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। फरीदाबाद में भी भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए। जलभराव को देखते हुए ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास और एनएचपीसी अंडरपास को एहतियातन बंद कर दिया गया। कई स्थानों पर हाईवे पर पानी भर जाने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी, बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में भी जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, कल तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। आज बारिश का सबसे अधिक प्रभाव रहने की संभावना है, जबकि कल को भी अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। 24 से 26 जुलाई के बीच वर्षा की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है।इस बीच जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने और आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखा गया है।

ट्रेड डील विरोध पर रोहतक में किसान नेता नजरबंद, दिल्ली जाने से पहले हुई कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता , रोहतक

दिल्ली के किसान घाट पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले रोहतक में पुलिस ने कई किसान नेताओं को उनके घरों पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। मंगलवार सुबह पुलिस टीम विभिन्न गांवों में पहुंची और आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे नेताओं को घरों से बाहर निकलने से रोक दिया। किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें नजरबंद किए जाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया।

जानकारी के अनुसार, किसान मजदूर संगठन हरियाणा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के आह्वान पर किसान दिल्ली के किसान घाट पर प्रदर्शन के लिए रवाना होने वाले थे। प्रदर्शन का उद्देश्य अमेरिका-भारत फ्री ट्रेड डील, स्मार्ट मीटर योजना और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों का विरोध दर्ज कराना था। पुलिस ने एहतियातन कई स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी और संभावित प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी। गांव धामड़ में किसान नेता रणधीर को भी उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट किया गया।

इसके अलावा जिले के अन्य किसान नेताओं के घरों के बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि कोई भी दिल्ली के लिए रवाना न हो सके। किसानों का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। किसान-मजदूर संगठन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष उमेद सिंह ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) की ओर से देशभर के किसानों को दिल्ली के किसान घाट पर एकत्र होने का आह्वान किया गया था। उनका आरोप है कि हरियाणा के विभिन्न जिलों में पुलिस किसानों को रास्ते में रोक रही है और कई नेताओं को घरों में ही नजरबंद कर दिया गया है।

दूसरी ओर, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दिल्ली की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। किसान संगठनों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूरे घटनाक्रम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

बसई में 149 करोड़ से बनेगा नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बढ़ेगी पेयजल आपूर्ति

बसई डब्ल्यूटीपी विस्तार से जलशोधन क्षमता 370 एमएलडी और भंडारण क्षमता 600 मिलियन लीटर बढ़ेगी

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम

साइबर सिटी गुरुग्राम की लगातार बढ़ती आबादी और भविष्य में बढ़ने वाली पेयजल मांग को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने बसई स्थित जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में 149 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। परियोजना के तहत बसई जल शोधन संयंत्र परिसर में 100 एमएलडी क्षमता की नई फिल्ट्रेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके अलावा 300-300 मिलियन लीटर क्षमता के दो अवसादन-सह भंडारण टैंक भी बनाए जाएंगे। इन संरचनाओं के निर्माण से न केवल जल शोधन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि बड़ी मात्रा में पानी का सुरक्षित भंडारण भी संभव हो सकेगा। इससे गर्मी के मौसम या आपूर्ति बाधित होने जैसी परिस्थितियों में भी शहर को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

वर्तमान में बसई जलघर की जल शोधन क्षमता 270 एमएलडी है। नई इकाई के निर्माण के बाद यह बढ़कर 370 एमएलडी हो जाएगी। वहीं जल भंडारण क्षमता में 600 मिलियन लीटर की बढ़ोतरी होगी। अधिकारियों का मानना है कि इस विस्तार से गुरुग्राम के कई पुराने और नए विकसित हो रहे क्षेत्रों में जल आपूर्ति अधिक व्यवस्थित और सुचारु हो सकेगी। विशेष रूप से तेजी से विकसित हो रहे आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जीएमडीए के अधिकारियों के अनुसार नई फिल्ट्रेशन यूनिट के निर्माण के लिए बसई में लगभग 77 एकड़ भूमि पहले से उपलब्ध है, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में भूमि अधिग्रहण जैसी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि नागरिकों को शीघ्र इसका लाभ मिल सके। गुरुग्राम में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जनसंख्या और शहरी विस्तार तेजी से बढ़ा है। इसके कारण पेयजल की मांग में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।

गर्मियों के दौरान कई इलाकों में पानी की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में बसई जल शोधन संयंत्र का विस्तार शहर की दीर्घकालिक जल प्रबंधन योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इससे भविष्य में बढ़ती आबादी की जरूरतों के अनुरूप पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद जल आपूर्ति नेटवर्क की कार्यक्षमता भी बेहतर होगी और विभिन्न क्षेत्रों तक पानी की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार का उद्देश्य शहर के नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

नई परियोजना के लागू होने से जल संकट की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। साथ ही, आधुनिक जल शोधन व्यवस्था और बढ़ी हुई भंडारण क्षमता गुरुग्राम की पेयजल व्यवस्था को अधिक मजबूत, विश्वसनीय और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परियोजना पूरी होने के बाद शहर के नए विकसित हो रहे क्षेत्रों के साथ पुराने इलाकों में भी पेयजल आपूर्ति अधिक नियमित होगी। इससे जल संकट में कमी आएगी और भविष्य की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

संत प्रेमानंद महाराज पर विवादित टिप्पणी से बढ़ा तनाव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पूज्य संतों पर विवादित बयान से उपजा आक्रोश, पार्टी प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग

एजेंसी, नई दिल्ली

कंबाइंड जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया का एक नया और बेहद विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह प्रसिद्ध कथावाचक और संत प्रेमानंद महाराज तथा मनुवादियों के खिलाफ बेहद तल्ख और आक्रामक टिप्पणी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक और धार्मिक गलियारों में भारी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में विजेता दहिया का रुख बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा है। वह मनुवादियों को सीधे तौर पर 'आतंकवादी' करार दे रहे हैं और अपनी बात रखते हुए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते दिख रहे हैं।

वीडियो में उन्होंने कहा कि 'चाहे तो तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं हूँ।' उनका यह आक्रामक अंदाज़ और कड़े शब्दों का प्रयोग अब विवाद का मुख्य कारण बन गया है। जानकारी के अनुसार, विजेता दहिया ने इस वीडियो को खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया था। वीडियो के अपलोड होते ही यह तेज़ी से शेयर होने लगा और देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया। संत प्रेमानंद महाराज के लाखों अनुयायियों और धार्मिक संगठनों ने इस वीडियो पर गहरा दुख और कड़ा विरोध व्यक्त किया है।

लोगों का कहना है कि किसी भी पूज्य संत या विचारधारा के खिलाफ इस तरह की अभद्र और हिंसक भाषा का प्रयोग पूरी तरह से अनुचित और निंदनीय है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहस छिड़ गई है। प्रेमानंद महाराज के समर्थकों ने

विजेता दहिया के इस कृत्य को सनातन संस्कृति और धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचाने वाला बताया है। कई उपयोगकर्ताओं ने शासन और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि समाज में विद्वेष और अशांति फैलाने की नीयत से दिए गए इस बयान पर विजेता दहिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी तरफ, कंबाइंड जनता पार्टी की ओर से इस विवाद पर आधिकारिक रुख अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने इस बयान से दूरी बनाई है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मर्यादा की सीमाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर नज़र रखी जा रही है।

गाजियाबाद मे हापुड़ चुंगी चौराहे पर 540 दिनों में बनकर तैयार होगा फ्लाईओवर

एजेंसी ,नई दिल्ली

गाजियाबाद शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए हापुड़ चुंगी चौराहे पर जल्द ही फ्लाईओवर का निर्माण शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक हापुड़ चुंगी पर लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इस फ्लाईओवर के निर्माण की तैयारी तेज कर दी है। प्रस्तावित फ्लाईओवर छह लेन का होगा, जिससे बड़ी संख्या में वाहनों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसका निर्माण अगले कुछ महीनों में शुरू होने की संभावना है।

फ्लाईओवर का रूट हापुड़ रोड पर यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इसके बनने के बाद मुख्य मार्ग से गुजरने वाले वाहन बिना रुकावट

गाजियाबाद में हापुड़ चुंगी पर जल्द बनेगा फ्लाईओवर

आगे बढ़ सकेंगे, जबकि स्थानीय यातायात के लिए सर्विस और स्लिप रोड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह परियोजना करीब 102 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की जाएगी और इसे लगभग 540 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

अधिकारियों के अनुसार, फ्लाईओवर बनने के बाद हापुड़ चुंगी, आसपास के प्रमुख मार्गों और शहर के अन्य हिस्सों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। जीडीए का मानना है कि यह फ्लाईओवर गाजियाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अहम भूमिका निभाएगा और आने वाले वर्षों में बढ़ते यातायात दबाव को संभालने में मदद करेगा। फ्लाईओवर बनने से हापुड़ चुंगी पर जाम कम होगा और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।

भिवानी में अग्रवाल समाज की पहल शादी में दिखावे और खर्च पर लगाम

एजेंसी ,नई दिल्ली

भिवानी में अग्रवाल समाज ने विवाह समारोहों में बढ़ते खर्च और सामाजिक कुरीतियों को कम करने के लिए तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अग्रसेन विवाह प्रकोष्ठ के तत्वावधान में कमला भवन धर्मशाला में आयोजित बैठक में समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में अग्रसेन ट्रस्ट और श्रीअग्रवाल सभा के पदाधिकारियों सहित समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस दौरान तय किया गया कि बेटी की शादी में मिठाई के डिब्बे देने और लेने की परंपरा पूरी तरह बंद की जाएगी। इसके अलावा लड़के की शादी में शगुन लेने और देने की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया।

समाज ने तिलक, पूजन और अन्य वैवाहिक रस्मों में होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करने के लिए मिलनी की राशि अधिकतम 100 रुपये निर्धारित की है। उपस्थित लोगों ने इन सभी प्रस्तावों को हाथ उठाकर और तालियों के साथ सर्वसम्मति से पारित किया। समाज के लोगों ने निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए घर-घर जाकर संकल्प पत्र भरवाने का भी फैसला लिया। समाज ने फैसलों को लागू करने के लिए संकल्प पत्र भरवाने का निर्णय लिया।

न्यूज ब्रीफ

भिवानी-मथुरा रूट पर यात्रियों को राहत रेलवे ने बढ़ाए तीन-तीन कोच

एजेंसी, नई दिल्ली यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने भिवानी-मथुरा और मथुरा-सवाई माधोपुर रूट पर चलने वाली दो जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी रूप से साधारण श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन नंबर 14725/14726 भिवानी-मथुरा-भिवानी में भिवानी से 24 जुलाई से 31 जुलाई तक और मथुरा से 25 जुलाई से 1 अगस्त तक तीन अतिरिक्त साधारण श्रेणी के डिब्बे लगाए जाएंगे। इसी तरह ट्रेन नंबर 54794/54793 मथुरा-सवाई माधोपुर-मथुरा में भी मथुरा से 24 जुलाई से 31 जुलाई तक और सवाई माधोपुर से 25 जुलाई से 1 अगस्त तक तीन साधारण श्रेणी के डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और सफर को आसान बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इसके अलावा सामाख्याली-गांधीधाम रेलखंड के बीच सामाख्याली, वोंध और भरूच स्टेशनों पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य भी किया जा रहा है।

गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में पहली बार शुरू हुआ एम-थियेटर, रंगमंच को मिलेगा नया मंच

एजेंसी, नई दिल्ली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एम-थिएटर की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को कला, संस्कृति और अभिनय के क्षेत्र में बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। विश्वविद्यालय में अब नाटक, मंचन और रचनात्मक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। एम-थिएटर के माध्यम से छात्रों को अभिनय, निर्देशन और रंगमंच से जुड़ी विभिन्न विधाओं को सीखने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह पहल विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नए परिसर में एक अत्याधुनिक थिएटर बनाने की भी तैयारी की जा रही है। इस थिएटर में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, नए परिसर में बनने वाला थिएटर छात्रों के साथ-साथ शहर के कलाकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इससे गुरुग्राम में रंगमंच और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

फरीदाबाद में बिना यूनिक नंबर प्लेट वाले ऑटो पर गिरेगी कार्रवाई की गाज

एजेंसी ,नई दिल्ली

फरीदाबाद में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। शहर की सड़कों पर 10 हजार से अधिक ऑटो ऐसे चल रहे हैं, जिन पर यूनिक पहचान नंबर प्लेट नहीं लगी है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऑटो चालकों और वाहनों की पहचान आसान बनाना था, लेकिन बड़ी संख्या में ऑटो इसके बिना ही संचालित हो रहे हैं। यूनिक नंबर प्लेट न होने से किसी घटना, शिकायत या अपराध की स्थिति में ऑटो और चालक की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर निगरानी के लिए यातायात पुलिस अब ऐसे ऑटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी ऑटो चालकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। बिना पहचान नंबर प्लेट वाले वाहनों की जांच की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की

जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य शहर में चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहनों की पहचान सुनिश्चित करना और यात्रियों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना है। ऑटो चालकों से भी अपील की जा रही है कि वे अपने वाहनों पर जरूरी पहचान प्लेट लगवाएं, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता आए और यात्रियों का भरोसा बढ़ सके।

रीदाबाद में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शहर में 10 हजार से अधिक ऑटो ऐसे चल रहे हैं, जिन पर यूनिक पहचान नंबर प्लेट नहीं लगी है। यह व्यवस्था ऑटो और चालकों की पहचान आसान बनाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन नियमों का पालन नहीं होने से निगरानी व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। यूनिक नंबर प्लेट न होने के कारण किसी दुर्घटना, शिकायत या आपराधिक घटना की स्थिति में वाहन और चालक की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। यातायात पुलिस अब ऐसे ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने की तैयारी में है।

प्रयागराज में अपराधियों पर शिकंजा गैंग लीडर समेत चार पर गैंगस्टर एक्ट

एजेंसी ,नई दिल्ली

प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। धूमनगंज पुलिस ने गैंग लीडर विनोद कुमार वर्मा और उसके तीन सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब इन सभी की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी कर रही है।पुलिस के अनुसार, शहर पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए यह कार्रवाई की गई है। गैंग लीडर विनोद कुमार वर्मा निवासी जयन्तीपुर साकेतनगर और उसके सहयोगी जितेंद्र कुमार, विक्रम सिंह तथा सोनू उर्फ राजू वर्मा निवासी जयन्तीपुर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपितों पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। अब गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क किया जाएगा।

प्रशासन और पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराध से जुड़े लोगों की आर्थिक कमर तोड़ना और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। पुलिस टीम आरोपितों की संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है। प्रशासन का उद्देश्य अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त कर अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा की रफ्तार बढ़ाएगा नया एलिवेटेड रोड, आईआईटी रुड़की बनाएगा डीपीआर

एजेंसी ,नई दिल्ली

नोएडा शहर में जल्द ही एक और नया एलिवेटेड रोड बनने की योजना है। नोएडा प्राधिकरण ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए डिजाइन और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की को सौंपी है। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की लंबाई 5 किलोमीटर से अधिक होगी और यह शहर के कई प्रमुख सेक्टरों को जोड़ेगा।

इस परियोजना का उद्देश्य नोएडा में बढ़ते यातायात दबाव को कम करना और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। एलिवेटेड रोड बनने के बाद प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण ने योजना के तकनीकी पहलुओं, ट्रैफिक जरूरतों और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आईआईटी रुड़की से अध्ययन कराने का फैसला लिया है। आईआईटी रुड़की विशेषज्ञों की टीम रोड के डिजाइन, निर्माण तकनीक और संभावित रूट का अध्ययन करेगी। डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना की लागत और निर्माण की समयसीमा तय की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण का मानना है कि यह एलिवेटेड रोड शहर के विकास में अहम भूमिका निभाएगा और आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी व वाहनों की संख्या के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराएगा।

कांवड़ यात्रा की तैयारी तेज एक्सप्रेसवे पर प्रवेश प्रतिबंधित

एजेंसी, नई दिल्ली

इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को एक्सप्रेसवे से जाने की अनुमति नहीं होगी। शासन स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाएगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मंडलायुक्तों, आईजी-डीआईजी, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गाजियाबाद समेत प्रदेश के सभी जिलों में एक सप्ताह के भीतर कांवड़ यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

घायल प्रदर्शनकारियों के समर्थन में केजरीवाल,कानूनी मदद का भरोसा

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली में सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएमएल अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान केजरीवाल ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उपचार और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी जरूरत में उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि घायल लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पार्टी उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी। सोमवार को आयोजित सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस और

केजरीवाल ने घायलों से मिलकर मदद का भरोसा दिया

प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। इस दौरान हुए लाठीचार्ज और अन्य घटनाओं में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। इसके बाद घायल लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आरएमएल अस्पताल में भर्ती कुछ घायलों से मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों से भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में घायल हुए किसी भी छात्र या प्रदर्शनकारी को यदि मेडिकल सहायता, कानूनी सलाह या अन्य किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो वह उनके द्वारा जारी किए गए संपर्क नंबर पर कॉल कर सकता है।

गुरुग्राम बॉर्डर पर दूसरे दिन भी सख्ती वाहनों की गहन जांच से ट्रैफिक प्रभावित

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। पुलिस ने सीमा पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की सघन जांच जारी रखी, जिससे सुबह और शाम के व्यस्त समय में ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी हो गई। दिल्ली में प्रवेश करने वाले लगभग सभी छोटे-बड़े वाहनों की जांच की गई। पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध वाहनों और यात्रियों से पूछताछ भी की, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है।

सोमवार सुबह से शुरू हुई यह जांच मंगलवार को भी जारी रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बॉर्डर पर लंबी वाहन

कतारें लगने से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच रोजाना सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर ट्रैफिक धीमा होने के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह एहतियात के तौर पर लागू की गई है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

लोधी रोड अग्निकांडः दमकल ने बुझाई आग, तीन शव बरामद

दिल्ली में आग का कहरः महिला समेत तीन की मौत, दमकल ने पाया आग पर काबू

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के लोधी रोड इलाके में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से एक महिला और उसकी दो बेटियों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और अन्य आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं। आग तेजी से फैलने के कारण इमारत में रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक तीन लोगों की जान जा चुकी थी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतकों में एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल हैं। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक उनकी आधिकारिक पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने तीनों के शवों को

लोधी रोड आग में मां-बेटियों समेत तीन की मौत

कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की पहचान करने और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है।

हादसे के बाद आसपास के इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जबकि पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र को घेर लिया। दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। काफी प्रयासों के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि आग आसपास की इमारतों तक न फैले। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और फायर विभाग की संयुक्त टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है तथा तकनीकी विशेषज्ञ भी जांच में जुटे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

इनामी बदमाश सोनू उर्फ प्रमोद गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद

एजेंसी ,नई दिल्ली

हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश सोनू उर्फ प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था और उसकी तलाश कई जिलों की पुलिस कर रही थी। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी हथियारों के साथ एक स्थान पर मौजूद है। सूचना के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अत्याधुनिक ग्लॉक पिस्टल, एक अवैध रिवॉल्वर तथा 226 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस मिलने से पुलिस भी सतर्क हो गई और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू उर्फ प्रमोद कुख्यात नीरज फरीदपुर गैंग का सक्रिय सदस्य है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी पर हरियाणा पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद हथियार और कारतूस किस उद्देश्य से रखे गए थे तथा इन्हें कहां से हासिल किया गया। एसटीएफ अब आरोपी से जुड़े अन्य गैंग सदस्यों, हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क और संभावित आपराधिक साजिशों की भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उससे गहन पूछताछ कर गैंग की गतिविधियों और अन्य मामलों में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा सके। गिरफ्तारी को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है।

राजौरी में स्कूल को उड़ाने की आतंकी साजिश नाकाम

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले के अड़गी क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों ने गांधी मेमोरियल अकादमी स्कूल को निशाना बनाने के उद्देश्य से स्कूल परिसर के पास इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) लगा रखी थी। स्थानीय लोगों की सतर्कता के कारण संदिग्ध वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस, सेना और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर पहुंच गईं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर लोगों की आवाजाही रोक दी गई और आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बम निरोधक दस्ते ने पूरी सावधानी और विशेषज्ञता के साथ सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे आईईडी को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ।

नशा तस्करों पर होगी सबसे सख्त कार्रवाई : मनोज सिन्हा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में ड्रग्स और नार्को-टेरर के खिलाफ अभियान अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 100 दिन के 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल शुरुआत है और नशे के कारोबार को पूरी तरह खत्म करने तक कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने ड्रग तस्करों को चेतावनी दी कि उनके खिलाफ कानून के तहत सबसे सख्त कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में उपराज्यपाल ने राजौरी, पुंछ और डोडा में हालिया फ्लैश फ्लड में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

जेएंडके के बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देगा केंद्र : मनोज सिन्हा

बोले- बाढ़ प्रभावितों की हर जरूरत का रखा जाएगा ध्यान, केंद्र सरकार पूरी तरह साथ

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई फ्लैश फ्लड से प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार ने हरसंभव सहायता का भरोसा दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित 100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के समापन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि राजौरी, पुंछ और डोडा जिलों में आई बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की जान गई है, जबकि बड़ी संख्या में घरों, दुकानों, सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक तथा निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। उपराज्यपाल ने मृतकों

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मीडिया को संबोधित करते हुए।

को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस कठिन समय में पूरा प्रशासन प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है।

मनोज सिन्हा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। राहत सामग्री पहुंचाने, बचाव अभियान को तेज करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि नागरिक प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और अन्य संबंधित एजेंसियों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है।

बचाव और पुनर्वास में नहीं होगी कोई कमी

उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तेजी से राहत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि प्रभावित परिवारों तक बिना किसी देरी के सहायता पहुंचाई जाए और पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से प्रभावित क्षेत्रों में जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जाएगी। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। साथ ही यह भरोसा दिलाया गया है कि बाढ़ पीड़ितों को इस कठिन समय में हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें किसी भी स्तर पर अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

मानसून से निपटने को तीन महीने का राशन एक साथ

मानसून अलर्ट के बीच जेएंडके सरकार का बड़ा फैसला, अब एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने आगामी मानसून के दौरान राशन वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा गैर-प्राथमिकता परिवार (एनपीएचएच) योजना के लाभार्थियों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का राशन एक साथ अग्रिम रूप से उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 अगस्त 2026 तक सभी पात्र लाभार्थियों को तीन महीने का खाद्यान्न वितरित कर दिया जाए, ताकि भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन या सड़क अवरुद्ध होने जैसी परिस्थितियों में लोगों को राशन की कमी का सामना न करना पड़े।

◆ **अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का खाद्यान्न 31 अगस्त तक वितरित करने का लक्ष्य**

इस व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को केवल एक बार ई-पॉस मशीन पर लेनदेन कर तीन महीने का पूरा राशन मिल जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से ई-पॉस मशीनों में विशेष सुविधा सक्रिय करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम, जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अग्रिम वितरण से खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारु बनी रहेगी।

न्यूज ब्रीफ

जम्मू-कश्मीर में फ्लैश फ्लड अलर्ट के बीच वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात गंभीर हो गए हैं। राजोरी समेत कई जिलों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ने पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, शिव खोड़ी और मचैल माता यात्राएं स्थगित कर दी गई हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा बिना जरूरी कारण घरों से बाहर न निकलने की अपील की है।

जम्मू-कश्मीर की भारी बारिश ने तबाह की सैकड़ों एकड़ फसल, उधमपुर में रो रहे किसान

भारतेंदु संवाददाता, उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के लांसी गांव में लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के कारण हुए भू-धंसाव से सोमवार को उधमपुर जिले में सात दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। भारी बारिश के कारण उधमपुर के ऊपरी किथेर-नारसू क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे भू-धंसाव की घटना हुई। इस घटना में एक रेस्तरां सहित सात दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त ढांचों से मलबा हटाया। अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लगभग चार एकड़ क्षेत्र में जमीन में दरारें पड़ गई हैं, जिससे आसपास मौजूद अन्य ढांचों पर भी खतरा मंडरा रहा है।

लद्दाख के मुद्दों को लेकर कारगिल में छात्र आंदोलन तेज

भारतेंदु संवाददाता, कारगिल। कारगिल में लद्दाख से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। छात्र संगठन सोनम वांगचुक के समर्थन में एक विरोध रैली आयोजित करने जा रहे हैं। इस रैली में दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और कारगिल विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। संगठन रैली के माध्यम से लद्दाख के विभिन्न मुद्दों को उठाएंगे और छात्रों तथा आम लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने की अपील की गई है। आयोजकों का कहना है कि यह प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों और चिंताओं को सामने रखने का माध्यम है।

सुरनकोट में तीसरे दिन भी बचाव अभियान जारी रहा

भारतेंदु संवाददाता, पुंछ। पुंछ जिले के सुरनकोट में बारिश से प्रभावित इलाकों में तीसरे दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी रहा। जिला पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमें मिलकर लगातार खोज अभियान चला रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थित तरीके से तलाशी ली जा रही है और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बचाव दल खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखी है और प्रभावित लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

गुरेज घाटी में चार जगह फटे बादल, खेत और सड़कें तबाह

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की गुरेज घाटी में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच चार स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। चोरवान और तुलैल क्षेत्रों में बादल फटने से कृषि भूमि, बीएसएनएल टावरों और सड़क संपर्क को नुकसान पहुंचा है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण दो सड़कें बंद हो गई थीं, जिनमें से एक को यातायात के लिए खोल दिया गया है, जबकि दूसरी सड़क को बहाल करने का कार्य जारी है। उपायुक्त बांदीपोरा इंदु कंवल चिब ने बताया कि बीआरओ, पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग और अन्य एजेंसियां राहत एवं बहाली कार्यों में जुटी हैं।

वैष्णो देवी यात्रा स्थगित होने पर श्राइन बोर्ड बना श्रद्धालुओं का सहारा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा खराब मौसम और भारी वर्षा की चेतावनी जारी किए जाने के बाद एहतियात के तौर पर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यात्रा रुकने के कारण कटड़ा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंस गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने व्यापक प्रबंध किए हैं। बोर्ड की ओर से कटड़ा स्थित निहारिका परिसर में निशुल्क लंगर सेवा लगातार संचालित की जा रही है, जहां श्रद्धालुओं को दिनभर भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

◆ **कटड़ा में फंसे श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड का सहारा**

◆ **श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड ने शुरू की मुफ्त भोजन सेवा**

श्राइन बोर्ड के अनुसार श्रद्धालुओं को सुबह चाय और नाश्ते के साथ-साथ दोपहर तथा रात्रि भोजन भी पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

भोजन में दाल-चावल, कढ़ी-चावल और अन्य पौष्टिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं, ताकि यात्रा बहाल होने तक किसी भी श्रद्धालु को भोजन की कमी या परेशानी का सामना न करना पड़े। लंगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजन ग्रहण कर रहे हैं और व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए बोर्ड के कर्मचारी तथा स्वयंसेवक लगातार सेवा में जुटे हुए हैं।

अखनूर सीमा पर पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, बहन से मिलने का किया दावा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के अखनूर क्षेत्र के परगवाल सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम करते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। घटना 20 और 21 जुलाई की दरमियानी रात की है, जब बीओपी मालाबेला के पास तैनात जवानों ने सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी। संतरी ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन संदिग्ध व्यक्ति भारतीय सीमा की ओर बढ़ता रहा। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने तत्काल घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान पाकिस्तान के पिंडी गांव निवासी 53 वर्षीय मोहम्मद रफीक उर्फ काला के रूप में बताई। उसने दावा किया कि वह अपनी विवाहित बहन से मिलने जा रहा था। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां उसके इस दावे की सत्यता और घुसपैठ की वास्तविक मंशा की गहन जांच कर रही हैं।

हाईटेक सुरक्षा का असर, एफआरएस ने पकड़ा यूएपीए का आरोपी

अनंतनाग में फेस रिकग्निशन सिस्टम के अलर्ट पर यूएपीए आरोपी गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, अनंतनाग। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के दौरान पुलिस को आधुनिक तकनीक की मदद से बड़ी सफलता मिली है। फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) की सहायता से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान वीरसरन निवासी दानिश अमीन रेशी के रूप में हुई है। यात्रा मार्ग पर तैनात फेस रिकग्निशन सिस्टम ने संदिग्ध की पहचान कर पुलिस को अलर्ट भेजा। इसके बाद जांच में पता चला कि उसके खिलाफ पहलगाम पुलिस थाने में यूएपीए के तहत पहले से मामला दर्ज है। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए अनंतनाग में बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र लागू किया गया है, जिसमें फेस रिकग्निशन सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक की मदद से इससे पहले भी 11 जुलाई को एक ओवर ग्राउंड वर्कर और 8 जुलाई को तीन अन्य संदिग्धों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस का कहना है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से तकनीकी निगरानी लगातार जारी रखी गई है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

मौसम अलर्ट के बीच जम्मू के सरकारी और निजी स्कूल बंद

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने 22 और 23 जुलाई को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों और अन्य स्कूल कर्मचारियों पर भी लागू रहेगा। मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक जम्मू संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही जलभराव, अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियां बनने का भी अलर्ट जारी किया गया है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को दो दिनों तक बंद रखा जाएगा।

◆ **भारी वर्षा की चेतावनी, जम्मू में दो दिन नहीं खुलेंगे स्कूल**

प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है और कुछ स्थानों पर सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है।

जिला प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की सलाह का पालन करने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। स्कूल प्रबंधन को भी आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सांबा में 10.65 ग्राम चिट्टे के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, सांबा। नशा मुक्त अभियान' के तहत ड्रग तस्करों विक्रेताओं के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए सांबा पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करके उसके पास से लगभग 10.65 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ (चिट्टा) बरामद किया है। सांबा पुलिस स्टेशन की एक टीम ने मानसर मोड़ पर नाका लगाया और एक पैदल चलने वाले व्यक्ति को रोका, जो संदिग्ध परिस्थितियों में इलाके में घूम रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 10.65 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ (चिट्टा) बरामद हुआ। ड्रग तस्कर की पहचान सुनील कुमार पिता बोध राज निवासी बाग-ए-बहू, जम्मू के रूप में हुई है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सांबा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/22 के तहत प्राथमिकी नंबर 215/2026 दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

◆ **मानसर मोड़ पर नाके के दौरान चिट्टे सहित तस्कर दबोचा**

12 साल पहले आई बाढ़ ने ताजा कर दी यादें

राजौरी में फिर दिखा प्रकृति का रौद्र रूप 2014 जैसी तबाही ने सहमा दिया पूरा शहर

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में 12 वर्ष पहले वर्ष 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ की दर्दनाक यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद आई फ्लैश फ्लड ने राजौरी शहर और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचा दी।

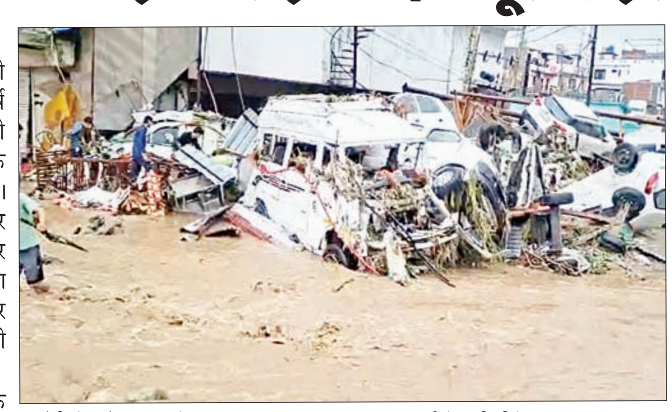

राजौरी में फ्लैश फ्लड के बाद जलमग्न सड़क पर बचाव कार्य में जुटी टीमें।

कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, सैकड़ों वाहन तेज बहाव में बह गए या मलबे में दब गए, जबकि घरों, दुकानों और बाजारों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई परिवारों को रातों-रात सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रशासन, सेना, पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

◆ **सैकड़ों वाहन बहे, हुआ भारी नुक्सान**

राजौरी के लोगों के लिए यह आपदा वर्ष 2014 की भयावह बाढ़ की यादें फिर से ताजा कर गई। उस समय लाम भाटा क्षेत्र में बारात लेकर जा रही एक बस उफनते नाले में समा गई थी, जिसमें लगभग 49 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे में लापता हुए कई लोगों के शव आज तक नहीं मिल सके हैं।

जेएंडके के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी एनसी

राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, दिल्ली प्रदर्शन सिर्फ शुरुआत : उमर अब्दुल्ला

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के संघर्ष को जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को दोबारा राज्य का दर्जा मिलना भविष्य में विशेष दर्जे की बहाली की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार बिना राज्य का दर्जा मिले जम्मू-कश्मीर की शक्तियों और अधिकारों को लेकर कोई ठोस व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। श्रीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार को उसके वादे की लगातार याद दिलाती रहेगी और उम्मीद है कि केंद्र अपना वादा पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन केवल अभियान की शुरुआत है, आगे पार्टी इस मुद्दे पर अपनी रणनीति और कार्यक्रम तय करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बनने के बाद विधानसभा के पहले सत्र में विशेष दर्जे से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, जो अभी भी प्रभावी है।

आपदा | भूस्खलन से पुंछ-जम्मू हाईवे बंद, बीआरओ ने शुरू किया राहत कार्य

शींदरा में भारी भूस्खलन, पुंछ-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग फिर बंद

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारी वर्षा के कारण पुंछ-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर शींदरा क्षेत्र में बड़ा भूस्खलन हो गया, जिससे सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और विशाल चट्टानें आ गिरीं। इसके चलते राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए। यात्रियों को घंटों तक सड़क पर इंतजार करना पड़ा। कई लोग जरूरी कार्यों के लिए यात्रा कर रहे थे, जबकि कुछ पर्यटक और स्थानीय निवासी भी जाम में फंसने से परेशान रहे। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

लगातार बारिश से उफान पर नदी, पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ा बाढ़ का खतरा।

घटना की सूचना मिलते ही सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की टीमें मौके पर पहुंच गईं और भारी मशीनों की सहायता से सड़क से मलबा हटाने का अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्य में बाधा बन रही है। मौसम अनुकूल होने के बाद ही राजमार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बनाकर यातायात के लिए खोला जा सकेगा। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर राहत एवं बहाली कार्य को तेज किया गया है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और यात्रा पर निकलने से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अधिकारियों का कहना है कि मानसून के दौरान पहाड़ी इलाकों में कभी भी भूस्खलन हो सकता है, इसलिए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।

जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कें बाधित हुई हैं और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इससे परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ आम लोगों का दैनिक जीवन भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। स्थानीय प्रशासन और बीआरओ की टीमें राजमार्ग को शीघ्र बहाल करने में जुटी हैं, जबकि लोगों से मौसम सामान्य होने तक धैर्य और सावधानी बरतने की अपील की गई है।

जम्मू में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, लोगों को घरों में रहने की सलाह

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में लगातार सक्रिय मानसून को देखते हुए मौसम विभाग ने 22 और 23 जुलाई के लिए जम्मू संभाग में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार इन दो दिनों के दौरान कई क्षेत्रों में तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम से संबंधित ताजा जानकारी पर लगातार नजर रखने की अपील की है। अधिकारियों ने बिना किसी जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए राजौरी जिला प्रशासन ने भी विशेष एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को खतरा हो सकता है। ऐसे सभी लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और नदी किनारों से तुरंत दूर रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने कहा है कि मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।

न्यूज ब्रीफ

महिला आरक्षण विधेयक लागू करने की मांग

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की मंडी जिला इकाई ने मंगलवार को सेरी चानणी में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को बिना किसी शर्त लागू करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से वर्तमान मानसून सत्र में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग उठाई। जिला अध्यक्ष डॉ. वीना वैद्य ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में संसद में पेश किया गया था। वर्ष 2023 में इसे पारित तो कर दिया गया, लेकिन जनगणना और परिसीमन की शर्त के कारण अब तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को राजनीतिक परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी संतोषजनक नहीं है। कार्यक्रम का संचालन अनीता ने किया, जबकि पूनम ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रदर्शन में गायत्री, गिरिजा, देवकी लता, कमला, भावना, विनय, रेहाना, रीता, संतोष, ललिता सहित कई महिलाओं ने भाग लिया।

31 को गेयटी थियेटर में जुटेंगे नामी साहित्यकार

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ 31 जुलाई को शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में संगोष्ठी एवं बहुभाषी कवि सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई नामी साहित्यकार अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे और बहुभाषी कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे। संगोष्ठी के दौरान हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र राजन के पांचवें उपन्यास 'कागज की नाव' का लोकार्पण भी किया जाएगा। राजेंद्र राजन ने बताया कि सुबह 10 से दोपहर डेढ़ बजे तक यह कार्यक्रम विभिन्न सत्रों में आयोजित किया जाएगा। 'कागज की नाव' पुस्तक के लोकार्पण व सह-चर्चा के बाद बहुभाषी कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार सतीश धर करेंगे। जबकि, आत्म रंजन मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि पत्र वाचन के सत्र की अध्यक्षता जयपुर के साहित्यकार प्रोफेसर सुधीर सोनी करेंगे। जबकि, देहरादून के प्रेम साहिल मुख्यातिथि और जयपुर के कैलाश चंद सोनी विशिष्टातिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस सत्र में डॉ. हेमराज कौशिक, डॉ. मीनाक्षी पॉल व डॉ. उषा बंदे जैसी प्रसिद्ध साहित्यकार अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। राजेंद्र राजन ने हिमाचल प्रदेश के साहित्यकारों एवं साहित्य प्रेमियों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है।

राम मंदिर चंदा मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों और राष्ट्रीय मुद्दों के खिलाफ बिलासपुर जिला मुख्यालय में जन आक्रोश यात्रा निकाली। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष बंबर ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण और राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए चंदे में पारदर्शिता न होने के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जन आक्रोश यात्रा कॉलेज चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए शहीद स्मारक तक पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाए। रैली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष बंबर ठाकुर ने कहा कि नीट पेपर लीक से लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को लेकर भी केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है। इससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। बंबर ठाकुर ने राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए चंदे में पारदर्शिता न होने का भी मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से हिसाब मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर है और जब तक सरकार जवाबदेह नहीं होगी, विरोध जारी रहेगा।

टैक्सी चालक से मारपीट, पुलिस अधिकारी भी घायल

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। थाना भोरंज के अंतर्गत मनोह स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर मंगलवार सुबह 4 बजे टैक्सी किराये को लेकर टैक्सी चालक और एक यात्री के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान दिनेश कुमार (48) पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव गुटकर, डाकघर गुटकर, तहसील बल्ह, जिला मंडी के रूप में हुई है। मारपीट के आरोपी की पहचान प्रदीप राणा, पुत्र जगदीश, निवासी गांव नुहाड़ा, डाकघर दिम्मी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस दल के साथ भी हाथापाई की, जिससे एक पुलिस अधिकारी को भी चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। भोरंज थाना प्रभारी प्रशांत सिंह ठाकुर ने बताया की आरोपी के खिलाफ थाना भोरंज में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 121(1) एवं 132 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।

अंगदान व नेत्रदान के महत्व की जानकारी दी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राज्य अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोटो) हिमाचल प्रदेश की ओर से एआईएमएसएस चमियाना में 'अंगदान जीवन संजीवनी अभियान' के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डायलिसिस यूनिट के नर्सिंग स्टाफ, तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों ने अंगदान की शपथ लेकर समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। इस दौरान डायलिसिस यूनिट में उपचाराधीन मरीजों के तीमारदारों को भी अंगदान और नेत्रदान के महत्व की जानकारी दी गई। सोटो हिमाचल की आईईसी/मीडिया कंसल्टेंट रामेश्वरी और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर नरेश कुमार ने अंगदान की प्रक्रिया, ब्रेन डेड की अवधारणा, कानूनी पहलुओं और इससे जुड़े भ्रमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ब्रेन डेड व्यक्ति के अंग कई गंभीर मरीजों को नया जीवन दे सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अंगदान से जुड़े मिथकों को दूर कर अपनी इच्छा परिवार के साथ साझा करें और अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ें। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने अंगदान की शपथ ली।

नूरपुर पुलिस ने 2 आदतन अपराधियों को निवारक हिरासत में लिया, भेजे जेल

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर ने नशा तस्करी के विरुद्ध अपने अभियान को और अधिक सशक्त करते हुए दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की है। नूरपुर पुलिस के प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के तहत जारी निवारक निरोध आदेशों के अनुपालन में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला कारागार धर्मशाला (कांगड़ा) में निरुद्ध किया गया है। आरोपियों में नामवीर सिंह पुत्र कंस राज, निवासी ग्राम तमोता, डाकघर उल्लेहरियां, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा शामिल है। उक्त आरोपी के खिलाफ पिछले के मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत इंदौरा थाना में 2 मामले दर्ज हैं। इसी तरह राजिंदर कुमार पुत्र बचन दास, निवासी ग्राम माजरा, डाकघर छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के खिलाफ भी इंदौरा और डमटाल पुलिस थाना में चिट्टे के 2 मामले दर्ज हैं। एसपी नूरपुर इल्मा अफरोज ने बताया कि इनकी निरंतर आपराधिक गतिविधियों व युवाओं पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को देखते हुए जन-सुरक्षा हेतु यह कार्रवाई की गई है।

मंडी। नगर निगम मेयर सुमन ठाकुर ने शहर के विकास की योजना बनाने हेतु प्रेस वार्ता कर शहरवासियों से मांगे सुझाव, उप मेयर जितेंद्र शर्मा भी रहे उपस्थित।

शाहपुर की बोह घाटी में बादल फटा, आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त, कई सड़कें प्रभावित

जाहलमा नाले में बाढ़ के बीच व्यापारी ने पुलिया से पार करवाई मटर की खेप

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच तबाही हुई है।

कांगड़ा जिले के उपमंडल शाहपुर की बोह घाटी में मंगलवार को बादल फटने से छह घर बह गए हैं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति की इसमें जान नहीं गई है। जानकारी के अनुसार बादल फटने से सपेड़ी और गरूं गांव में छह घर बह गए हैं। वहीं लम गांव को भी खतरा पैदा हो गया है। बादल फटने से कई सड़क मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया मौके पर पहुंचकर प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं, जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के जाहलमा नाले में बाढ़ आने से अस्थायी सड़क पूरी तरह से बह गई हैं। ऐसे में व्यापारी ने हिम्मत की मिसाल पेश की है और अपने मटर को पुलिया से मजदूरों के द्वारा पार निकाला। व्यापारी को आशंका थी कि नाले में अस्थायी सड़क की बहाली में देर होने से उसकी मटर की फसल को नुकसान हो सकता है। उन्होंने बिना देर किए मजदूरों की मदद से बीआरओ की ओर से नाले में लगाई गई पुलिया के रास्ते करीब एक पिकअप मटर की बोरियां नाले के उस पार शिफ्ट किया। व्यापारी ने मटर से बोरियों को नाले के पार पहुंचाकर यहां से दूसरी गाड़ी में भरकर मंडियों के लिए रवाना किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही व्यापारी को मटर की बोरियों की ढुलाई के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा हो, लेकिन वह कामयाब रहे और मटर की इस खेप को समय पर सब्जी मंडी तक पहुंचाएंगे।

आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

22 जुलाई को भी मौसम खराब बना रहेगा। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जबकि बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला में मध्यम से तेज बारिश का पूर्वानुमान है।

राजनीतिक प्रतिशोध में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का उत्पीड़न लोकतंत्र पर सीधा हमला : लखनपाल

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रशासन पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों, जिला परिषद सदस्यों तथा अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यह केवल जनप्रतिनिधियों का उत्पीड़न नहीं, बल्कि लोकतंत्र और जनता के जनादेश का भी खुला अपमान है। लखनपाल ने आरोप लगाया कि जनता द्वारा बार-बार नकारे गए कुछ राजनीतिक लोग मुख्यमंत्री के नाम का दुरुपयोग कर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। उनके प्रभाव में एक ही मामलों में बार-बार जमीनों की निशानदेही करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी हो, तब दोबारा-दोबारा कार्रवाई करवाने का उद्देश्य न्याय नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रताड़ना और छवि धूमिल करना है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि बरसात के मौसम में, जब सामान्यतः राजस्व विभाग इस प्रकार की कार्रवाई से बचता है, तब भी अधिकारियों को दलबल के साथ मौके पर भेजा जा रहा है। कई मामलों में संबंधित पक्षों को पूर्व सूचना तक नहीं दी जाती, जो प्राकृतिक न्याय और प्रशासनिक प्रक्रिया दोनों के विपरीत है। विधायक ने कहा कि एक ओर आम लोगों के इंतकाल, सीमांकन, प्रमाण-पत्र, राजस्व मामलों और विकास कार्यों की फाइलें लंबे समय तक लंबित रहती हैं, जबकि राजनीतिक दुर्भावना से जुड़े मामलों में असाधारण तेजी दिखाई जाती है। इससे प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। लखनपाल ने अधिकारियों से संविधान, कानून और सेवा नियमों के अनुरूप निष्पक्ष होकर कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि वे किसी राजनीतिक दबाव में एजेंट की भूमिका न निभाएं।

घुमारवीं में नीलगायों के आतंक से किसान परेशान, फसलें हो रहीं बर्बाद

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। उपमंडल घुमारवीं के दर्जनों गांवों में नीलगायों के बढ़ते आतंक से हजारों किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि जंगली जानवरों के कारण उनकी फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं, जिससे कई लोग खेती छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।

प्रभावित गांवों में मसौर, मसधाण, बेकल, मटयाल, रयांगली, कुठेड़ा, पुआणा, भटोली, पटेर, मोरसिंघी, बछड़ी, करनवाड़ी, दाड़ी, दावला, कसौहल, गाहर, लंजता, मुहाणा, वाह-पड़ोहड़ी, पध्याण, चंडवाणी, देहलवी, जरोड़ा, स्वारा, खसवीं और केट सहित कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। किसान बलबीर सिंह चंदेल, वीरेंद्र सिंह मैहता, अश्वनी कुमार, राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, चतर सिंह, अवतार सिंह, हंसराज, बलवंत सिंह, अच्छर सिंह, संजय कुमार, राजीव कुमार, प्रेम वशिष्ठ, जगदेव सिंह, ज्ञान सिंह, सुरेश कुमार, रोशन लाल और रमेश कुमार सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से नीलगायों के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

किसानों का कहना है कि पहले ही जंगली सूअरों के आतंक से खेती प्रभावित थी, अब नीलगायों की समस्या ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। खेतों में खड़ी फसलें कुछ ही समय में नष्ट हो जा रही हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग से मांग की है कि फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को सब्सिडी के साथ बाड़बंदी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। किसानों ने कहा कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो उपजाऊ खेत बंजर होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे और लोग खेती से पूरी तरह दूर हो जाएंगे।

बिलासपुर में बैडमिंटन टूर्नामेंट 26 जुलाई से

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बैडमिंटन संघ के जिला महासचिव विभोर शर्मा ने बताया कि जिले में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंडर-17, अंडर-19 के साथ सीनियर पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे।

उन्होंने बताया कि अंडर-17 वर्ग में 1 जनवरी 2010 के बाद जन्मे खिलाड़ी और अंडर-19 वर्ग में 1 जनवरी 2008 के बाद जन्मे खिलाड़ी हिस्सा लेने के पात्र होंगे। सभी प्रतिभागियों के लिए हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य होगा। एक खिलाड़ी अधिकतम तीन स्पर्धाओं में भाग ले सकेगा। पंजीकरण और प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 26 जुलाई को सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक लुहणू इंडोर स्टेडियम में होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे से मुकाबले शुरू होंगे।

विधायक इंद्र सिंह गांधी ने मुख्यमंत्री सुक्खू से की मुलाकात

बल्ह के विकास कार्यों को लेकर रखीं मांगें

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने शिमला स्थित मुख्यमंत्री आवास ओकओवर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने बल्ह विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित एवं विकासात्मक विषयों को प्रमुखता से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा तथा उनके शीघ्र समाधान का आग्रह किया।

इस वार्ता के दौरान विधायक गांधी ने सर्वप्रथम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या भंगरोटू तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला बनौण (शिक्षा खंड रिवालसर) को यथावत संचालित रखने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय क्षेत्र के विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं स्थानीय जनता की भावनाओं के अनुरूप है तथा इससे शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने मुख्यमंत्री को नगर निगम मंडी के वार्ड बैहना-14 को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर पुनः पंचायत क्षेत्र में शामिल करने अथवा उसे पंचायत का दर्जा प्रदान करने संबंधी ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता लंबे समय से इस मांग को उठा रही है और जनभावनाओं को देखते हुए इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने भंगरोटू खेल मैदान का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया। विधायक ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस मैदान में कोविड सेंटर एवं मेक-शिफ्ट अस्पताल स्थापित किया गया था। वर्तमान में इस मैदान को पुनः राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंगरोटू को खेल गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों, युवाओं एवं उभरती खेल प्रतिभाओं को समुचित खेल सुविधाएं मिल सकें और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिले। विधायक गांधी ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के अंतर्गत लंबे समय से लंबित एवं बंद पड़े विकास कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण एवं संपर्क सड़कों के निर्माण एवं सुधार, नालियों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास सहित क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक बजट एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान करने का अनुरोध किया। सुक्खू ने विधायक द्वारा उठाए गए सभी विषयों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने सभी मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

झंडूता में भाजपा का बूथ मजबूत अभियान शुरू

विधायक जीतराम कटवाल ने कार्यकर्ताओं को दिया एकता का मंत्र

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। भाजपा ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र में संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने के लिए पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता संवाद एवं समन्वय अभियान शुरू कर दिया है।

अभियान का शुभारंभ मंगलवार को झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने समोह, विजयपुर व हीरापुर पंचायतों के दौरे से किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर संगठन को मजबूत करने और आपसी तालमेल बढ़ाने का आह्वान किया। विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए टीम वर्क, आपसी सहयोग और एकता बेहद जरूरी है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि बूथ संगठन की सबसे छोटी इकाई जरूर है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है। बूथ मजबूत होगा तो संगठन भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की मुहिम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर संगठन हित में काम करने, समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाने और लोगों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का आह्वान किया। कटवाल ने कहा कि हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाले होंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से सक्रिय होकर फील्ड में उतरना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि झंडूता विधानसभा क्षेत्र में भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है और इसे पूरा करने में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होगी। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों को पहुंचाने का आह्वान किया।

कांग्रेस अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही : रणधीर शर्मा

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। श्री नयना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं व आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण विकास कार्यों पर असर पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि बिलासपुर जिले में एचआरटीसी के 34 बस रूट बंद हो चुके हैं व निगम के पास बसों के टायर बदलने तक के लिए बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सरकार परिवहन व्यवस्था को सुचारू रखने में असमर्थ है, उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि खाद की कमी के कारण किसान परेशान हैं और कई जगह उन्हें विरोध प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि बरसात शुरू होने के बावजूद पिछली आपदा में क्षतिग्रस्त हुई कई सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है। इसके अलावा नालियों का निर्माण कार्य भी लंबित है और कई प्रभावित परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिजली बिलों में बढ़ोतरी कर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। रणधीर शर्मा ने श्री नयना देवी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल घवांडल का भवन 75 प्रतिशत निर्माण के बाद भी अधूरा पड़ा है। वहीं केंद्र सरकार से स्वीकृत क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी दो वर्षों से शुरू नहीं हो पाया है।

आदतन तस्कर को निरोधात्मक हिरासत में भेजा

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नशा तस्करी के खिलाफ जिला बिलासपुर पुलिस के विशेष अभियान के तहत आदतन और बार-बार अपराध करने वाले तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने विपन कुमार पुत्र होशियार सिंह, निवासी गांव दरयाना, डाकघर औहर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थों से संबंधित कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद जारी आदेशों की अनुपालना में आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जबली स्थित खुली जेल में दाखिल किया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी मादक पदार्थों से जुड़े दो मामले दर्ज हैं, जिनमें नशीले पदार्थ बरामद हुए थे। पुलिस ने बताया कि नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

राहत उपमुख्यमंत्री की पहल रंग लाई, हजारों टैक्सी संचालकों को मिलेगा फायदा

15 साल तक जारी रहेगा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश के ऑल इंडिया टैक्सी ऑपरेटरों की लंबे समय से चली आ रही एक महत्वपूर्ण मांग पूरी हो गई है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों के लिए अधिकतम परिचालन अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किए जाने के प्रावधान को लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं।

इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) भी अधिसूचित कर दी गई है, जिससे पात्र वाहनों को संशोधित नियमों का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के पर्यटन एवं परिवहन क्षेत्र से जुड़े हजारों टैक्सी संचालकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से वाहन संचालक इस मांग को उठा रहे थे, अब संशोधित व्यवस्था लागू होने से पात्र वाहनों का संचालन 15 वर्ष तक किया जा सकेगा, जिससे टैक्सी ऑपरेटरों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनके रोजगार को मजबूती मिलेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ऑल इंडिया टैक्सी ऑपरेटरों की इस मांग को उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार को अवगत कराया था कि हिमाचल जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में हजारों परिवार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में वाहनों की परिचालन अवधि बढ़ाना समय की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नियमों में संशोधन किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी तत्परता दिखाते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।

पर्यटन और परिवहन क्षेत्र को मिलेगा संबल

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से न केवल टैक्सी ऑपरेटरों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश के पर्यटन उद्योग को भी नई गति मिलेगी। पर्यटन सीजन के दौरान बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी और हजारों परिवारों की आजीविका सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उनकी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।

नियमों के अनुसार मिलेगा लाभ

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि संशोधित व्यवस्था के तहत ऐसे पात्र एआईटीपी वाहन, जिनकी पंजीकरण तिथि 15 वर्ष से कम है, निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, सभी करों एवं सरकारी देयताओं का भुगतान तथा अन्य वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

200 पदों के लिए कैंपस साक्षात्कार 30 जुलाई को

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। महेंद्रा एंड महेंद्रा स्वराज मोहाली की ओर से विभिन्न श्रेणियों के 200 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर राजेश मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए 30 जुलाई को उपरोजगार कार्यालय घुमारवीं और 31 जुलाई को जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में कैंपस साक्षात्कार होंगे। उन्होंने बताया कि मशीन ऑपरेटर, फिटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मोटर मैकेनिक, पेंटर और टर्नर पदों के लिए पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा पास होना चाहिए। वर्ष 2023 से 2026 तक उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की आयु 18 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 17 हजार रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार सभी मूल दस्तावेज, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, बायोडाटा और पासपोर्ट आकार के फोटो सहित निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुंच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

वन महोत्सव : शिमला के मलाही वन क्षेत्र में लगाए गए 175 पौधे

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के सहयोग से सर्वांगीण कृषि समाधान फाउंडेशन ने 'वन महोत्सव-2026' के तहत जिला शिमला के मशोबरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पुजारली (बिओलिया) स्थित मलाही वन क्षेत्र में वृहद पौधरोपण अभियान आयोजित किया।

वन मित्र नितिका की उपस्थिति में आयोजित इस अभियान के दौरान विभिन्न प्रजातियों के 175 पौधे लगाए गए। अभियान में सर्वांगीण कृषि समाधान फाउंडेशन के स्वयंसेवकों के अलावा हिमगिरि कल्याण आश्रम के विद्यार्थियों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों तथा वेस्ट वॉरियर्स सोसायटी के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोजक के रूप में सहयोग दिया। बैंक के मुख्य प्रबंधक घनश्याम ठाकुर ने परिवार सहित पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पौधरोपण के साथ वेस्ट वॉरियर्स सोसायटी के स्वयंसेवकों ने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान भी चलाया। उन्होंने प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट एकत्र कर उनके वैज्ञानिक निस्तारण के लिए संस्था के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तक पहुंचाया। फाउंडेशन के निदेशक डीएन चौहान ने कहा कि जंगली जानवरों द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान से किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने किसानों से आसपास के जंगलों में स्थानीय फलदार और चारा प्रजातियों के पौधे लगाने का आह्वान किया, ताकि वन्यजीवों को जंगल में ही भोजन उपलब्ध हो सके और उनका रुख खेतों की ओर कम हो। उन्होंने पौधरोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल पर भी जोर दिया। हिमगिरि कल्याण आश्रम के अध्यक्ष धरम पाल व सचिव अनुपम शर्मा ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी और व्यावहारिक सीख विकसित करते हैं। यह अभियान सरकारी विभागों, बैंकिंग संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों के सामूहिक प्रयास का प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा।

एमा राडुकान की खूबसूरत अदा

ब्रिटेन। एमा राडुकानू ब्रिटेन की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने वर्ष 2021 में यूएस ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रचा और सबसे कम उम्र की ग्रैंड स्लैम विजेताओं में शामिल हुईं।

स्पोर्ट्स विंडो

टी20 सीरीज में भारत और जिम्बाब्वे के पास समान मौके : सिकंदर रजा

एजेंसी, हरारे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने तीन मैच की टी20 सीरीजमें भारत को प्रबल दावेदार मानने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी और उनके पास समान रूप से जीत हासिल करने के मौके होंगे। विश्व चैंपियन भारत का टी20 अंतरराष्ट्रीय में हाल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उसे आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की सीरीज में उसे चार मैच में हार मिली जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। अब उसके पास जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत की राह पर लौटने का मौका होगा। इस सीरीज का पहला मैच वीरवार को खेला जाएगा। रजा ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ''इस सीरीज में दोनों देशों के पास समान मौके होंगे। हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हमारी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सीरीज बेहद रोमांचक होगी।'' जिम्बाब्वे ने फरवरी में कोलंबो में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया था। उसने इस साल श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत दर्ज की हैं। रजा ने कहा, ''जहां तक जीत हार का सवाल है तो दोनों टीमों के पास यह श्रृंखला जीतने के बराबर के मौके होंगे। भारत अभी बदलाव के दौर से गुजर रहा है जिससे यह श्रृंखला और अधिक रोमांचक हो गई है। मुझे नहीं लगता कि यह श्रृंखला एकतरफा होगी।'' दूसरा और तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 25 और 26 जुलाई खेले जाएंगे।

विश्व जूनियर स्क्वाश में भारतीय खिलाड़ियों की अच्छी शुरुआत

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अनाहत सिंह ने न्यूजीलैंड की क्वालीफायर लिली विल्सन को आसानी से 11-2, 11-1, 11-3 से हराकर कनाडा के ओंटारियो में चल रही विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप के महिला एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया। आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह की भारतीय तिकड़ी ने सोमवार को प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष एकल के तीसरे दौर में प्रवेश किया। पुरव रामभिया ने रोनी हिकलिंग के सामने कड़ी चुनौती पेश की लेकिन पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी को आखिर में हार का सामना करना पड़ा। महिला वर्ग के पहले दौर में अनिका दुबे ने जापान की अन्ना कुवाहारा को सीधे गेम में हराया और सान्वी ने पांच गेम के मुकाबले में नीदरलैंड की एल्के मोल्स को पराजित किया।

फीफा ने शुरू की स्पेन-अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के बीच हुई झड़प की जांच

एजेंसी, नई दिल्ली। फीफा ने विश्व कप-2026 फाइनल के बाद स्पेन और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों व कोचिंग स्टाफ के बीच हुई झड़प की अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी है। न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में फेरान टोरेस के 106वें मिनट में किए गए गोल की बदौलत अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा पुरुष विश्व कप खिताब जीता। मैच के अंतिम पलों में अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजो फर्नांडीज को स्पेन के पाउ कुबार्सी पर खतरनाक फाउल के लिए दूसरा पीला कार्ड मिलने के बाद लाल कार्ड दिखाया गया। मुकाबला खत्म होते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। वीडियो में अर्जेंटीना के लिएंड्रो परेडेस, नाहुएल मोलिना और निकोलस ओटामेंडी की स्पेन के एरिक गार्सिया और रोद्री से तीखी बहस और धक्का-मुक्की देखी गई। अर्जेंटीना के सहायक कोच रोबर्टो आयाला पर भी स्पेन के दानी ओल्मो के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। स्थिति को शांत कराने के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी और अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी बीच-बचाव के लिए मैदान में उतरे। फीफा ने मामले की जांच के लिए अनुशासन एवं नैतिकता अभियोजक नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

एशियाई खेलों से पहले भारतीय निशानेबाजों की होगी बड़ी परीक्षा

एजेंसी, हांगझोऊ। बुधवार से शुरू होने वाला आईएसएसएफ विश्व कप भारतीय निशानेबाजों के लिए एशियाई खेलों से पहले अपनी तैयारियों को परखने का अहम मंच होगा। इस प्रतियोगिता में भारत को दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने और चीन के खिलाफ अपनी ताकत का आकलन करने का मौका मिलेगा। हाल के विश्व कप में चीन का प्रदर्शन शानदार रहा है, जबकि भारत ने भी म्यूनिख चरण में बेहतर खेल दिखाया। युवा निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और उनसे एक बार फिर पदक की उम्मीद है। ईशा सिंह 25 मीटर पिस्टल में अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगी। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल में उतरेंगी। वहीं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और अनीश भानवाला पुरुष वर्ग में भारत की चुनौती संभालेंगे।

फीफा विश्व कप रैंकिंग : अर्जेंटीना दूसरे, फ्रांस तीसरे स्थान पर बरकरार

विश्व चैंपियन स्पेन बना दुनिया में नंबर-वन

एजेंसी, नई दिल्ली

फीफा विश्व कप-2026 का खिताब जीतने के साथ ही स्पेन ने फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भी नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया है। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर छह महीने बाद फिर से शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया और मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को दूसरे स्थान पर धकेल दिया।

विश्व कप फाइनल में फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागकर स्पेन को उसका दूसरा पुरुष विश्व कप खिताब दिलाया। इस उपलब्धि के साथ स्पेन अब पुरुष और महिला दोनों फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। स्पेन की महिला टीम भी मौजूदा विश्व चैंपियन है।

लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना एक स्थान नीचे खिसककर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। विश्व कप में चौथे स्थान पर रहने के बावजूद फ्रांस तीसरे स्थान पर कायम है, जबकि इंग्लैंड चौथे स्थान पर बना हुआ है। यूईएफए नेशंस लीग चैंपियन पुर्तगाल, जिसे विश्व कप के प्री-क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बाहर किया था, दो स्थान फिसलकर सातवें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं, इसी दौर में बाहर होने वाला ब्राजील एक स्थान की छलांग लगाकर छह महीने बाद फिर से शीर्ष-5 में लौट आया है और अब पांचवें स्थान पर है।

चार बार का विश्व चैंपियन जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ-32 में पैराग्वे से पेनाल्टी शूटआउट में हारकर बाहर हो गया था। इसका असर रैंकिंग पर भी पड़ा और जर्मनी दो स्थान नीचे खिसककर 12वें स्थान पर पहुंच गया। यह सितंबर 2025 के बाद उसकी सबसे खराब रैंकिंग है।

विश्व कप के सह-मेजबान देशों में मेक्सिको ने सबसे बड़ी प्रगति की। मेक्सिको चार स्थान ऊपर चढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गया। टीम प्री-क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, जहां उसे अपने घरेलू मैदान एज्टेका स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा।

फीफा के अनुसार, जून रैंकिंग चक्र के दौरान कुल 105 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए, जिनमें से 104 मुकाबले फीफा विश्व कप 2026 के थे। यह टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित हुआ।

टॉप-10 टीमें

रैंकिंग	देश
1.	स्पेन
2.	अर्जेंटीना
3.	फ्रांस
4.	इंग्लैंड
5.	ब्राजील
6.	मोरक्को
7.	पुर्तगाल
8.	बेल्जियम
9.	नीदरलैंड्स
10.	मेक्सिको

विश्व कप फाइनल की हार के बाद भावुक हुए मेसी, बोले-यह दर्द बहुत गहरा है

एजेंसी, नई दिल्ली

फीफा विश्व कप-2026 के फाइनल में स्पेन से अतिरिक्त समय में 0-1 की हार के एक दिन बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने भावुक संदेश जारी करते हुए प्रशंसकों का आभार जताया। मेसी ने कहा कि इस हार का दर्द बहुत गहरा है और इस घाव को भरने में समय लगेगा, लेकिन टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जो संघर्ष किया, उस पर उन्हें गर्व है।

न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप खिताब अपने नाम किया। मैच के बाद मेसी भावुक होकर रोते हुए नजर आए और उनके अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हो गईं। इंस्टाग्राम पर स्पेनिश भाषा में लिखे अपने संदेश में मेसी ने कहा, 'यह दर्द बहुत गहरा है और इस घाव को भरने में समय लगेगा। लेकिन मैं उन सभी अच्छे पलों को भी संजोकर रखूंगा... वे मुकाबले जिन्हें हमने वापसी करते हुए जीता, जिनमें हमने अपना सब कुछ झोंक दिया। वे पल हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। पूरे देश का समर्थन, और इस टीम की मेहनत व समर्पण ने हमें एक बार फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल किया।' उन्होंने आगे कहा, 'आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने हमें शुभकामनाएं दीं और संदेश भेजे। एक बार फिर हम पूरे देश को एकजुट करने में सफल रहे और अर्जेंटीना होने के गर्व को साथ मिलकर महसूस किया।'

मेसी ने अपने संदेश में स्पेन को भी बधाई देते हुए कहा, 'मैं स्पेन को भी इस चैंपियनशिप के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।' इंटर मियामी के स्टार खिलाड़ी मेसी ने 2022 विश्व कप फाइनल में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाया था। इसके अलावा उन्होंने 2021 और 2024 में लगातार दो कोपा अमेरिका खिताब भी टीम को जिताए। इस विश्व कप के दौरान मेसी ने अपने अंतरराष्ट्रीय गोलों की संख्या 125 तक पहुंचा दी, जो केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो (146 गोल) से कम है।

बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम घोषित

एजेंसी, मेलबर्न

कमिंस-हेजलवुड और लियोन की वापसी

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 13 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। कप्तान पैट कमिंस, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन चोट से उबरकर टीम में लौट आए हैं, जिससे टीम को बड़ी मजबूती मिली है।

कमिंस निचली पीठ की स्ट्रेस इंजरी, हेजलवुड हैमस्ट्रिंग और अकिलिस की चोट, जबकि लियोन हैमस्ट्रिंग सर्जरी के बाद लंबे समय से बाहर थे। तीनों खिलाड़ियों की वापसी पर मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्होंने मेडिकल और स्पोर्ट्स साइंस टीम के साथ कड़ी मेहनत कर फिटनेस हासिल की है। वरिष्ठ खिलाड़ियों की वापसी के कारण एशेज में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले माइकल नेसर और ब्रेंडन डॉगेट को टीम में जगह नहीं मिली। हालांकि दोनों, ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी के साथ, मुख्य टीम के साथ अभ्यास करेंगे और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रहेंगे। बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एशेज में पदार्पण करने वाले जेक वेदराल्ड को एक और मौका मिला है और वह ट्रैविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। वहीं खराब फॉर्म के बावजूद मार्नस लाबुशेन पर चयनकर्ताओं ने भरोसा कायम रखा है।

तेज गेंदबाजी आक्रमण में कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड शामिल हैं। ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन और ब्यू वेबस्टर भी अंतिम एकादश के दावेदार हैं। दोनों टेस्ट 13-17 अगस्त (डार्विन) और 22-26 अगस्त (मैकाय) में खेले जाएंगे।

राष्ट्रमंडल खेलों का 23 जुलाई से होगा आगाज

एजेंसी, नई दिल्ली। स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 74 देशों और क्षेत्रों के 3,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 11 दिनों तक चलने वाले इन खेलों में 11 खेलों की 215 पदक स्पर्धाओं में मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में ओलंपिक और विश्व चैंपियन खिलाड़ियों के साथ कई उभरते सितारे भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। खेलों की शुरुआत 23 जुलाई को बाउल्स और पैरा बाउल्स से होगी, जबकि समापन 2 अगस्त को ट्रैक साइक्लिंग, जूडो और नेटबॉल के पदक मुकाबलों के साथ होगा। एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, 3×3 बास्केटबॉल और पैरा स्पर्धाएं आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत बने कप्तान

एजेंसी, नई दिल्ली

हॉकी इंडिया ने एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप बेल्जियम एवं नीदरलैंड्स 2026 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। अनुभवी डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिक विशेषज्ञ हरमनप्रीत सिंह टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह टीम में अनुभव की अहम भूमिका निभाएंगे। विश्व कप का आयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होगा। भारत को पूल-डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने सभी लीग मुकाबले नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेलेगी।

मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टीम चयन पर संतोष जताते हुए कहा, 'यह एक संतुलित टीम है। इसमें बड़े टूर्नामेंट का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों के साथ शानदार फॉर्म में चल रहे युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है। इन युवाओं ने अपनी प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई है।'भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से मुकाबला होगा। भारत-पाकिस्तान मैच पूल चरण का सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला माना जा रहा है।

फुल्टन ने कहा, 'प्रेस, काउंटर और प्रदर्शन' केवल हमारी रणनीति नहीं है, बल्कि यही इस टीम की सोच और प्रशिक्षण का आधार भी है। हम फिलहाल बहुत आगे नहीं सोच रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक समय में एक मैच पर पूरा ध्यान देना है और हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है।'

अफगानिस्तान में बाढ़ से 20 लोगों की मौत

एजेंसी, काबुल (अफगानिस्तान)। अफगानिस्तान में तेज बारिश से जानमाल की क्षति हुी है। भारी बारिश की वजह से पूर्वी अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में सोमवार को अचानक आई बाढ़ से हाहाकार मच गया। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान 20 लोगों की मौत हो गई। कम से कम 80 लोग घायल हो गए। लगभग 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

◆ **80 से ज्यादा घायल, 100 लापता**

अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी पझवोक की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि की है। उसने मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। अथॉरिटी का कहना है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नूरिस्तान प्रांत की राजधानी पारुन में हाल ही में आई बाढ़ से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। अथॉरिटी ने बयान में कहा कि यह आंकड़े शुरुआती हैं और प्रभावित इलाके में बचाव दल अभी भी काम कर रहे हैं। अथॉरिटी ने यह भी कहा कि सर्वे और आकलन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मीडिया के साथ पुख्ता जानकारी साझा की जाएगी। मृतकों और घायलों की संख्या में बदलाव हो सकता है। बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है।

डोनाल्ड ट्रंप बोले-अमेरिका में नहीं होगी नेतन्याहू की गिरफ्तारी

एजेंसी, वॉशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान नेतन्याहू की संभावित गिरफ्तारी के कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही थी।

◆ **न्यूयॉर्क मेयर की टिप्पणी पर जताई नाराजगी**

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि नेतन्याहू को अमेरिका में 'किसी भी तरह, किसी भी रूप में' गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ संघर्ष में अमेरिका के सहयोगी हैं और वॉशिंगटन उनका समर्थन करता है। ट्रंप ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने हजारों निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या की है और पिछले कई दशकों में अमेरिकी सैनिकों समेत कई लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में नेतन्याहू के खिलाफ किसी कार्रवाई की कोई संभावना नहीं है। वहीं, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि उनका प्रशासन नेतन्याहू की संभावित गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) द्वारा लगाए गए आरोपों के चलते नेतन्याहू को हेग में जवाब देना चाहिए।

हालांकि, ममदानी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका प्रशासन कानून की सीमाओं के भीतर ही कोई कदम उठाएगा। ट्रंप और ममदानी के अलग-अलग रुख ने नेतन्याहू की संभावित अमेरिका यात्रा को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज कर दी है।

मीनाक्षी नटराजन ने हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के फैसले को दी चुनौती

एजेंसी, भोपाल/जबलपुर

मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार रहीं वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। नटराजन ने तय 45 दिनों की वैधानिक सीमा के भीतर याचिका दायर कर निर्वाचन आयोग के फैसले को गलत ठहराया है।

◆ **जंतर-मंतर पर छात्राओं पर लाठीचार्ज की निंदा की**

मीनाक्षी नटराजन मंगलवार को जबलपुर पहुंचीं और उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दाखिल की। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने नियमानुसार निर्धारित 45 दिनों की समय-सीमा के भीतर यह याचिका दायर की है। नटराजन का आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनका नामांकन पत्र बिना किसी ठोस और वैध कानूनी आधार के निरस्त किया गया था। जिस मामले का संज्ञान तक नहीं लिया गया था, उसे ही आधार बनाकर उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले चुनावों में 'वोटों की चोरी' के आरोप लगते थे, लेकिन इस बार तो पूरी की पूरी 'सीट ही चुरा' ली गई है। नटराजन ने भरोसा जताया कि उन्हें उच्च न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। कानूनी लड़ाई के साथ-साथ मीनाक्षी नटराजन ने राजनीतिक मोर्चे पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को घटित घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला दिन था, जब अपने जायज अधिकारों की मांग कर छात्र-छात्राओं पर बर्बरतापूर्वक पुलिस से लाठीचार्ज कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार हर शांतिपूर्ण जन-आंदोलन को पुलिस बल के दम पर कुचलने का प्रयास कर रही है।

चांदी 3159 रुपए महंगी, सोना 1150 बढ़कर 1.43 लाख पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली। सोने-चांदी की कीमतों में मंगलवार काफी उछाल आया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, एक किलो चांदी 3,159 रुपए बढ़कर 2.23 लाख रुपए पर पहुंच गई है। वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,150 रुपए चढ़कर 1.43 लाख रुपए आ गया है। इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 10 हजार रुपए महंगा हुआ है। (अनंत ज्ञान)

सेंसेक्स 77470 पर बंद और निफ्टी 24188 पर आया

एजेंसी, मुंबई। सेंसेक्स मंगलवार को 238 अंक नीचे 77,470 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 51 अंक की गिरावट रही, ये 24,188 के स्तर पर आ गया। सरकारी बैंक और आईटी शेयर्स में आज ज्यादा बिकवाली दिखी। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का शेयर 574 रुपए के आईपीओ प्राइस से 6.85 प्रतिशत तेजी के साथ लिस्ट हुआ। एनएसई पर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का शेयर 613.30 रुपए पर खुला। वहीं, बीएसई पर यह 610 रुपए यानी 6.27 प्रतिशत ऊपर लिस्ट हुआ।

किसानों का दिल्ली कूच स्थगित, सरकार से वार्ता के आश्वासन पर लौटे आंदोलनकारी

शंभू बॉर्डर पर बैठक के बाद फैसला, हिरासत में लिए किसान नेताओं की रिहाई पर बनी सहमति

एजेंसी, गुरुग्राम

अमेरिका-भारत फ्री ट्रेड डील के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मंगलवार को प्रस्तावित दिल्ली कूच और किसान घाट महापंचायत फिलहाल स्थगित कर दी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ हुई बैठक के बाद किसान वापस लौट गए।

किसान नेताओं के मुताबिक, हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई और केंद्र सरकार से बातचीत शुरू कराने के आश्वासन के बाद यह फैसला लिया गया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी रिहा कर दिया। हालांकि, संसद घेराव के मद्देनजर हरियाणा के पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जुड़े बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी हुई है। कई जगह किसान नेताओं और समर्थकों को हिरासत में लिया गया। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर 27 जुलाई तक धारा 163 लागू कर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। वहीं, कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर जांच के कारण लंबा जाम लगा। किसान नेता सरवण पंधेर ने बताया कि कृषि मंत्री राणा ने जल्द ही हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अगले 8-10 दिनों में बातचीत शुरू कराने का आश्वासन दिया है।

उच्चाधिकार समिति ने अरावली संरक्षण पर जनता से मांगे सुझाव

एजेंसी, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े मामलों पर जनता, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव एवं अभ्यावेदन आमंत्रित किए हैं। समिति को 31 अगस्त 2026 तक अपनी व्यापक रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंपनी है। उच्चतम न्यायालय ने 25 मई 2026 को स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 10/2025 में पारित आदेश के तहत इस उच्चाधिकार समिति का गठन किया था। समिति को अरावली क्षेत्र से जुड़े पर्यावरण, जैव विविधता, खनन, आजीविका और अन्य संबंधित मुद्दों की विस्तृत जांच का दायित्व सौंपा गया है।

समिति ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात सहित अन्य राज्यों के हितधारकों, पर्यावरणविदों, संरक्षणवादियों, गैर-लाभकारी संगठनों, खनन पट्टा धारकों, परियोजना प्रस्तावकों, ग्रामीणों, किसानों, खदान श्रमिकों, स्थानीय समुदायों तथा विषय में वैध हित रखने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त होने वाले सुझावों के साथ, जहां संभव हो, दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य सत्यापन योग्य सामग्री भी संलग्न की जाए। सभी अभ्यावेदन सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर ईमेल और निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।